

फेम इंडिया

सोच बदलें, समाज बदलेगा

सर्वश्रेष्ठ पुलिस

कप्तान 2026

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट सर्वे



व्यक्तित्व - राजीव मिश्रा



राहत टैक्स से फ्रीडम इंटरेस्ट से

नागरिकों के लिए सुनहरा मौका



अवधि
15 अगस्त से
15 दिसंबर,
2026 तक

नगर निकायों में लंबित संपत्ति कर (गृहकर/जलकर/सीवर-कर) हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.)

पूरा बकाया भुगतान करने पर ब्याज एवं सरचार्ज में मिलेगी
100% छूट

ऑनलाइन तथा ऑफलाइन
दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा

बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए
अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा

बकाया राशि का 1/3 हिस्सा 30 दिनों में और शेष 2/3 हिस्सा
दो मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा

1 अप्रैल, 2026 तक लंबित सभी प्रकार की
संपत्तियों के कर पर मिलेगा OTS का लाभ

OTS अपनाएं
ब्याज में
पूरी राहत पाएं

अपने नगर निकाय के कार्यालय आएँ,
समय रहते OTS का लाभ उठाएँ,
कर के बोझ से मुक्ति पाएँ.

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

टोल फ्री नं. : 1533



फेम इंडिया

www.thefameindia.com

वर्ष 14, अंक 9, सितंबर 2026

एडिटर इन चीफ - धीरज कुमार
मैनेजिंग एडिटर - अनिल सिंह

असिस्टेंट एडिटर - मनीष सिंह

एडिटोरियल टीम -
दिलीप सिंह, श्वेता जया, राकेश चौधरी, नीलम शुक्ला, सुनील
सिंह, नम्रता नारायण, कल्पना पुंडीर, विजय पांडेय, अमरनाथ,
हेमंत सिंह, रोहित रोहण, विकास सिंह, नीरज सहाय, सुधा पांडेय,
संतोष कुमार सिंह, संजय बाली

संपादकीय सलाहकार - अतुल सिंघल

कोऑर्डिनेटर - देवेश मिश्रा

आर्ट डायरेक्टर - स्वर्ण लता

वेब टीम - मानवेंद्र प्रताप, रश्मि सिंह

सेल्स - अनामिका गौतम
मार्केटिंग - सुनील पुंडीर
सर्कुलेशन - प्रवीण मिश्रा

कानूनी सलाहकार
अमित खेमका

(स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक राजश्री द्वारा ज्योति प्रिंटर्स,
ई-94, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर से मुद्रित एवं
ए-533, जीडी कालोनी, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली से
प्रकाशित, संपादक - धीरज कुमार)

संपादकीय एवं मार्केटिंग ऑफिस
फेम इंडिया पब्लिकेशन प्रा. लि।
एफ 6, सेक्टर-50, नोएडा 201304 (उ.प्र.)
फोन नं. - +91- 9717727501 / 9451587800 / 0120 315 4572
ईमेल : fameindia.publication@gmail.com

RNI No. DELHIN/2012/48773

सर्वश्रेष्ठ पुलिस कप्तान
विशेषांक 2026



3

क्यों जरूरी है पुलिस की सराहना?

पुलिस की आलोचना कोई नई बात नहीं है। पुलिस कानून के शासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है, इसलिए उससे जवाबदेही और संवेदनशीलता की अपेक्षा होना बिल्कुल उचित है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस के हर प्रयास और हर अच्छे काम को केवल इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाए क्योंकि कहीं कोई चूक हुई है?

हकीकत यह है कि देश का आम नागरिक जब किसी मुश्किल में फंसाता है, खतरा महसूस करता है या उसके साथ कोई अपराध होता है, तो सबसे पहले जिस व्यवस्था की ओर उम्मीद से देखता है, वह पुलिस ही है। सड़क दुर्घटना हो, चोरी हो, कोई व्यक्ति लापता हो, महिलाओं या बच्चों की सुरक्षा का सवाल हो, कोई आपराधिक गिरोह परेशान कर रहा हो या अचानक कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए—हर परिस्थिति में पुलिस को सबसे पहले मोर्चे पर खड़ा होना पड़ता है।

पुलिसकर्मियों की नौकरी सामान्य नौ से पांच की नौकरी नहीं है। त्योहार हो या चुनाव, दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, पुलिसकर्मियों की इयूटी जारी रहती है। कई बार उसे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों को पीछे छोड़कर समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ती है।

विडंबना यह है कि पुलिस की हजार अच्छी कार्रवाइयां अक्सर खबर नहीं बनती, लेकिन एक गलती सुर्खियों में आ जाती है। किसी गंभीर अपराधी की गिरफ्तारी, किसी लापता बच्चे की सुरक्षित बरामदगी, किसी बड़े अपराध का खुलासा, समय रहते किसी हिंसक घटना को रोक देना या संकट में फंसे नागरिक की मदद करना—ये पुलिस के ऐसे कार्य हैं,

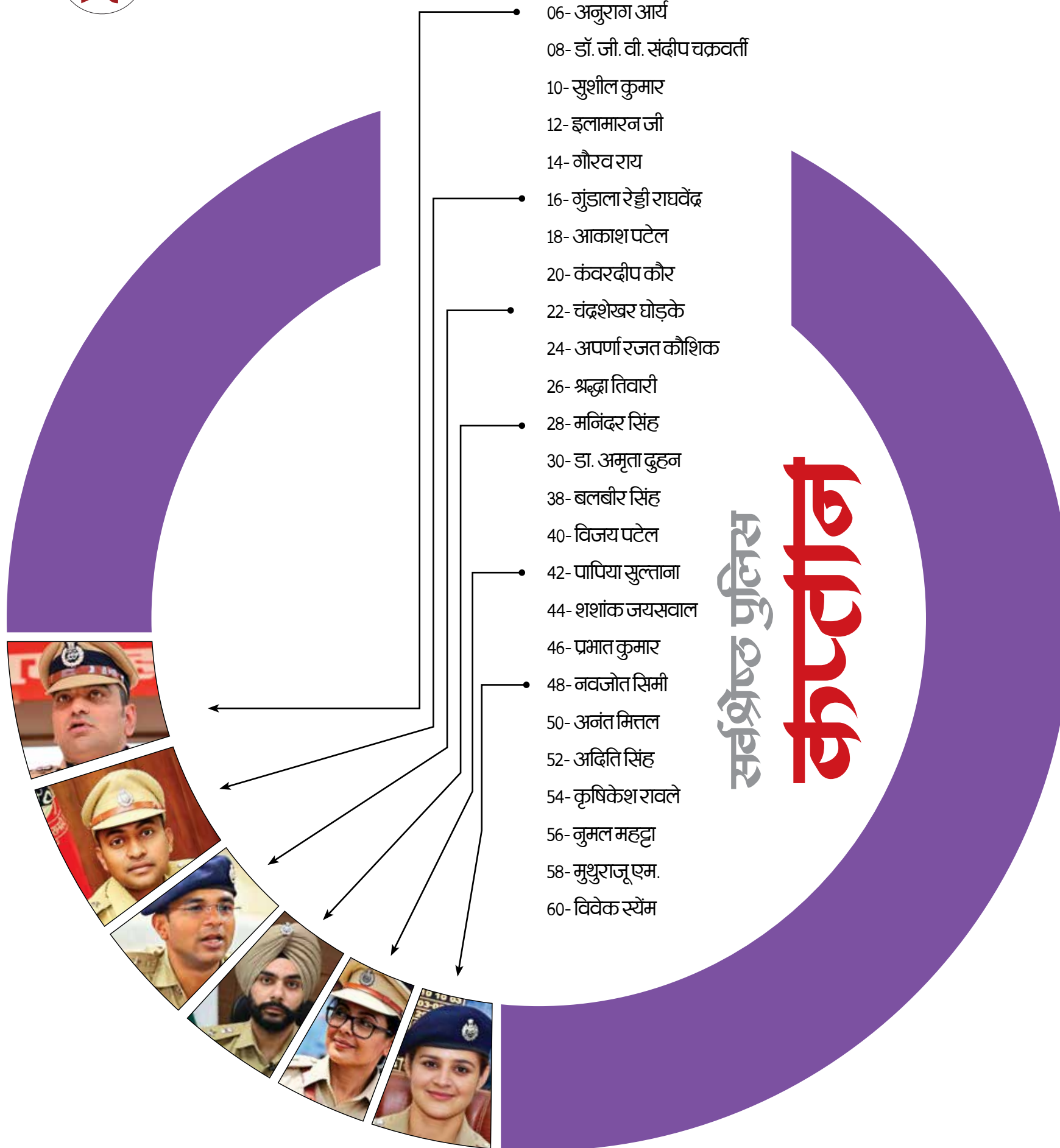
जिनकी चर्चा उतनी नहीं होती जितनी किसी विवाद की होती है।

आलोचना जरूरी है, लेकिन निष्पक्षता उससे भी ज्यादा जरूरी है। यदि किसी पुलिसकर्मियों ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी एक चूक को पूरे पुलिस बल की कार्यशैली का प्रमाण मान लेना उचित नहीं है। यह भी स्वीकार करना होगा कि कठिन और दबावपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले हजारों पुलिसकर्मियों प्रतिदिन ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं।

पुलिस का मनोबल केवल पुरस्कारों से नहीं, बल्कि समाज के भरोसे से बढ़ता है। जब कोई नागरिक पुलिस के अच्छे काम के लिए धन्यवाद देता है, जब किसी अधिकारी या जवान की ईमानदारी और साहस की सार्वजनिक सराहना होती है, तो उसका असर पूरे बल पर पड़ता है।

पुलिस की आलोचना व्यवस्था को सुधार सकती है, लेकिन पुलिस की ईमानदारी सराहना उसका मनोबल बढ़ाती है। जरूरत पुलिस को अंध समर्थन देने की नहीं, बल्कि उसकी कमियों पर सवाल उठाने के साथ उसकी उपलब्धियों को भी निष्पक्षता से स्वीकार करने की है।

धीरज



सुरक्षा और जनविश्वास के प्रतीक

सर्वश्रेष्ठ पुलिस कप्तान

किसी भी विकसित और समृद्ध समाज की सबसे बड़ी पहचान उसके नागरिकों में सुरक्षा और कानून के प्रति विश्वास की भावना होती है। जब नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी शिक्षा, व्यापार, उद्योग, निवेश और सामाजिक गतिविधियां सुचारु रूप से आगे बढ़ती हैं। इसी कारण प्रभावी कानून व्यवस्था किसी भी राज्य और जिले के सर्वांगीण विकास की आधारशिला मानी जाती है।

जिला पुलिस प्रमुख, चाहे वे एसएसपी, एसपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर अथवा समकक्ष अधिकारी हों, कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, साइबर अपराध और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने, सड़क यातायात को सुव्यवस्थित रखने तथा संकट की परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।



एक सक्षम पुलिस कप्तान केवल अपराधियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं करता, बल्कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास का मजबूत संबंध भी विकसित करता है। आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग, पारदर्शी कार्यशैली, जवाबदेही, जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग और सवेदनशील प्रशासन किसी भी जिले में शांति और विकास का मजबूत आधार तैयार करते हैं।

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट ने देशभर के 25 सर्वश्रेष्ठ पुलिस कप्तानों को चुना और प्रकाशित किया है। इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण का उद्देश्य उन पुलिस अधिकारियों के कार्यों को पहचान देना है जिन्होंने अपने नेतृत्व, प्रभावी कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जनोन्मुख पुलिसिंग के माध्यम से समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण स्थापित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

वर्तमान में देशभर में लगभग 1,100 से अधिक जिला पुलिस प्रमुख विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों का नेतृत्व कर रहे हैं। इनमें से केवल 100 अधिकारियों का चयन करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण और बहुस्तरीय प्रक्रिया थी।

सर्वेक्षण के प्रथम चरण में फेम इंडिया और एशिया पोस्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकारों के उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों, विभिन्न प्रशासनिक स्रोतों, मीडिया रिपोर्टों, विशेषज्ञों की राय, सोशल मीडिया विश्लेषण तथा व्यापक ग्राउंड सर्वे के आधार पर देश के शीर्ष 100 पुलिस अधिकारियों की पहचान की है। उनका मूल्यांकन दस प्रमुख मानकों पर किया गया, जिनमें अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था में सुधार, जनमित्र पुलिसिंग, दूरदर्शी नेतृत्व एवं नवाचार, जवाबदेह एवं पारदर्शी कार्यशैली, त्वरित निर्णय क्षमता, सजगता एवं संकट प्रबंधन, व्यवहार कुशलता एवं जनसंपर्क, विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध व्यक्तियों की राय तथा मीडिया एवं सार्वजनिक छवि शामिल हैं।

इन सभी मानकों पर विस्तृत मूल्यांकन के बाद चयनित 25 अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में प्रकाशित किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल उत्कृष्ट अधिकारियों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि देशभर में प्रभावी पुलिस नेतृत्व और जनोन्मुख पुलिसिंग के सफल मॉडलों को सामने लाना भी है।

अनिल सिंह



अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और मजबूत पुलिस नेतृत्व

अनुराग आर्य

बरेली, उत्तर प्रदेश

भारतीय पुलिस सेवा के 2013 बैच के अधिकारी अनुराग आर्य की पहचान ऐसे पुलिस अधिकारी के रूप में बनी है, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए माफिया, संगठित अपराध और गंभीर आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। वर्तमान में बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत अनुराग आर्य इससे पहले उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनके करियर में आजमगढ़, मऊ, अमेठी, बलरामपुर, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र शामिल रहे हैं। आधिकारिक विवरण के अनुसार वे 25 जून 2024 से बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं।



अनुराग आर्य का करियर अपराध के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई, जमीनी पुलिसिंग तथा प्रशासनिक नेतृत्व के संतुलन को दर्शाता है। कानपुर में सट्टा माफिया पर कार्रवाई से लेकर मऊ में आपराधिक साम्राज्य पर प्रहार, आजमगढ़ में बड़े पैमाने पर गैंगस्टर कार्रवाई और जहरीली शराब के नेटवर्क के खिलाफ अभियान तथा बरेली में गंभीर अपराधों और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने तक उनकी कार्यशैली में एक बात लगातार दिखाई देती है—कानून के प्रभावी अनुपालन के साथ अपराधियों के नेटवर्क पर सीधा प्रहार। यही दृष्टिकोण उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुभवी और परिणामोन्मुख अधिकारियों में विशिष्ट स्थान देता है।

आईपीएस सेवा में आने के बाद उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में वाराणसी और गाजियाबाद में कार्य किया। इसके बाद वे कानपुर नगर में पुलिस अधीक्षक नगर पूर्व रहे। वर्ष 2017-18 में कानपुर में एसपी सिटी के रूप में उनके कार्यकाल की एक प्रमुख उपलब्धि सट्टा माफिया के खिलाफ कार्रवाई रही। इस दौरान आईपीएल क्रिकेट से जुड़े सट्टेबाजों पर भी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई संगठित सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की सक्रिय रणनीति का उदाहरण बनी।

इसके बाद अनुराग आर्य को मऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। वर्ष 2019-20 में मऊ में उन्होंने मुख्तार अंसारी के आपराधिक साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की। उनके कार्यकाल में उसके गुर्गों द्वारा करीब चार दशक से संचालित अवैध बूचड़खाने और अवैध चुंगी टैक्स की व्यवस्था को बंद कराया गया तथा करीब 30 अपराधियों को जेल भेजा गया। यह कार्रवाई केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि अवैध आर्थिक गतिविधियों और आपराधिक नेटवर्क की जड़ों पर प्रहार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थी।

अनुराग आर्य के करियर में आजमगढ़ की पोस्टिंग विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। आधिकारिक रिकॉर्ड में भी बरेली से पहले उनकी तैनाती पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के रूप में दर्ज है। इस दौरान उन्होंने अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। उनके कार्यकाल में लगभग 1300 अपराधियों पर कार्रवाई तथा 357 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज किए गए, जिसे जिले में अपराध नियंत्रण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना गया।

आजमगढ़ में ही उन्होंने जहरीली शराब के कारोबार से जुड़े कुख्यात माफिया रमाकांत यादव के खिलाफ कार्रवाई की और उसे जेल भेजा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह अभी भी जेल में निरुद्ध है। जहरीली शराब का कारोबार आम लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई ने अपराध नियंत्रण के साथ जनसुरक्षा को भी प्राथमिकता दी।

इसके बाद वे प्रतापगढ़ और अन्य जिलों में पुलिस अधीक्षक रहे तथा बरेली में पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। इन तैनातियों ने उन्हें जिला पुलिसिंग के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस प्रशासन और कानून-व्यवस्था प्रबंधन का अनुभव दिया। आधिकारिक सेवा विवरण में अमेठी, बलरामपुर, मऊ, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ सहित उनकी विभिन्न जिला तैनातियां दर्ज हैं।

25 जून 2024 को उन्होंने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद संभाला। बरेली में उनके कार्यकाल की शुरुआती बड़ी उपलब्धियों में सीरियल किलर की गिरफ्तारी शामिल रही। वर्ष 2023-24 में 11 महिलाओं की हत्या के मामलों से जुड़े आरोपी कुलदीप को उन्होंने अपनी तैनाती के लगभग डेढ़ महीने के भीतर अगस्त 2024 में गिरफ्तार कराया। लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। इस कार्रवाई ने गंभीर अपराधों की जांच में पुलिस की तत्परता और निगरानी क्षमता को सामने रखा।

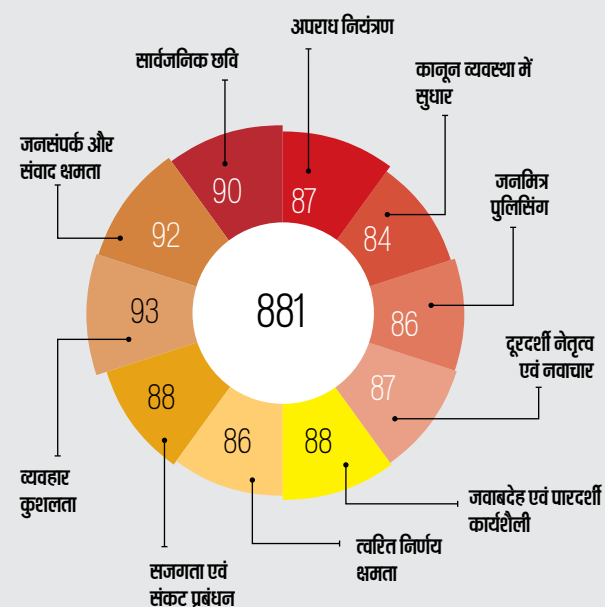
बरेली में वर्ष 2025 में कानून-व्यवस्था की एक चुनौतीपूर्ण स्थिति के दौरान भी पुलिस नेतृत्व की परीक्षा हुई। मौलाना तौकीर द्वारा प्रायोजित बताई गई हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करने के साथ पुलिस ने 12 प्राथमिकी दर्ज कीं और मौलाना तौकीर तथा उसके करीब 90 सहयोगियों को जेल भेजा। इस कार्रवाई में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ उपद्रव में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई।

पुलिस सेवा में अनुराग आर्य के कार्य को लगातार सम्मानों से भी मान्यता मिली है। उन्हें डीजी की कमेंडेशन डिस्क सिल्वर 2020, गोल्ड 2022 और प्लेटिनम 2024 से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 में उन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक भी मिला।

उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष खेलों से जुड़ा है। वे बास्केटबॉल में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं तथा घुड़सवारी और पर्वतारोहण में भी रुचि रखते हैं। खेलों से जुड़ा अनुभव अनुशासन, टीम भावना और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में धैर्य जैसे गुणों को मजबूत करता है।



उत्तर प्रदेश के बागपत में 10 दिसंबर 1987 को जन्मे अनुराग आर्य के पिता रमेश चंद्र आर्य और माता डॉ. पूनम आर्य हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में बीएससी ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की। विज्ञान की पृष्ठभूमि ने उनके भीतर तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को मजबूत किया, जिसका लाभ आगे पुलिस सेवा में निर्णय लेने और अपराध की परिस्थितियों को समझने में मिला।

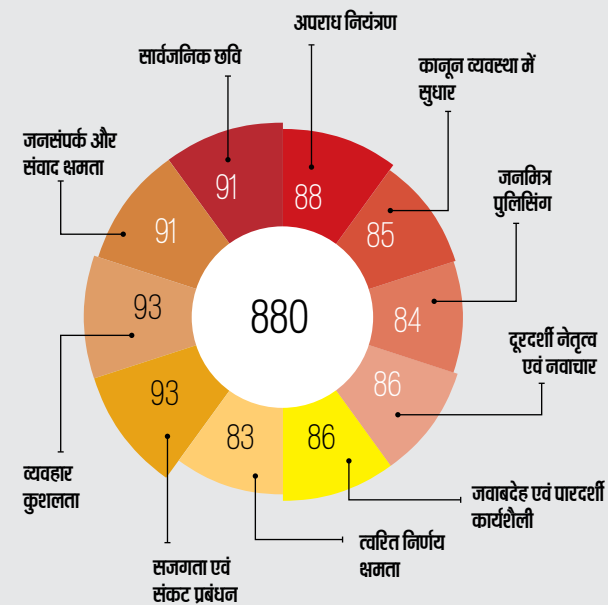


आतंक के खिलाफ रणनीतिक
पुलिसिंग और वीरता की मिसाल

डॉ. जी. वी. संदीप चक्रवर्ती

श्रीनगर, कश्मीर

डॉ. जी. वी. संदीप चक्रवर्ती भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी हैं, जिनकी पहचान केवल उनके पद से नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व, असाधारण साहस और लगातार चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में किए गए कार्यों से बनी है। वर्ष 2014 बैच के आईपीएस और वर्तमान में श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत डॉ. चक्रवर्ती ने अपने करियर का बड़ा हिस्सा जम्मू-कश्मीर के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिसिंग करते हुए बिताया है। आतंकवाद विरोधी अभियानों, खुफिया आधारित कार्रवाई, कानून-व्यवस्था, नार्को-टेरर नेटवर्क के खिलाफ अभियान और युवाओं को कट्टरपंथ से दूर रखने के प्रयासों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।



आं ध्र प्रदेश के कर्नूल में जन्मे और पले-बढ़े डॉ. जी. वी. संदीप चक्रवर्ती का परिवार भी सेवा क्षेत्र से जुड़ा रहा है। उनके पिता डॉ. जी. वी. राम गोपाल राव कर्नूल के सरकारी जनरल अस्पताल में आरएमओ के पद से सेवानिवृत्त हुए, जबकि उनकी माता पी. सी. रंगम्मा स्वास्थ्य विभाग की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने वहीं के मोटिसरी पब्लिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और बाद में कर्नूल मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। सरकारी डॉक्टर के रूप में करियर बनाने के बावजूद उन्होंने भारतीय

छह राष्ट्रपति पुलिस पदक वीरता सहित अनेक सम्मान उनके असाधारण साहस की पहचान हैं, लेकिन उनकी वास्तविक उपलब्धि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लगातार प्रभावी पुलिसिंग करने में दिखाई देती है। उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि आधुनिक पुलिसिंग में साहस के साथ विवेक, रणनीतिक साथ संवेदनशीलता और कार्रवाई के साथ जनविश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डॉ. जी. वी. संदीप चक्रवर्ती का करियर इन्हीं गुणों के संतुलन की एक उल्लेखनीय मिसाल है।



पुलिस सेवा को चुना। चिकित्सा विज्ञान से पुलिस सेवा तक का यह सफर उनके व्यक्तित्व की बहुआयामी क्षमता को दर्शाता है।

डॉ. चक्रवर्ती को प्रारंभ में जम्मू-कश्मीर कैडर आवंटित हुआ था, जो वर्तमान में एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा है। जम्मू-कश्मीर में उनकी पहली महत्वपूर्ण फ़ील्ड जिम्मेदारी 2015-16 में एएसपी पूंछ के रूप में रही। इसके बाद उन्होंने एसडीपीओ उरी और एसडीपीओ सोपोर के रूप में कार्य किया। वर्ष 2018 में वे एसपी ऑपरेशंस, बारामूला रहे। इसी दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनका अनुभव और गहरा हुआ। 2018 से 2020 तक उन्होंने श्रीनगर के साउथ जोन में एसपी की जिम्मेदारी संभाली।

वर्ष 2020 में उन्हें हंदवाड़ा का जिला पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इसके बाद उन्होंने कुपवाड़ा और कुलगाम जैसे संवेदनशील जिलों में जिला पुलिस का नेतृत्व किया। 2021 में कुपवाड़ा और फिर 2021 से 2023 तक कुलगाम में उनकी तैनाती रही। वर्ष 2023 से 2025 तक उन्होंने अनंतनाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2025 से वे श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं।

उनके करियर का सबसे उल्लेखनीय पक्ष आतंकवाद विरोधी अभियान है। उन्होंने विभिन्न कार्यकालों में करीब 150 आतंकवाद विरोधी मुठभेड़ों और अभियानों में सक्रिय रहे या उनका नेतृत्व किया। इन अभियानों में करीब 200 आतंकी मारे जा चुके हैं। हालांकि इन अभियानों की सफलता केवल आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती। डॉ. चक्रवर्ती की पुलिसिंग केवल मुठभेड़ और प्रत्यक्ष कार्रवाई तक सीमित नहीं रही। उन्होंने आतंकियों के समर्थन तंत्र, नार्को-टेरर मॉड्यूल और संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भी कार्रवाई की।

वर्ष 2025 में दिल्ली बम धमाकों के दौरान अचानक संदीप कुमार का नाम राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आया जब उन्होंने कश्मीर में दीवारों पर लगे पोस्टरों के जरिए देश भर में पैर पसार रहे जैश-ए-मोहम्मद के टेरर मोड्यूल को बेनकाब किया। उन्होंने ही हरियाणा के एक मेडिकल कॉलेज में चल रहे डॉक्टरों के जिहादी दस्ते का पर्दाफाश किया और बड़ी वारदातों से देश को बचाया।

उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक वीरता के लिए छह बार और जम्मू-कश्मीर पुलिस पदक वीरता के लिए चार बार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, उत्तरी कमान के जीओसी-इन-सी कमेंडेशन कार्ड तथा जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक की कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभियानों में योगदान के लिए भी उन्हें सम्मान मिला है। उन्हें सीआरपीएफ के डीजीपी की कमेंडेशन डिस्क पांच बार तथा आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी के डीजीपी की कमेंडेशन डिस्क प्राप्त हुई है। इन सम्मानों से विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ उनके प्रभावी समन्वय और परिचालन क्षमता का पता चलता है।

ऑपरेशन महादेव में उनके योगदान के लिए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक भी प्रदान किया गया। यह अभियान पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले से जुड़े आतंकवादियों को निष्प्रभावी करने की कार्रवाई से संबंधित था। ऐसे अभियानों में खुफिया एजेंसियों, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल महत्वपूर्ण होता है।

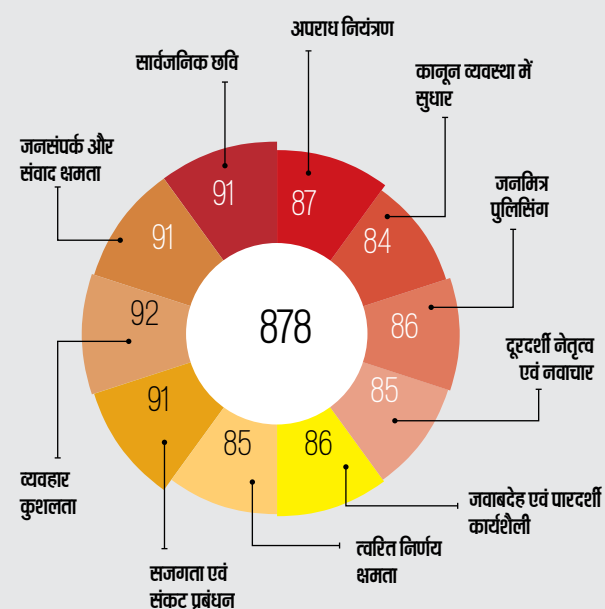
श्रीनगर जैसे महत्वपूर्ण शहर की पुलिस कमान संभालना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है। आतंकवाद, कानून-व्यवस्था, पर्यटन, साइबर अपराध, सुरक्षा और सामुदायिक संबंधों जैसी अनेक चुनौतियां यहां एक साथ मौजूद रहती हैं। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न संवेदनशील जिलों में लंबे समय का मैदानी अनुभव डॉ. चक्रवर्ती को एक विशिष्ट प्रशासनिक और परिचालन दृष्टि प्रदान करता है।

साहस, अनुशासन और परिणाम
आधारित पुलिसिंग

सुशील कुमार

गयाजी, बिहार

भारतीय पुलिस सेवा के 2015 बैच के अधिकारी सुशील कुमार वर्तमान में गयाजी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जनवरी 2026 में बिहार सरकार के बड़े पुलिस फेरबदल में उन्हें मुजफ्फरपुर के एसएसपी पद से स्थानांतरित कर गयाजी का एसएसपी बनाया गया। बिहार के मूल निवासी सुशील कुमार का जन्म 22 फरवरी 1983 को हुआ। उन्होंने नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, और वे आईपीएस में सेलेक्शन से पहले आईआरएस अधिकारी रह चुके हैं।



सुशील कुमार के करियर की शुरुआत से ही फील्ड पुलिसिंग को विशेष महत्व मिला। प्रशिक्षण के बाद वे गया के इमामगंज अनुमंडल में एसडीपीओ रहे। नक्सल प्रभावित और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में यह जिम्मेदारी उनके शुरुआती पुलिस करियर का महत्वपूर्ण अनुभव रही। आधिकारिक सेवा अभिलेखों में उन्हें एसडीपीओ, इमामगंज, गया के रूप में दर्ज किया गया है। इसके बाद उन्होंने लखीसराय के पुलिस अधीक्षक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। लखीसराय में उनके कार्यकाल

सुशील कुमार की सेवा यात्रा में साहसिक ऑपरेशन, फील्ड का अनुभव, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक अनुशासन के चार प्रमुख आयाम दिखाई देते हैं। वीरता के लिए पुलिस पदक उनकी साहसिक पुलिसिंग की पहचान है, जबकि वर्तमान कार्यशैली यह संकेत देती है कि वे कठोर कानून-व्यवस्था के साथ जवाबदेह और सक्रिय पुलिस प्रशासन को भी समान महत्व देते हैं।



ने उनके करियर को विशेष पहचान दिलाई। अपराध नियंत्रण और नक्सल विरोधी अभियानों में उनके नेतृत्व की प्रभावशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण वर्ष 2023 में मिला, जब उन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। यह सम्मान एक फरवरी 2022 को हुए उस अभियान के लिए था, जिसमें सुरक्षा बलों ने घने जंगल वाले क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

इस अभियान में खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि घोघी कोडासी क्षेत्र में नक्सली लेवी वसूलने और एक ठेकेदार के अपहरण की योजना बना रहे हैं। सुशील कुमार ने ऑपरेशन के लिए दो टीमें गठित कीं। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगभग तीन घंटे तक मुठभेड़ चली। सुशील कुमार के नेतृत्व में चले इस अभियान में दो नक्सली मारे गए तथा एसएलआर, आईईडी और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ। राष्ट्रपति की ओर से घोषित पुलिस पदक में इस कार्रवाई को असाधारण साहस, कर्तव्यनिष्ठा और नेतृत्व का उदाहरण माना गया।

वर्ष 2022 में उनका तबादला मधुबनी के पुलिस अधीक्षक के रूप में हुआ जहां एक बड़े और सामाजिक रूप से विविध जिले में उन्होंने कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लगभग दो वर्षों के इनके कार्यकाल में मधुबनी में अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे आया था।

दिसंबर 2024 में सुशील कुमार को मुजफ्फरपुर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया। वहां उन्हें महानगरीय और ग्रामीण दोनों तरह की पुलिसिंग से जुड़ी व्यापक जिम्मेदारियां मिलीं। मुजफ्फरपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले में अपराध नियंत्रण, यातायात, संगठित अपराध, कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के साथ पुलिस बल के प्रशासनिक प्रबंधन पर भी ध्यान देना उनकी भूमिका का हिस्सा रहा।

जनवरी 2026 में गयाजी की कमान उनके लिए एक महत्वपूर्ण वापसी की तरह भी देखी जा सकती है, क्योंकि उनके आईपीएस करियर का शुरुआती दौर इसी जिले में रहा था। लगभग 58 लाख की आबादी, करीब 4,976 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 46 थानों वाले गयाजी जिले को पुलिसिंग की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यहां अपराध नियंत्रण के साथ बोधगया जैसे अंतरराष्ट्रीय धार्मिक एवं पर्यटन केंद्रों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।

गयाजी में उनके कार्यकाल के दौरान अपराध नियंत्रण को लेकर उनका रुख स्पष्ट और सख्त दिखाई दिया है। उन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने का निर्देश दिया। रात में थानों के औचक निरीक्षण के जरिए भी उन्होंने पुलिस व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर नजर रखने का प्रयास किया।

गंभीर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई में भी उनकी सक्रिय भूमिका सामने आई। जून 2026 में गुरुआ बाजार में करीब 45 लाख रुपये के आभूषण लूट और ज्वेलर को गोली मारने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार और लूटा गया सोना बरामद किया गया।

अवैध खनन और बालू माफिया के खिलाफ भी गयाजी पुलिस ने अभियान चलाया। अप्रैल 2026 में पुलिस ने छापेमारी कर 11 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद तेज किए गए अभियान का हिस्सा थी।

महिला सुरक्षा को भी उनकी वर्तमान पुलिसिंग में प्रमुख स्थान मिला है। अगस्त 2026 में उन्होंने गयाजी में 'अभया ब्रिगेड' और 'पुलिस दीदी' टीमों को रवाना किया। महिला पुलिसकर्मियों को दोपहिया वाहनों के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त की जिम्मेदारी दी गई। इसका उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के साथ पुलिस और युवाओं के बीच संवाद बढ़ाना भी है।

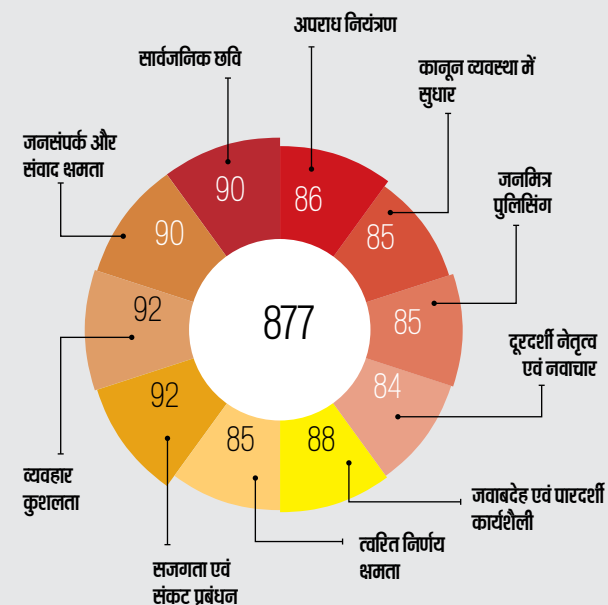


संवेदनशीलता और तकनीक आधारित पुलिसिंग की मिसाल

डॉ. एलामरन जी

एटा, उत्तर प्रदेश

भारतीय पुलिस सेवा में प्रभावी नेतृत्व की पहचान केवल अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने से नहीं होती, बल्कि बदलती सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों को समझते हुए पुलिसिंग को अधिक जवाबदेह, संवेदनशील और परिणामोन्मुख बनाने से होती है। 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. एलामरन जी इसी दृष्टिकोण के साथ पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत डॉ. एलामरन ने अपने करियर में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन, जनसुरक्षा, खुफिया आधारित पुलिसिंग और सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव हासिल किया है।



तमिलनाडु के तिरुवारूर जिले से आने वाले डॉ. एलामरन का पारिवारिक परिवेश ग्रामीण जीवन और मेहनत से जुड़ा रहा है। उनके माता-पिता किसान हैं। कृषि पृष्ठभूमि से निकलकर भारतीय पुलिस सेवा तक पहुंचना उनकी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिचायक है। उन्होंने पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री यानी एमवीएससी की शिक्षा प्राप्त की। चिकित्सा और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ने उनके व्यक्तित्व में विश्लेषणात्मक सोच

डॉ. एलामरन की कार्यशैली का महत्वपूर्ण पक्ष कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ अपराध की रोकथाम पर विशेष जोर है। उनका मानना है कि पुलिसिंग का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराध के संभावित कारणों और पैटर्न को समय रहते पहचानकर उसे रोकना भी है। इसके लिए डेटा आधारित विश्लेषण और खुफिया सूचनाओं का प्रभावी इस्तेमाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी पुलिसिंग में अपराध के पैटर्न और हॉटस्पॉट की पहचान कर लक्षित रणनीति तैयार करने पर जोर दिया जाता है।



और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत किया, जिसका उपयोग वे पुलिसिंग में भी करते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा में आने के बाद उनका प्रशिक्षण आगरा में हुआ, फिर क्षेत्राधिकारी के रूप में आजमगढ़ में जिम्मेदारी संभाली। यह उनके लिए जमीनी पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था को समझने का महत्वपूर्ण चरण था। इसके बाद वे नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात रहे। इसके बाद उन्होंने अमेठी, मऊ और एटा जैसे जिलों में जिला पुलिस नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। अलग-अलग सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों वाले इन जिलों में कार्य करने से उन्हें पुलिसिंग के विविध आयामों को समझने का अवसर मिला। वर्तमान में एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में वे जिले की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की समग्र जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

सड़क सुरक्षा भी उनके पेशेवर दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क दुर्घटनाओं को केवल यातायात संबंधी समस्या के रूप में नहीं, बल्कि जनसुरक्षा से जुड़े गंभीर विषय के रूप में देखा जाना आवश्यक है। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान, यातायात नियमों के पालन, जागरूकता और संबंधित विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से सड़क हादसों को कम करने की दिशा में रणनीति विकसित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी उनका दृष्टिकोण संवेदनशील और सक्रिय है। कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए प्रभावी पुलिसिंग के साथ त्वरित शिकायत निवारण, भरोसेमंद पुलिस संपर्क और आवश्यक होने पर तकनीकी संसाधनों का उपयोग महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि पुलिस व्यवस्था की वास्तविक सफलता तभी है जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे।

बदलते दौर में साइबर अपराध और तकनीक-आधारित अपराध पुलिस के सामने नई चुनौती बनकर उभरे हैं। डॉ. एलामरन पुलिस की तकनीकी क्षमता बढ़ाने और आधुनिक जांच पद्धतियों के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण मानते हैं। साइबर अपराध की पहचान, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण और तकनीक आधारित अपराधों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की क्षमता विकसित करना आधुनिक पुलिसिंग की आवश्यकता है।

पुलिस बल के भीतर अनुशासन, जवाबदेही और पेशेवर मानकों को मजबूत करना भी उनकी नेतृत्व शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जोर टीमवर्क और स्पष्ट जिम्मेदारी पर रहता है। उनके अनुसार किसी भी पुलिस संगठन की प्रभावशीलता उसके संसाधनों से अधिक उसके मानव संसाधन, नेतृत्व और कार्य संस्कृति पर निर्भर करती है।

जनता और पुलिस के बीच विश्वास को वे प्रभावी पुलिसिंग की आधारशिला मानते हैं। इसके लिए पुलिस का सुलभ, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित होना जरूरी है। शिकायत सुनने से लेकर कार्रवाई की जानकारी देने तक, पुलिस की संवेदनशीलता और पारदर्शिता जनता के विश्वास को मजबूत करती है।

डॉ. एलामरन का नेतृत्व दर्शन आधुनिक पुलिसिंग को व्यापक सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है। उनके अनुसार कानून लागू करना आवश्यक है, लेकिन कानून के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तकनीक, खुफिया जानकारी, डेटा और नवाचार को मानवीय दृष्टिकोण के साथ जोड़कर ही सुरक्षित और भरोसेमंद समाज का निर्माण किया जा सकता है।

उनकी पेशेवर दृष्टि एक ऐसी पुलिस व्यवस्था विकसित करने की है, जो तकनीक आधारित, खुफिया संचालित, नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह हो तथा साथ ही संवैधानिक मूल्यों और पेशेवर मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। डॉ. एलामरन जी की कार्यशैली यह संदेश देती है कि आधुनिक पुलिसिंग की असली ताकत कठोर कार्रवाई के साथ तकनीक, नवाचार, टीमवर्क और मानवीय संवेदनशीलता के संतुलन में है।

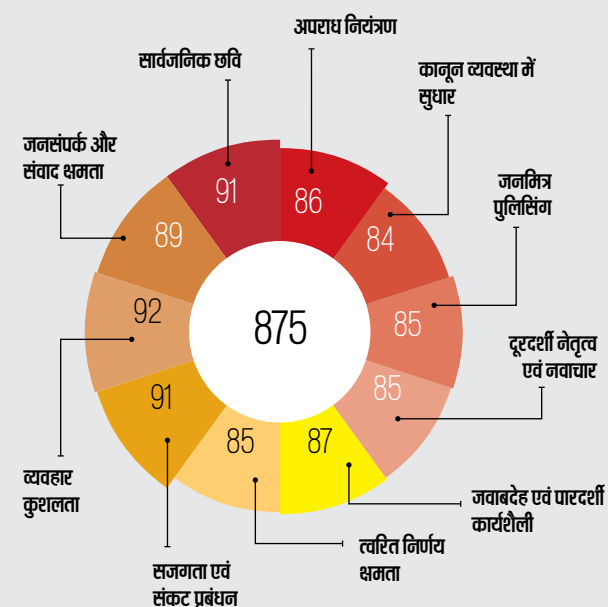


नक्सल मोर्चे से जनकेंद्रित पुलिसिंग तक

गौरव राय

दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ (अब बलोदाबाजार)

महाराष्ट्र के अमरावती निवासी गौरव राय ने पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। सिविल सेवा की कठिन परीक्षा क्रैक करने के बाद उन्हें 2019 में छत्तीसगढ़ कैडर मिला। बीजापुर में कुछ समय तक रहने के बाद उनकी पोस्टिंग वर्ष 2023 में कमी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले दंतेवाड़ा के एसपी के तौर पर हुई। दंतेवाड़ा की पुलिस कमान किसी सामान्य जिले की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। इस क्षेत्र में पुलिसिंग का अर्थ केवल अपराध नियंत्रण नहीं, बल्कि सुरक्षा बलों की प्रभावी तैनाती, खुफिया सूचनाओं का उपयोग, दूरदराज के इलाकों तक प्रशासन की पहुंच और स्थानीय लोगों में भरोसा कायम करना भी है।



छत्तीसगढ़ कैडर के 2019 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी गौरव राय ने चुनौतीपूर्ण नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रभावी और रणनीतिक पुलिसिंग की पहचान बनाई। मई 2023 में दंतेवाड़ा के एसपी का पदभार संभालने के बाद उन्होंने सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने पर विशेष जोर दिया।

तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी उनका दृष्टिकोण आधुनिक पुलिसिंग के अनुरूप रहा। सुरक्षा और जांच व्यवस्था को अधिक सटीक बनाने के लिए सीसीटीवी निगरानी और एआई आधारित वीडियो एनालिटिक्स जैसे तकनीकी साधनों के उपयोग पर जोर दिया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलावा सामान्य अपराध नियंत्रण में भी तकनीक पुलिस को घटनाओं के विश्लेषण, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने में सहायता देती है।



उनकी कार्यशैली का प्रमुख पक्ष नक्सल विरोधी अभियानों में रणनीतिक दृष्टिकोण रहा। दंतेवाड़ा में पदभार संभालने के बाद उन्होंने सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान चलाने के लिए स्थानीय स्तर की सूचनाओं, क्षेत्र की भौगोलिक समझ और विभिन्न सुरक्षा इकाइयों के बीच तालमेल की विशेष आवश्यकता होती है। उनके नेतृत्व में पुलिस ने इसी समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया।

दंतेवाड़ा में उनकी पुलिसिंग का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सुरक्षा के साथ विकास को गति देना रहा। नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतों को पहुंचाना तभी संभव है जब वहां सुरक्षा का भरोसा हो। ऐसे क्षेत्रों में पुलिस की भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विकास एजेंसियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की भी होती है। गौरव राय ने पुलिस और जिला प्रशासन के बीच समन्वय के माध्यम से ऐसे प्रयासों को सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया।

इसका सीधा संबंध ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विश्वास से भी है। लंबे समय तक हिंसा से प्रभावित रहे दंतेवाड़ा में सरकारी संस्थाओं की मौजूदगी मजबूत करना एक बड़ी चुनौती थी। बंद पड़े अंदरूनी रास्तों को फिर से खोलकर विकास कार्यों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा रहा। इस दृष्टिकोण में पुलिस को केवल सुरक्षा बल के रूप में नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया के सहयोगी के रूप में भी देखा गया।

नक्सल समस्या से निपटने में केवल सशस्त्र कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए वहां 'लोन वरटू' अभियान को गति देने के प्रयास इसी सोच से जुड़े रहे। पूर्व नक्सलियों को शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ना इस रणनीति का अहम हिस्सा रहा। पुलिस और प्रशासन का उद्देश्य यह संदेश देना रहा कि हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौटने वालों के लिए पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की संभावनाएं मौजूद हैं।

ऐसे अभियानों में पुलिस नेतृत्व की भूमिका केवल अभियान चलाने तक सीमित नहीं होती। आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन, पुलिस और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय आवश्यक होता है। गौरव राय के कार्यकाल में इस पहल को सुरक्षा रणनीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में आगे बढ़ाया गया।

दंतेवाड़ा में उनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण पहलू पुलिस बल का मनोबल बढ़ाना भी रहा। चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात जवानों के लिए नेतृत्व की स्पष्टता, बेहतर समन्वय और कमांड स्तर पर भरोसा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऑपरेशनल पुलिसिंग में निर्णय लेने की क्षमता और टीम के प्रत्येक सदस्य को एक साझा लक्ष्य से जोड़ना किसी भी अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

करीब तीन वर्षों तक दंतेवाड़ा में जिम्मेदारी निभाने के बाद जुलाई 2026 में राज्य सरकार के बड़े पुलिस फेरबदल में गौरव राय का तबादला बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में किया गया। बलौदाबाजार उनके लिए दंतेवाड़ा से अलग तरह की पुलिसिंग की चुनौती लेकर आया है। यहां बदलते शहरी और ग्रामीण अपराध, साइबर अपराध, यातायात, अवैध शराब तथा कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

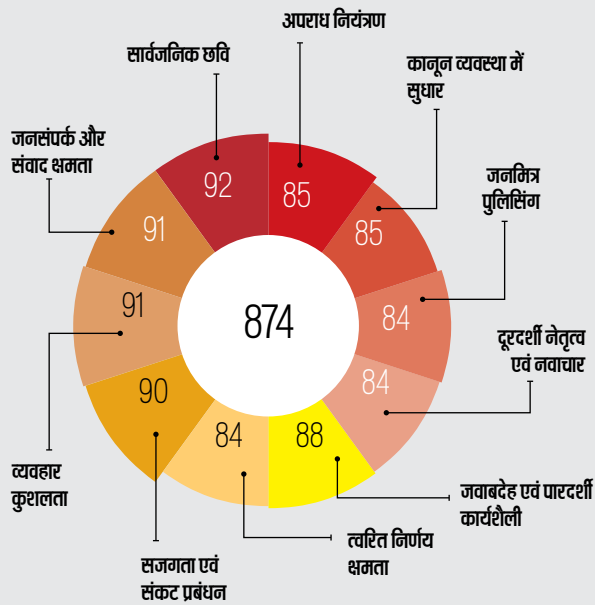
गौरव राय का करियर इस बदलाव का उदाहरण है कि एक पुलिस अधिकारी को परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। अनुशासन, तकनीक, टीमवर्क और जनता का विश्वास उनके नेतृत्व की केंद्रीय कड़ियां दिखाई देती हैं। यही संतुलन उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस के उभरते हुए फील्ड ऑफिसर्स में एक अलग पहचान देता है।

कर्मठता, साहस और संवेदनशील पुलिसिंग से बनाई अलग पहचान

गुंडला रेड्डी राघवेन्द्र

झारसुगुड़ा, ओडिशा

ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक 2019 बैच के आईपीएस गुंडला रेड्डी राघवेन्द्र तकनीक, जमीनी खुफिया तंत्र और तेज कार्रवाई को साथ लेकर चलने वाले अधिकारी हैं। उनकी कार्यशैली का विशेष पहलू यह है कि वे पारंपरिक पुलिसिंग को आधुनिक तकनीकी साधनों के साथ जोड़कर अपराध की रोकथाम और अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।



राघवेन्द्र का जन्म 13 जून 1988 को हुआ और उनका गृह राज्य आंध्र प्रदेश है। उन्होंने बी.टेक. की शिक्षा प्राप्त की और 2019 बैच में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। उन्हें 2019 में ओडिशा कैडर आवंटित हुआ और उनके करियर की शुरुआत गंजाम में प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में हुई। उनके कार्य की गुणवत्ता और पेशेवर क्षमता को देखते हुए उन्हें सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में उत्कृष्ट प्रशिक्षु के रूप में मान्यता मिली।

झारसुगुड़ा पुलिस में राघवेन्द्र ने तकनीक और मानवीय खुफिया जानकारी को एक साथ इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य अपराधियों की गतिविधियों को केवल घटना के बाद समझना नहीं, बल्कि उनके नेटवर्क, संपर्क और गतिविधियों के पैटर्न को पहले से पहचानना है। उनकी टीम की कार्यशैली का एक उदाहरण जुलाई 2026 में सामने आया, जब झारसुगुड़ा पुलिस ने विदेशी शराब की दुकानों को निशाना बनाने वाले अंतर-जिला गिरोह का पर्दाफाश किया। दो दुकानों में हुई चोरी के मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जानकारी और फील्ड इनपुट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई तथा अलग-अलग स्थानों पर विशेष जांच दल भेजे थे।



नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच उन्होंने कंधमाल जिले के बालिगुड़ा में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्य किया। यह क्षेत्र नक्सली गतिविधियों और संवेदनशील कानून-व्यवस्था की चुनौतियों के लिए जाना जाता है। उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में फरवरी 2022 में तीन-स्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों का शांतिपूर्ण संचालन शामिल रहा।

उनके करियर का एक महत्वपूर्ण चरण नुआपाड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में रहा। यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता है और यहां माओवादी गतिविधियों से निपटना पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी रही है। राघवेन्द्र के कार्यकाल में जिला पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच समन्वय के साथ कई अभियान चलाए गए। जुलाई 2025 में नुआपाड़ा के जंगलों में जिला स्वैच्छिक बल (DVF) और CRPF ने एक संयुक्त अभियान में माओवादी कैप का पता लगाया। वहां से देशी बंदूक, गोलियां, जिलेटिन स्टिक, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, बारूद, संचार उपकरण, दवाइयां और अन्य सामान बरामद किया गया। इस अभियान का नेतृत्व राघवेन्द्र ने किया था।

इसी अवधि में नुआपाड़ा के नारायण डोंगर रिजर्व फॉरेस्ट में भी सुरक्षा बलों ने एक माओवादी कैप का पता लगाया था। खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए इस अभियान में टिफिन आईईडी, जिलेटिन स्टिक, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। इन अभियानों से यह संकेत मिलता है कि उनके नेतृत्व में पुलिस ने केवल घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय खुफिया जानकारी और क्षेत्रीय निगरानी के माध्यम से खतरे को पहले पहचानने पर जोर दिया।

झारसुगुड़ा में उनकी वर्तमान भूमिका उनके पुलिसिंग मॉडल के दूसरे पहलू को सामने लाती है। झारसुगुड़ा ओडिशा का औद्योगिक रूप से विकसित और खनिज संपदा से समृद्ध जिला है। यहां औद्योगिक गतिविधियों, शहरीकरण, आर्थिक गतिविधियों और साइबर अपराध जैसी विभिन्न चुनौतियों के कारण पुलिसिंग का स्वरूप भी जटिल है।

झारसुगुड़ा में उनकी पुलिसिंग का एक और उदाहरण जुलाई 2026 का बेलपहाड़ ब्लाइंड मर्डर केस है, जिसे पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सुलझा लिया। जांच में तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी विश्लेषण और मानवीय खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद किए गए।

राघवेन्द्र की कार्यशैली को तीन शब्दों में समझा जा सकता है—ईटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और स्पीड। नुआपाड़ा में जहां चुनौती माओवादी गतिविधियों और जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों की थी, वहीं झारसुगुड़ा में उनका सामना साइबर अपराध, संगठित अपराध, चोरी और शहरी अपराध की बदलती प्रकृति से है। दोनों परिस्थितियों में उनका जोर सूचना के बेहतर इस्तेमाल और तेजी से कार्रवाई पर दिखाई देता है।

उनकी उपलब्धियों को विभिन्न स्तरों पर सम्मान भी मिला है। उन्हें सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का उत्कृष्ट प्रशिक्षु, 2025 का केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, विशेष अभियानों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक, पुलिस महानिदेशक का पदक और कई प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें नक्सल प्रभावित जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने तथा 'ऑपरेशन साइबर कवच' में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिले सम्मान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

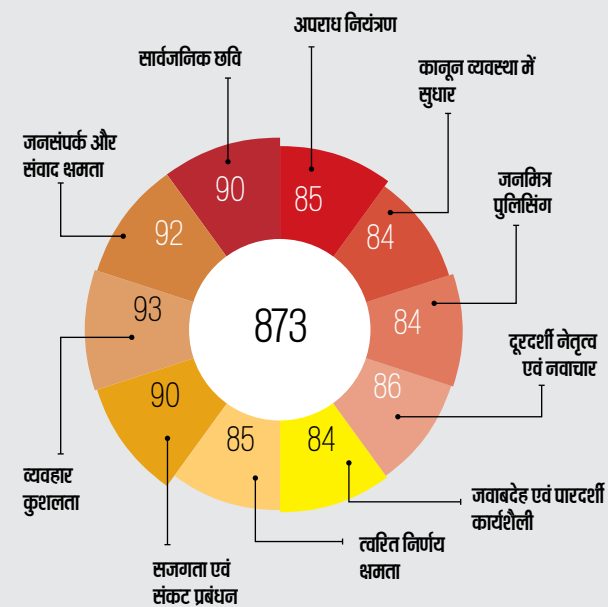
उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि आज की पुलिसिंग केवल बल और कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गई है। आधुनिक पुलिस अधिकारी को तकनीक समझने, डेटा और डिजिटल साक्ष्यों का इस्तेमाल करने, जमीनी नेटवर्क विकसित करने और दबाव की स्थिति में तेजी से निर्णय लेने की क्षमता भी रखनी होती है। गुंडला रेड्डी राघवेन्द्र इसी बदलती पुलिसिंग व्यवस्था में अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं।

आधुनिक सोच और प्रभावी पुलिसिंग की नई मिसाल

आकाश पटेल

चंदौली, उत्तर प्रदेश

कुछ अधिकारी अपनी कार्यशैली, अनुशासन और बदलती चुनौतियों को समझने की क्षमता के कारण अलग पहचान बनाते हैं। 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी आकाश पटेल ऐसे ही अधिकारियों में शामिल हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत पटेल ने अपने करियर में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जांच, पुलिस प्रशासन और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया है।



उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से आने वाले आकाश पटेल की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर, फतेहपुर से हुई। उन्होंने कक्षा 12 तक की पढ़ाई वहीं पूरी की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में बीए और एमए की डिग्री प्राप्त की। उनकी सिविल सेवा यात्रा विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। वर्ष 2015 में उनका चयन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में हुआ और उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आवंटित किया गया।

उनकी कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पहलु डेटा आधारित और तकनीक समर्थित पुलिसिंग है। बदलते दौर में साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और संगठित अपराध जैसी चुनौतियां पुलिस के सामने तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में आंकड़ों का विश्लेषण, आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग और सूचना के आधार पर निर्णय लेना पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बना सकता है। पुलिस प्रशासन और प्रदर्शन प्रबंधन भी उनके पेशेवर दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जोर पुलिस बल में अनुशासन, जवाबदेही, बेहतर प्रशिक्षण और कार्यक्षमता बढ़ाने पर है।



इसके बाद उनका चयन 2017 बैच की भारतीय राजस्व सेवा, आयकर में हुआ। उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा में प्रवेश लिया और प्रशिक्षण भी शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में एक और बड़ी सफलता हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित हुए। वर्ष 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी के रूप में उनका चयन उनके दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत का परिणाम रहा।

आईपीएस अधिकारी के तौर पर आकाश पटेल की पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में सहायक पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद की तैनाती शामिल रही। तेजी से विकसित हो रहे गाजियाबाद जैसे बड़े शहरी क्षेत्र में उन्हें कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जटिल चुनौतियों से निपटने का अनुभव मिला। इसके बाद उन्हें लखनऊ में राज्यपाल के एडीसी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इस भूमिका में सुरक्षा, प्रोटोकॉल, प्रशासनिक समन्वय और संवैधानिक पद की गरिमा से जुड़ी जिम्मेदारियों का अनुभव प्राप्त हुआ।

इसके बाद उन्होंने कानपुर कमिश्नरेट में एडीसीपी ईस्ट और एडीसीपी वेस्ट के रूप में कार्य किया। कानपुर जैसे बड़े औद्योगिक शहर में पुलिसिंग के दौरान कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस बल के प्रबंधन और विभिन्न स्तरों पर समन्वय की जिम्मेदारियां उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहीं। अलग-अलग क्षेत्रों की कमान संभालने से उन्हें शहरी पुलिसिंग की जटिलताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति तैयार करने का व्यापक अनुभव मिला।

वाराणसी में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। वे एडीसीपी गोमती जोन और बाद में डीसीपी गोमती जोन रहे। वाराणसी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। यहां पुलिसिंग में सामान्य कानून-व्यवस्था के साथ धार्मिक आयोजनों का प्रबंधन, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था तथा संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। इस अनुभव ने उनके प्रशासनिक और परिचालन कौशल को और मजबूत किया।

वर्तमान में आकाश पटेल चंदौली के पुलिस अधीक्षक के रूप में जिले की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। जिला पुलिस प्रमुख के रूप में उनकी जिम्मेदारियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध की रोकथाम, गंभीर आपराधिक मामलों की निगरानी, जांच की गुणवत्ता में सुधार और पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाना शामिल है। उनका प्रयास पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, सक्रिय और जनकेंद्रित बनाने की दिशा में है।

आकाश पटेल की पेशेवर रुचियों में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के साथ आपराधिक जांच तथा आपराधिक न्याय व्यवस्था प्रमुख हैं। उनका दृष्टिकोण यह है कि प्रभावी पुलिसिंग केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अपराध की रोकथाम, वैज्ञानिक जांच, बेहतर अभियोजन और तकनीक के इस्तेमाल के जरिए न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना भी पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

पुलिस सेवा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें डीजी की कमेंडेशन डिस्क—सिल्वर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके कार्य और पुलिसिंग में योगदान के प्रति वरिष्ठ स्तर पर मिली सराहना को दर्शाता है।

आकाश पटेल की यात्रा एक ऐसे युवा आईपीएस अधिकारी की कहानी है, जिसने अलग-अलग सरकारी सेवाओं के अनुभव से गुजरते हुए पुलिस सेवा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। फतेहपुर से शिक्षा की शुरुआत, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य की पढ़ाई, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और भारतीय राजस्व सेवा में चयन तथा अंततः भारतीय पुलिस सेवा तक पहुंचना उनकी निरंतर मेहनत और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

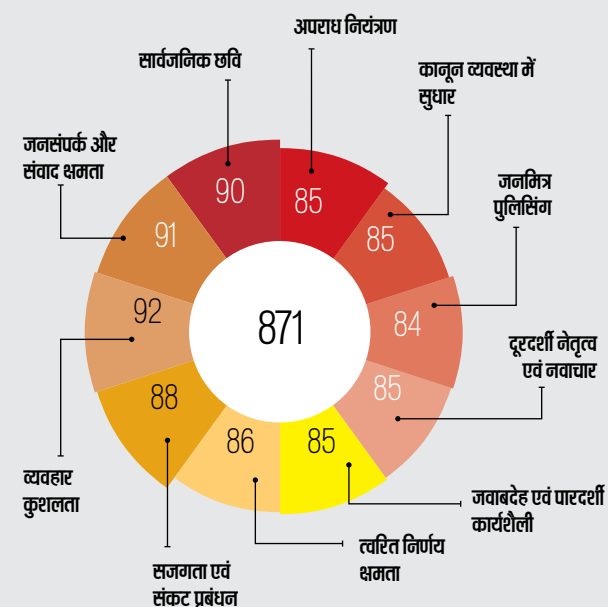
कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण जांच, पुलिस प्रशासन और तकनीक आधारित पुलिसिंग पर उनका जोर उन्हें ऐसे अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो पारंपरिक पुलिसिंग के अनुभव को आधुनिक सोच और तकनीकी दृष्टिकोण के साथ जोड़कर प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख पुलिस व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

दृढ़ नेतृत्व और आधुनिक पुलिसिंग की साहसिक पहचान

कंवरदीप कौर

चंडीगढ़, पंजाब

कंवरदीप कौर भारतीय पुलिस सेवा की उन महिला अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर की पुलिसिंग, अपराध अनुसंधान और प्रशासनिक नेतृत्व के साथ अपनी अलग पहचान बनाई है। 2013 बैच की पंजाब कैडर की आईपीएस अधिकारी कंवरदीप कौर वर्तमान में चंडीगढ़ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। वे मार्च 2023 में इस पद पर नियुक्त हुई थीं और चंडीगढ़ की दूसरी महिला एसएसपी बनीं। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने उनकी अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया, जिसके बाद वे मार्च 2027 तक चंडीगढ़ पुलिस का नेतृत्व करेंगी।



पंजाब से संबंध रखने वाली कंवरदीप कौर ने अपनी स्कूली शिक्षा मोहाली और चंडीगढ़ में पूरी की और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उनकी शैक्षणिक योग्यता बीई है और जन्मतिथि 25 अगस्त 1988 है। वर्ष 2013 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन के बाद उन्होंने पंजाब कैडर में सेवा शुरू की। उनके शुरुआती करियर का बड़ा हिस्सा पंजाब पुलिस में फील्ड और खुफिया जिम्मेदारियों के बीच बीता। वे एआईजी

चंडीगढ़ जैसे आधुनिक और तेजी से बदलते शहर में उनकी पुलिसिंग की चुनौती पारंपरिक अपराध नियंत्रण से कहीं व्यापक है। शहर में साइबर अपराध, नशे की तस्करी, सड़क अपराध, महिलाओं की सुरक्षा, रात्रिकालीन गतिविधियां और संगठित अपराध जैसे मुद्दे पुलिस के सामने लगातार मौजूद रहते हैं। कंवरदीप कौर ने साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने और 1930 साइबर हेल्पलाइन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। नशे के खिलाफ कार्रवाई और अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी को भी उनकी प्राथमिकताओं में रखा गया।



काउंटर इंटेलिजेंस के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने कपूरथला और फाजिल्का सहित महत्वपूर्ण जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाली। कपूरथला में उनके कार्यकाल के दौरान गंभीर आपराधिक मामलों की जांच और त्वरित कार्रवाई ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। बाद में फाजिल्का की एसएसपी के रूप में भी उन्होंने जिला पुलिस का नेतृत्व किया।

उनके करियर की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक गंभीर यौन अपराध के मामले की जांच से जुड़ी है। कपूरथला की एसएसपी रहते हुए उन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले की जांच की निगरानी की। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 12 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल किया और अदालत ने आरोपी को घटना के 11 महीने के भीतर मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसी उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उन्हें वर्ष 2023 का केंद्रीय गृह मंत्री पदक उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए प्रदान किया गया। यह सम्मान देशभर में चुने गए 140 पुलिसकर्मियों में शामिल था और इनमें 22 महिला पुलिस अधिकारी थीं।

चंडीगढ़ की एसएसपी के रूप में कंवरदीप कौर की प्राथमिकताएं शुरू से स्पष्ट रही हैं। पद संभालने के समय उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, अपराध की रोकथाम और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता को प्रमुख लक्ष्य बताया था। उन्होंने पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद, सामुदायिक पुलिसिंग और बीट अधिकारियों की जवाबदेही को भी महत्वपूर्ण माना।

वर्ष 2025 में चंडीगढ़ पुलिस के प्रदर्शन में सड़क अपराध में कमी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्नैचिंग के मामले 2024 के 131 से घटकर 2025 में 100 रह गए, यानी लगभग 24 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। गंभीर अपराधों में भी अधिकांश मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया। पुलिस ने नशे, साइबर धोखाधड़ी और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई का दायरा भी बढ़ाया।

चंडीगढ़ पुलिस ने उनकी अगुवाई में आधुनिक तकनीक और नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप पुलिसिंग को भी मजबूत किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला ऐसा क्षेत्र बना, जहां भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन का दावा किया गया। अपराध स्थल की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन और महिलाओं से जुड़े मामलों में जीरो एफआईआर जैसी व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा मिला।

उनकी नेतृत्व क्षमता का एक और उदाहरण 2025 में पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों के दौरान देखने को मिला। संवेदनशील स्थिति में उन्होंने छात्र नेताओं से सीधे संवाद बनाए रखते हुए हिंसा रोकने और परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस तरह की परिस्थितियों में पुलिस के लिए बल प्रयोग और संवाद के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होता है।

कंवरदीप कौर को पुलिस प्रशासन में उनके योगदान के लिए चंडीगढ़ पुलिस का गोल्ड डिस्क भी प्राप्त हुआ है। आधिकारिक रिकॉर्ड में 2024 में उनके नाम के साथ गोल्ड डिस्क दर्ज है। इसके अतिरिक्त 2023 का केंद्रीय गृह मंत्री पदक उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उनकी पेशेवर उपलब्धियों का महत्वपूर्ण प्रमाण है।

कंवरदीप कौर की पंजाब के विभिन्न जिलों में पुलिस नेतृत्व से लेकर काउंटर इंटेलिजेंस और फिर चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण केंद्रशासित क्षेत्र की कमान तक उनकी यात्रा व्यापक अनुभव को दर्शाती है। उनका करियर इस बात का उदाहरण है कि प्रभावी पुलिस नेतृत्व में कठोरता के साथ संवेदनशीलता, कार्रवाई के साथ संवाद और परंपरागत पुलिसिंग के साथ तकनीक का संतुलन आवश्यक है।



तकनीक और सख्त पुलिसिंग का संतुलन

चंद्रशेखर घोड़ेके

अल्मोड़ा, उत्तराखंड

उत्तराखंड पुलिस में चंद्रशेखर घोड़ेके एक ऐसे अधिकारी हैं, जिनकी योग्यताएं बहुआयामी हैं। पुलिसिंग में तकनीक, अपराध अनुसंधान, नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने पर उनका विशेष जोर रहा है। वर्तमान में अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत घोड़ेके ने अपनी सेवा के दौरान उधम सिंह नगर और बागेश्वर जैसे जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनकी कार्यशैली में फील्ड पुलिसिंग के साथ तकनीकी दक्षता और आधुनिक प्रशासनिक प्रणालियों को अपनाने की स्पष्ट झलक मिलती है।



चंद्रशेखर घोड़ेके की पुलिस यात्रा तकनीकी शिक्षा, निजी क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र के अनुभव को फील्ड पुलिसिंग से जोड़ने की कहानी है। उनकी कार्यशैली का एक साझा तत्व दिखाई देता है: आधुनिक तकनीक को प्रभावी पुलिस कार्रवाई के साथ जोड़ना। यही दृष्टिकोण उन्हें उत्तराखंड पुलिस के उल्लेखनीय युवा पुलिस अधिकारियों में अलग पहचान देता है।

पुलिसिंग में भी उपयोगी साबित हुआ। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से पुलिस प्रबंधन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है।

भारतीय पुलिस सेवा में आने के बाद उनकी शुरुआती तैनाती उत्तराखंड में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई। उन्होंने देहरादून व उधम सिंह नगर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में एसपी की जिम्मेदारी संभाली। आगे चलकर वे उधम सिंह नगर में एसपी क्राइम एवं ट्रैफिक बने जहां कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की निगरानी में अहम भूमिका निभाई। भरामल बाबा और बाबा तरसेम हत्याकांड जैसे चर्चित मामलों की विवेचना की करीबी निगरानी उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में रही।

साइबर अपराधों और आर्थिक अपराधों की जांच में भी उनका तकनीकी अनुभव उपयोगी साबित हुआ। रुद्रपुर स्थित इंडसट्रियल बैंक से सरकारी खातों की धनराशि के कथित रूप से साइफन किए जाने के मामले में उनकी निगरानी में जांच आगे बढ़ी। इस प्रकरण में 12 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी धनराशि कुछ ही दिनों में सफलतापूर्वक बरामद कर ली गई।

इसके बाद चंद्रशेखर घोड़ेके को बागेश्वर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया जहां उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान नशे के खिलाफ अभियान रही। पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई की और वर्ष 2025 में उत्तराखंड में चरस की सबसे बड़ी बरामदगी बागेश्वर जिले में की गई। इसी अवधि में कुमाऊं रेंज में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई। साफ था, कि उनकी रणनीति केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं रही, बल्कि कानूनी प्रावधानों का प्रभावी इस्तेमाल कर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने पर भी केंद्रित रही।

बागेश्वर में उनका एक और उल्लेखनीय प्रयास पुलिस प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ा रहा। जिला पुलिस ने रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों के लिए ई-ऑफिस व्यवस्था अपनाई और बागेश्वर उत्तराखंड का पहला पुलिस जिला बना, जहां इस प्रणाली को दैनिक कामकाज में लागू किया गया। इससे फाइलों के निस्तारण, रिकॉर्ड प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने की कोशिश हुई।

फरवरी 2026 में चंद्रशेखर घोड़ेके ने अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। पहाड़ी जिले में पुलिसिंग की अपनी अलग चुनौतियां हैं। दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, पर्यटन का बढ़ता दबाव, सड़क दुर्घटनाएं, नशे की समस्या और दूरस्थ इलाकों तक पुलिस की पहुंच जैसे विषय यहां विशेष महत्व रखते हैं। कार्यभार संभालते हुए उन्होंने महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, नशे के खिलाफ कार्रवाई और अपराध नियंत्रण को प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा।

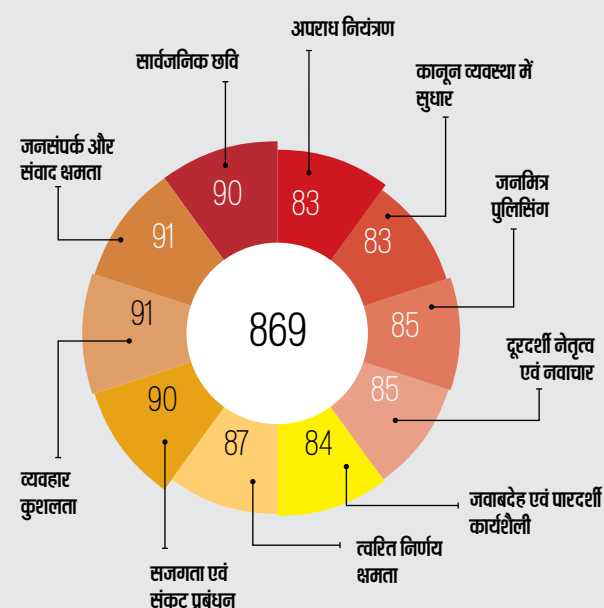
अल्मोड़ा में उनका विशेष फोकस तकनीक आधारित यातायात प्रबंधन पर दिखाई देता है। स्मार्ट कंट्रोल रूम और तकनीकी निगरानी के माध्यम से यातायात नियमों के प्रभावी प्रवर्तन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तेजी से बढ़ते वाहन दबाव वाले इस पहाड़ी पर्यटन केंद्र में यह व्यवस्था दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

अल्मोड़ा में उन्होंने पुलिस बल की पेशेवर क्षमता और अनुशासन पर भी जोर दिया है। प्रशिक्षण, ड्रिल और शारीरिक दक्षता के साथ थाना स्तर की कार्यप्रणाली और लंबित मामलों की समीक्षा उनकी प्राथमिकताओं में रही है। महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित कार्रवाई तथा नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर भी जोर दिया गया है।

उनकी सेवाओं को भी सम्मान मिला है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर उन्हें पुलिस महानिदेशक की प्रशंसा डिस्क, सिल्वर प्रदान की गई। वर्ष 2024 में पंजाब पुलिस के डीजीपी की ओर से भी उनके सहयोग और कार्य के लिए उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुई।



महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई के मूल निवासी चंद्रशेखर घोड़ेके की शैक्षणिक यात्रा भी उनके पेशेवर व्यक्तित्व को समझने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन में बी.टेक. किया। पुलिस सेवा में आने से पहले वे इंफोसिस में सिस्टम इंजीनियर, और भारतीय रिजर्व बैंक में मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं। तकनीकी और वित्तीय संस्थानों में काम का यह अनुभव बाद में उनकी





साहस, संवेदनशीलता और प्रभावी पुलिसिंग की मिसाल

अपर्णा आर. कौशिक

मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत अपर्णा आर. कौशिक का जीवन संघर्ष और आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी भी है। उन्होंने अपने करियर में जिला पुलिसिंग से लेकर महानगरीय पुलिस व्यवस्था तक का व्यापक अनुभव हासिल किया है। अपराध नियंत्रण, गंभीर मामलों की जांच, खुफिया आधारित कार्रवाई, कानून-व्यवस्था और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रिय भूमिका उनके पुलिस नेतृत्व की प्रमुख विशेषता रही है।



पुलिस सेवा में उनके योगदान को डीजी की कमेंडेशन डिस्क—सिल्वर 2022 और गोल्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनके कार्य और पेशेवर योगदान की मान्यता हैं। अपर्णा आर. कौशिक का करियर जिला पुलिसिंग, महानगरीय पुलिसिंग, अपराध अनुसंधान, तकनीकी जांच और खुफिया आधारित अभियानों के संतुलित अनुभव को दर्शाता है। उनकी कार्यशैली यह संदेश देती है कि प्रभावी पुलिसिंग में साहस और अनुशासन के साथ संवेदनशीलता, तकनीक, संवाद और जवाबदेही भी उतने ही आवश्यक हैं।

उच्च शिक्षा के लिए जयपुर का रुख किया और एनआईटी इलाहाबाद से जैव प्रौद्योगिकी में बीटेक की डिग्री प्राप्त की।

सिविल सेवा में आने से पहले वे गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के रूप में कार्यरत थीं। हालांकि उस समय उनका वार्षिक पैकेज लगभग 18 लाख रुपये था, लेकिन एक सफल कॉरपोरेट करियर के बावजूद उन्होंने सार्वजनिक सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। यूपीएससी की कठिन परीक्षा क्रैक की और भारतीय पुलिस सेवा में अपनी जगह बनाई।

उनके निजी जीवन में भी सामाजिक सरोकार की झलक दिखाई देती है। वर्ष 2018 में उन्होंने सादगीपूर्ण तरीके से विवाह किया। बताया जाता है कि विवाह समारोह में अनावश्यक खर्च से बचाकर उस धन को महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए योगदान करने का निर्णय लिया गया। यह पहल उनके व्यक्तित्व में सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के महत्व को दर्शाती है।

आईपीएस अधिकारी के रूप में अपर्णा आर. कौशिक की शुरुआती तैनातियों ने उन्हें जमीनी पुलिसिंग का व्यापक अनुभव दिया। वो गाजियाबाद में बतौर सीओ और एसपी तैनात रहीं। उन्होंने शाहजहांपुर में एसपी (रूरल) के रूप में कार्य किया। अपने पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने शाहजहांपुर जनपद में एक रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाते हुए अपने ही विभाग के आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कराई और उसे सजा दिलाई। इसके बाद वे औरैया और कासगंज की पुलिस अधीक्षक बनीं। जिला पुलिस की कमान संभालते हुए उन्हें कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन, जन शिकायतों के समाधान और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय का अनुभव मिला।

कासगंज में उनके कार्यकाल की एक विशेषता पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करने पर जोर रही। पुलिसिंग को केवल अपराध के बाद कार्रवाई तक सीमित रखने के बजाय समुदाय के साथ बेहतर संपर्क, समय पर शिकायतों का समाधान और निवारक पुलिसिंग को प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया गया। इससे पुलिस की पहुंच और जवाबदेही को मजबूत करने का प्रयास दिखाई देता है।

इसके बाद अपर्णा ने लखनऊ कमिश्नरेट में डीसीपी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। राजधानी जैसे बड़े महानगरीय क्षेत्र में पुलिसिंग की अपनी जटिलताएं हैं। गंभीर अपराधों की जांच, संगठित एवं आर्थिक अपराध पर कार्रवाई, कानून-व्यवस्था, कई थाना क्षेत्रों के बीच समन्वय और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया यहां विशेष महत्व रखते हैं। लखनऊ में उनके कार्यकाल ने उन्हें शहरी पुलिसिंग का महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान किया।

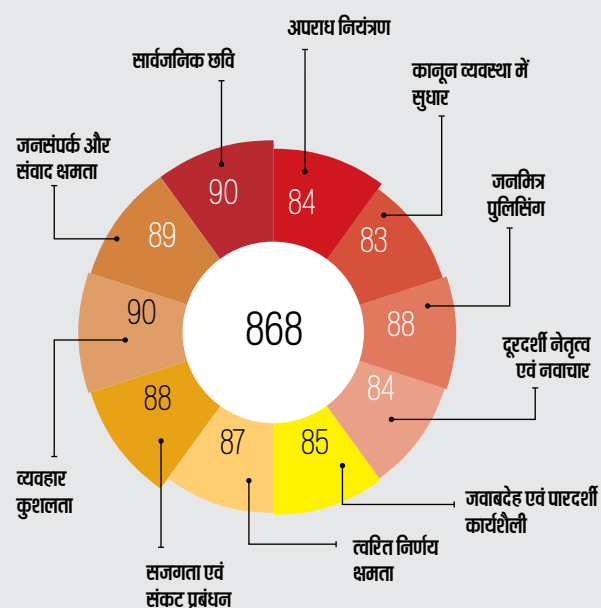
अपर्णा की पेशेवर क्षमता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण अमेठी में उनके कार्यकाल के दौरान सामने आया। पुलिस अधीक्षक के रूप में उन्होंने कई गंभीर आपराधिक मामलों की जांच और कार्रवाई की निगरानी की। एक चर्चित हत्या के मामले में पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हुए घटनाक्रम को जोड़ा। चार आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए। मामले के सफल खुलासे के लिए पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार भी दिया गया।

अमेठी में उनके कार्यकाल के दौरान अवैध और नकली कृषि उत्पादों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। एक अभियान में ब्रांडेड पैकेजिंग में घटिया उर्वरक और कीटनाशक दोबारा पैक करने वाली अवैध इकाई का पर्दाफाश किया गया। बड़ी संख्या में पैकेट और नकली रैपर बरामद हुए तथा संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया।

4 फरवरी 2026 को अपर्णा कौशिक ने मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक का पद संभाला। यहां उनकी पुलिसिंग में संगठित और अंतरराज्यीय आपराधिक नेटवर्क पर विशेष ध्यान दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण अभियान में मिर्जापुर पुलिस ने एसओजी, सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस के समन्वय से एक कथित अंतरराज्यीय लूट गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में कथित रूप से लूटे गए सोने के आभूषण, हथियार, कारतूस और नकदी बरामद हुई।



उत्तर प्रदेश के रामपुर में 7 मार्च 1991 को जन्मी अपर्णा के पिता रणवीर प्रताप गौतम का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था। उनकी मां प्रीति गौतम ने अकेले उनका पालन-पोषण किया और उनकी शिक्षा तथा व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहीं अपर्णा ने दयावती मोदी अकादमी से शिक्षा प्राप्त की और वर्ष 2006 की कक्षा 10 की परीक्षा में राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद उन्होंने



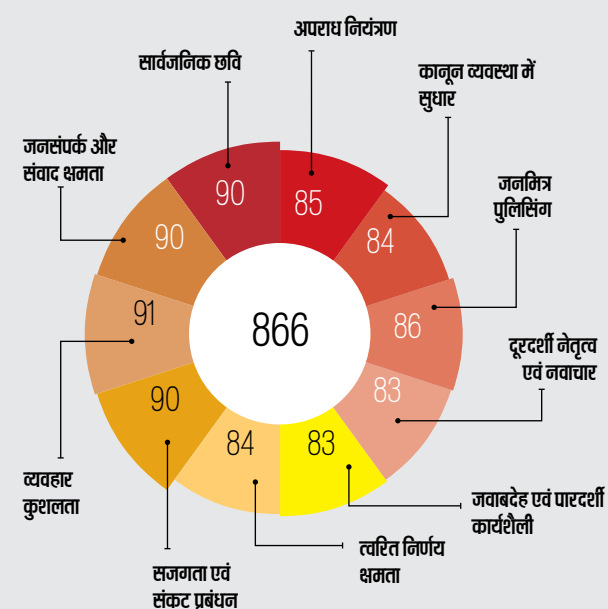


अनुशासन, जवाबदेही और जनोन्मुख पुलिसिंग की पहचान

श्रद्धा तिवारी

भोपाल, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी श्रद्धा तिवारी ने अपने लंबे पुलिस करियर में फील्ड पुलिसिंग से लेकर महानगरीय पुलिस प्रशासन तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वर्ष 2012 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी श्रद्धा तिवारी ने अपनी पेशेवर दक्षता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के बल पर विशिष्ट पहचान बनाई है। अगस्त 2026 में उन्हें उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया गया।



श्रद्धा तिवारी मूल रूप से मध्य प्रदेश पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में आई और 5 फरवरी 2020 को उन्हें आईपीएस कैडर में शामिल किया गया। पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ फील्ड पुलिसिंग में भी प्रभावी भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और नागरिकों के साथ पुलिस के संवाद को प्राथमिकता मिली।

लगभग डेढ़ दशक के पुलिस अनुभव में श्रद्धा तिवारी ने फील्ड पुलिसिंग, प्रशासनिक प्रबंधन, चुनावी कानून-व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और जनजागरूकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित की है। सिंहस्थ ज्योति मेडल, राष्ट्रपति पुलिस पदक और कर्मवीर योद्धा पदक उनकी सेवा यात्रा के महत्वपूर्ण सम्मान हैं। अगस्त 2026 में डीआईजी पद पर पदोन्नति उनके करियर का नया महत्वपूर्ण पड़ाव है। अनुशासन, जवाबदेही, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण और जनोन्मुख पुलिसिंग उनकी कार्यशैली की प्रमुख पहचान हैं।



उनकी सेवा उपलब्धियों को विभिन्न स्तरों पर सम्मान भी मिला है। वर्ष 2016 में सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रबंध के रूप में कार्य करते हुए सिंहस्थ 2016 के आयोजन में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 'सिंहस्थ ज्योति मेडल 2016' प्रदान किया गया। विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान पुलिस व्यवस्था के लिए आवश्यक संसाधनों की समय पर उपलब्धता एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी और इसमें उनके योगदान को महत्वपूर्ण माना गया।

वर्ष 2019 में पुलिस विभाग में दी गई उनकी सराहनीय सेवाओं को मान्यता देते हुए भारत सरकार की ओर से महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उन्हें 'सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक' प्रदान किया गया। वहीं, वर्ष 2020-21 में वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें 'कर्मवीर योद्धा पदक' से सम्मानित किया। महामारी के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ नागरिकों की सहायता और प्रशासनिक समन्वय में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

श्रद्धा तिवारी के करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शुरू हुआ। वर्ष 2022 में राजधानी भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर उन्होंने प्रथम महिला डीसीपी के रूप में लगभग तीन वर्षों तक जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, चुनाव प्रबंधन और वीआईपी सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन किया।

उनके कार्यकाल में पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए गए। राजधानी भोपाल में आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा वीआईपी और वीवीआईपी ड्यूटी में भी उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। इन जिम्मेदारियों में पुलिस बल का बेहतर समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण रही।

डीसीपी जोन-2 के रूप में उन्होंने भोपाल के महत्वपूर्ण थाना क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था की निगरानी की। थाना स्तर पर अपराध नियंत्रण, अधिकारियों की तैनाती और पुलिस संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया गया। मिसरोद थाने के आधुनिकीकरण और उसे आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन दिलाने की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। इसका उद्देश्य थाने की कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को अधिक व्यवस्थित बनाना था।

सितंबर 2024 में पुलिस प्रशासनिक फेरबदल के दौरान उन्हें डीसीपी जोन-2 से डीसीपी मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई। इस भूमिका में पुलिस बल की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था, मानव संसाधन, अनुशासन, पदस्थापन और विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय जैसी जिम्मेदारियां उनके कार्यक्षेत्र में रहीं। उनकी भूमिका ने फील्ड पुलिसिंग और प्रशासनिक प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में योगदान दिया।

आधुनिक पुलिसिंग के क्षेत्र में भी श्रद्धा तिवारी की भूमिका उल्लेखनीय रही। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए 'साइबर फ्रॉड पे चर्चा' जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी रोजगार योजनाओं, ऑनलाइन ऋण और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।

नशे के खिलाफ जागरूकता अभियानों में विद्यार्थियों, नागरिक संगठनों और आम लोगों की भागीदारी पर भी जोर दिया गया। इस तरह पुलिसिंग को केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित रखने के बजाय सामाजिक भागीदारी और जनजागरूकता से जोड़ने का प्रयास किया गया।

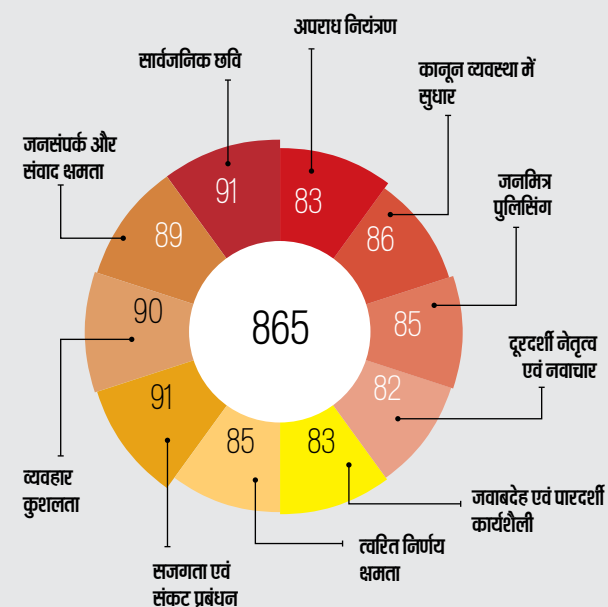


सीमा सुरक्षा से जनविश्वास तक, एक आईपीएस अधिकारी की चुनौतीपूर्ण यात्रा

मनिंदर सिंह

रूपनगर (रोपड़), पंजाब

पंजाब के रूपनगर, जिसे आम बोलचाल में रोपड़ भी कहा जाता है, की पुलिस कमान संभालने वाले मनिंदर सिंह, IPS की कहानी एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कहानी है, जिसकी पेशेवर यात्रा में अपराध नियंत्रण, सीमा सुरक्षा, नशा-तस्करी के खिलाफ अभियान, संकट प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार—सभी के अलग-अलग अध्याय दिखाई देते हैं। वर्ष 2019 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी मनिंदर सिंह ने जनवरी 2026 में एसएसपी रूपनगर का पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने साफ-सुथरा, भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी पुलिस प्रशासन देने तथा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को अपनी प्राथमिकताओं में रखा।



मनिंदर सिंह की पेशेवर नींव मजबूत प्रशिक्षण और टीम भावना पर आधारित रही है। उनके करियर सारांश के अनुसार राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी और समर्पित टीम प्लेयर के रूप में भी रेखांकित किया। यही टीम भावना आगे चलकर उनके नेतृत्व के तरीके का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी।

फील्ड पुलिसिंग में उनकी कार्यशैली का प्रारंभिक परिचय उन अभियानों से मिलता है, जिनमें तेज अपराध-पहचान और प्रभावी कार्रवाई प्रमुख रही। मनसा में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में उन्होंने मूसा गांव के दोहरे हत्याकांड को 72 घंटे के भीतर ट्रेस किया। अमृतसर दक्षिण में उन्होंने एक अभियान का नेतृत्व करते हुए हैंड ग्रेनेड बरामद किया, तीन ब्लाइंड मर्डर मामलों को सुलझाया, तीन नाबालिग अपहृत लड़कियों को छुड़ाया और 4.746 किलोग्राम हेरोइन, एक ड्रोन तथा 67.59 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की।



तरनतारन में एसपी मुख्यालय के रूप में उनका कार्यकाल प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से भी उल्लेखनीय रहा। उनके करियर सारांश के अनुसार उन्होंने 100 से अधिक विरोध-प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला और पुलिस बल के 50 प्रतिशत हिस्से को फील्ड स्टेशनों पर पुनर्नियोजित किया। इसका परिणाम जिला सांझ रैंकिंग में भी दिखाई दिया, जहां जिला नीचे के पांच जिलों से ऊपर के पांच जिलों में पहुंचा। इसी दौरान उन्होंने 25 लाख रुपये के हवाला-ड्रग नेटवर्क को भी ध्वस्त किया।

राज्यपाल के एडीसी के रूप में भी मनिंदर सिंह को प्रोटोकॉल और उच्चस्तरीय प्रशासन का अनुभव मिला। करियर सारांश के अनुसार उन्होंने 42 आधिकारिक दौरों और राजभवन में आयोजित महत्वपूर्ण शपथ ग्रहण समारोहों के प्रोटोकॉल का प्रबंधन किया।

उनके करियर का एक बड़ा अध्याय अमृतसर ग्रामीण के SSP के रूप में सामने आया, जिसमें वर्दी के पीछे एक मानवीय दिल की धड़कन दिखी। 2025 में उन्होंने सीमावर्ती गांवों में आई भूषण बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव अभियानों का नेतृत्व किया। उनके करियर सारांश के अनुसार इस दौरान हजारों ग्रामीणों को सीमा क्षेत्र के गांवों से सुरक्षित निकाला गया। दूसरी ओर, उन्होंने अपनी ऐक्टिव पुलिसिंग भी जारी रखी। उनके नेतृत्व में पुलिस ने नार्को-टेरर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए 1,354 गिरफ्तारियां, 237 किलोग्राम हेरोइन, 1.9 करोड़ रुपये की ड्रग मनी, 297 पिस्तौल और 15 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। साथ ही 800 से अधिक ग्राम रक्षा समितियों को सक्रिय कर सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत रूप देने का प्रयास किया गया। अवैध रूप से अर्जित करीब 10 करोड़ रुपये की संपत्तियों को फ्रीज करना भी इसी रणनीति का हिस्सा था।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी उनकी टीम सक्रिय रही। मई 2025 में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने दो लोगों को कथित रूप से पाकिस्तानी खुफिया तंत्र को सैन्य प्रतिष्ठानों और सैनिकों की आवाजाही से संबंधित संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच में सैन्य प्रतिष्ठानों और एयरबेस की तस्वीरें तथा अन्य संवेदनशील जानकारी साझा किए जाने की बात सामने आई।

हालांकि मनिंदर सिंह के करियर में एक कठिन दौर भी आया जब नवंबर 2025 में पंजाब सरकार ने उन्हें अमृतसर ग्रामीण SSP के पद से निलंबित किया। निलंबन का आधार गैंगस्टर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने और कथित प्रशासनिक चूक से जुड़ा था। यह उनके करियर का महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण अध्याय रहा, लेकिन कहते हैं न - सांच को आंच नहीं।

लगभग दो महीने बाद ही दिसंबर-जनवरी के दौरान सरकार ने उनका निलंबन वापस ले लिया, और जनवरी 2026 में उन्हें एसएसपी रूपनगर नियुक्त किया गया। रूपनगर पहुंचने के बाद मनिंदर सिंह ने अपने संदेश में पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त पुलिस प्रशासन, मजबूत कानून-व्यवस्था तथा असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकल्प दोहराया। यह प्राथमिकताएं उनके अब तक के करियर की व्यापक तस्वीर से भी मेल खाती हैं—जहां एक ओर अपराध और संगठित नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ जैसी आपदा में नागरिकों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास भी दिखाई देता है।

आज रूपनगर में उनकी नई जिम्मेदारी उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहां उनकी चुनौती केवल अपराध कम करना नहीं, बल्कि नागरिकों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत करना भी है। उनका अब तक का अनुभव उन्हें अपराध नियंत्रण, संकट प्रबंधन और सीमा सुरक्षा की गहरी समझ देता है।

मनिंदर सिंह की कहानी अंततः एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कहानी है, जिसके करियर में उपलब्धियों के साथ कठिन परीक्षाएं भी आई हैं। यही कारण है कि रूपनगर में उनका कार्यकाल केवल एक नई पोस्टिंग नहीं, बल्कि अनुभव, जवाबदेही और नेतृत्व की अगली परीक्षा के रूप में भी देखा जाएगा।

दृढ़ नेतृत्व और संवेदनशील पुलिसिंग की मिसाल

डॉ. अमृता दुहन

उदयपुर, राजस्थान

भारतीय पुलिस सेवा में डॉ. अमृता दुहन की पहचान एक ऐसी अधिकारी के रूप में बनी है, जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र से पुलिस सेवा तक का असाधारण सफर तय किया और राजस्थान में अपनी सख्त, सक्रिय तथा जनकेंद्रित पुलिसिंग के लिए अलग पहचान बनाई। वर्ष 2016 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी डॉ. अमृता दुहन वर्तमान में उदयपुर की पुलिस अधीक्षक हैं। मार्च 2026 में उनकी नियुक्ति के साथ वे इस जिले की पहली महिला एसपी बनीं।



उदयपुर में भी उनकी कार्यशैली का केंद्र सक्रिय और जनसरोकार वाली पुलिसिंग दिखाई दे रहा है। जुलाई 2026 में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के दौरान उन्होंने स्वयं बस्तियों में जाकर महिलाओं से संवाद किया और बुजुर्गों के घर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं। इस तरह की पहल पुलिस को समुदाय के करीब लाने और महिलाओं तथा कमजोर वर्गों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। डॉ. अमृता दुहन की यात्रा कई स्तरों पर प्रेरक है। सख्त कार्रवाई के साथ संवाद और संवेदनशीलता का संतुलन ही डॉ. अमृता दुहन की कार्यशैली को विशिष्ट बनाता है।

किया। बेटे के जन्म के बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी शुरू की और 32 वर्ष की उम्र में वर्ष 2016 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुईं। उनका यह सफर उन लोगों के लिए विशेष प्रेरणा है, जो जीवन के किसी भी चरण में करियर की नई दिशा चुनना चाहते हैं।

सेवा में आने के बाद डॉ. दुहन ने राजस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिसिंग का अनुभव हासिल किया। वे कोटा सिटी में सहायक पुलिस अधीक्षक रहीं। इसके बाद उन्होंने राजस्थान स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में कमांडेंट तथा जयपुर कमिश्नरेट में यातायात, मुख्यालय और अपराध शाखा से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालीं। वर्ष 2021 में वे प्रतापगढ़ की पुलिस अधीक्षक रही जहाँ मादक पदार्थों की तस्करी व महिला अपराधों के विरुद्ध काम किया।

जोधपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ईस्ट के रूप में भी उन्होंने काम किया। डीसीपी ईस्ट के पद पर रहते हुए दो मर्डर में फरार आरोपी व एक लाख इनामी अपराधी की गिरफ्तारी की गई, इसके साथ साइबर क्राइम में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विदेशों में पैसा भेजने वाले बड़े सिंडिकेट का राजफाश किया व उनसे करोड़ों रुपए की बरामदगी की गई।

उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय कोटा शहर की पुलिस अधीक्षक के रूप में रहा। फरवरी 2024 में उन्होंने कोटा की कमान संभाली और वे शहर की पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनीं। कोटा जैसे शिक्षा केंद्र में उनकी प्राथमिकताओं में अपराध नियंत्रण के साथ बड़ी संख्या में रहने वाले कोचिंग विद्यार्थियों की सुरक्षा भी शामिल रही। उन्होंने हॉस्टल, पीजी और विद्यार्थियों के आवासीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा पुलिस को विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।

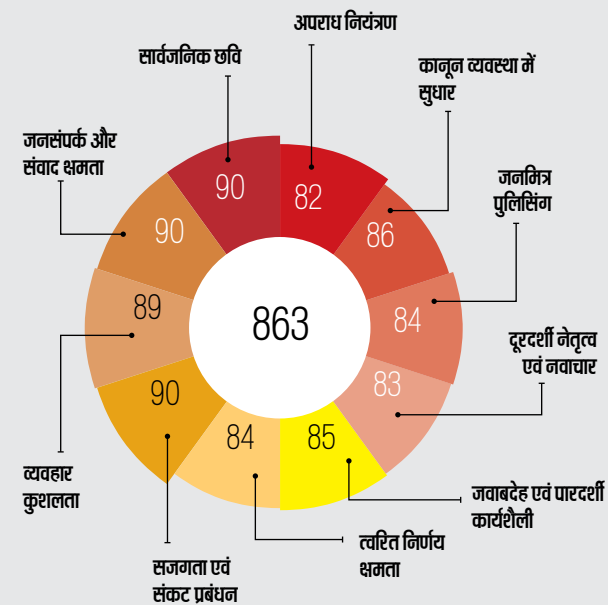
कोटा में छात्र सुरक्षा को लेकर उनका दृष्टिकोण केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं था। उन्होंने विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। महिला विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए 'ऑपरेशन मेरा मान' जैसी पहल में भी उनकी भूमिका रही। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को सक्रिय किया गया, जिसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी की व्यवस्था की गई। अपराध की जांच में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। कोटा में अपहरण के एक नकली मामले का रहस्योद्घाटन खासा चर्चित रहा था, जिसमें उनकी तार्किक सूझ-बूझ की खूब प्रशंसा हुई थी।

इसके बाद श्रीगंगानगर की पुलिस अधीक्षक के रूप में उनका कार्यकाल नशे के खिलाफ अभियान के कारण विशेष रूप से चर्चा में रहा। जुलाई 2025 में पदभार संभालने के बाद उन्होंने अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए गैंगस्टर्स तथा नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। उनके नेतृत्व में 'नशा मुक्त श्रीगंगानगर' अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

श्रीगंगानगर में पुलिस ने नशे के अवैध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखा। नवंबर 2025 में सरकारी जमीन पर कथित रूप से बनाए गए ड्रग हब के खिलाफ कार्रवाई की गई और अवैध अतिक्रमण हटाया गया। मार्च 2026 में उन्हें उदयपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। यह नियुक्ति ऐतिहासिक रही, क्योंकि वे उदयपुर जिले की पहली महिला एसपी बनीं। उदयपुर एक साथ महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र, तेजी से विकसित होता शहरी क्षेत्र और आदिवासी बहुल इलाकों वाला जिला है। यहां कानून-व्यवस्था के साथ महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, तस्करी, पर्यटन सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच जैसी चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं।



हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली डॉ. अमृता दुहन ने चिकित्सा को अपना शुरुआती पेशा बनाया। उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई वर्ष 2007 में पूरी की और इसके बाद वर्ष 2011 में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा हासिल की। वे चिकित्सक के रूप में कार्य करने के साथ मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहीं। विवाह और मातृत्व के बाद उन्होंने अपने करियर की दिशा बदलने का फैसला





मा० पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सार्वजनिक सूचना



सर्वसाधारण/आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा आवासीय / गैर आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की जा रही हो तो कृपया भूमि क्रय करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी निम्न सूचनाओं/जानकारी का संज्ञान अवश्य लिया जाये :-

- ❖ प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत भूमि क्रय करने से पूर्व कृपया। एम.डी.डी.ए. कार्यालय से भूमि के भू-उपयोग की जानकारी अवश्य रूप से ली जाये। इस हेतु केता को कय की जाने वाली भूमि/भूखण्ड का वास्तुविद /ड्राफ्टमैन द्वारा बनाया गया की-प्लान तथा भू-खण्ड के गूगल को-ऑर्डिनेट्स/भू-खण्ड की गूगल लोकेशन प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ❖ अवैध प्लॉटिंगों पर कय किये गये भू-खण्ड पर एम.डी.डी.ए. द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाता है।
- ❖ मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश तथा भवन उपविधि के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज नदी के क्षेत्र से 30 मी० की दूरी के उपरान्त ही भूमि कय की जाये।
- ❖ प्राधिकरण से बिना स्वीकृति/अनुमति से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भू-खण्ड कदापि कय न किया जाये। यदि सूचित होने के बावजूद भी भू-खण्ड कय किया जाता है तथा एम.डी.डी.ए. द्वारा भवन उपविधि के अनुसार प्रश्नगत अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सील अथवा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केता की रहेगी। एम.डी.डी.ए. द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत की गयी अवैध प्लॉटिंगों की भूमि के सम्बन्ध में सूचना/जानकारी एम.डी.डी.ए. की ऑफिशियल वेबसाइट एमडीडीएओनलाइन-इन पर उपलब्ध है।
- ❖ जनहित में यह भी सूचित किया जाता है कि भूमि/भू-खण्ड कय करने से पूर्व कय की जाने वाली भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण/सजरे के अनुसार भू-खण्ड खसरा न० की स्थिति स्पष्ट करने/कय की जाने वाली भूमि में किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद होने अथवा न 1 न होने/कय की जाने वाली भूमि के रकबे में सरकारी भूमि सम्मिलित होने के सम्बन्ध में कृपया राजस्व विभाग से गली-माति परीक्षण कराया जाये।
- ❖ प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी उक्त सूचनाओं / जानकारी के कम में कय की गयी भूमि/भू-खण्ड का एम.डी.डी.ए. कार्यालय से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही मोके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
- ❖ क्रय की जाने वाली भूमि/भू-खण्ड के सम्बन्ध में भूमि विक्रेता से भूमि/भू-खण्ड का प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट/तलपट मानचित्र की जानकारी प्राप्त की जाये कि जो भू-खण्ड केता द्वारा बिक्रेता से कय किया जा रहा है क्या वह भू-खण्ड स्वीकृत ले-आउट मानचित्र का भू-खण्ड का माग है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में भूमि विक्रेता से स्वीकृत ले-आउट मानचित्र/मानचित्र संख्या की जानकारी प्राप्त करते हुए उसका सत्यापन एम.डी.डी.ए. कार्यालय से अवश्य रूप से किया जाये।

उक्त सूचना/जानकारी जनहित में जारी की जाती है।

“आज्ञा से
उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण”
देहरादून।

फेम इंडिया

सोच बदलें, समाज बदलेगा

राजीव मिश्रा
लखनऊ का जनसेवक



समाज में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी पहचान केवल उनके पद या राजनीतिक दायित्वों से नहीं, बल्कि उनके कर्म, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण से बनती है। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ऐसे ही व्यक्तित्वों में शामिल हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, वे उन्हें केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि समाज के सच्चे सेवक के रूप में स्थापित करते हैं।



राजीव मिश्रा के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहज मानवीय संवेदना है। जरूरतमंद व्यक्ति की परेशानी को केवल सुन लेना उनके लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि वे यथासंभव उसके समाधान का प्रयास करते हैं। उनके लिए सेवा किसी प्रदर्शन या प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि इंसान होने की जिम्मेदारी है।

सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकार का सशक्त नाम

राजीव मिश्रा

राजीव मिश्रा का विश्वास है कि राजनीति का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सम्मान पहुंचाना है। यही सोच उनके सार्वजनिक जीवन और सामाजिक कार्यों में स्पष्ट दिखाई देती है। वे सदैव मानते रहे हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पूँजी जनता का विश्वास होता है और यह विश्वास केवल निरंतर सेवा से अर्जित किया जा सकता है।

पत्नी के असामयिक निधन के दुख से उबरते हुए उन्होंने उनके नाम पर ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की तथा खुद को जनसेवा में समर्पित कर दिया। राजीव मिश्रा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं, लेकिन उनके आवास पर अपनी परेशानी को लेकर उमड़ने वाली भीड़ उन्हें किसी भी जनप्रतिनिधि से ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। वह समस्याओं को लेकर आने वाले पीड़ित की ना केवल पूरी बात सुनते हैं, बल्कि उसका त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करते हैं। चारों तरफ से निराश व्यक्ति की आखिरी उम्मीद राजीव मिश्रा ही बनते हैं।

राजीव मिश्रा की ईंसानियत उनके छोटे-छोटे व्यवहारों में भी दिखाई देती है। वे सामने वाले व्यक्ति की स्थिति, सम्मान और भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। यही संवेदनशीलता उन्हें केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि लोगों के बीच भरोसे का नाम बनाती है।

ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के अनेक प्रयासों को गति दी है। उनकी सोच केवल सहायता तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी रही है। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता उन्हें एक अलग पहचान देती है। कोविड काल के दौरान उन्होंने विकट परिस्थितियों



में जिस तरह का सेवा भाव दिखाया तथा दवा से लेकर चिकित्सकीय सुविधायें गरीब एवं मजबूर लोगों को उपलब्ध करायी वह अनुकरणीय है।

शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हजारों बच्चों की विद्यालयी फीस माफ करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे अनेक बच्चों की पढ़ाई बीच में रुकने से बच जाती है। यह केवल किसी एक वर्ष का काम नहीं है, बल्कि वह दशकों से निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षित करने की राह में आने वाले अवरोधों को हटाते आ रहे हैं। जिन परिवारों के लिए बच्चों की फीस भरना कठिन था, उनके लिए यह प्रयास किसी वरदान से कम नहीं रहा। राजीव मिश्रा का मानना है कि शिक्षा सबसे बड़ा सामाजिक निवेश है और किसी भी बच्चे की पढ़ाई आर्थिक अभाव के कारण नहीं रुकनी चाहिए। यही सोच उनके इस अभियान की प्रेरणा है। वह बच्चों को भारत का भविष्य मानते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उनका योगदान प्रेरणादायी है। उन्होंने विभिन्न अभियानों के माध्यम से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण को जनआंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया है। उनके नेतृत्व और प्रेरणा से बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए तथा लोगों को केवल पौधे लगाने ही नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल के लिए भी प्रेरित किया गया। उनका विश्वास है कि एक वृक्ष केवल पर्यावरण ही नहीं बचाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन, स्वच्छ हवा और बेहतर भविष्य की नींव भी तैयार करता है।

भाजपा के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में राजीव मिश्रा संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के सम्मान और जनसंपर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। वे कार्यकर्ताओं को संगठन की वास्तविक शक्ति मानते हैं और उनसे निरंतर संवाद बनाए रखते हैं। उनकी सहजता, सादगी और सभी को साथ लेकर चलने की कार्यशैली उन्हें एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में स्थापित करती है। वह कार्यकर्ताओं के लिये हर परेशानी में साथ खड़े मिलते हैं।

उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समाज के हर वर्ग के लोगों से समान आत्मीयता के साथ मिलते हैं। उनके लिए सेवा किसी जाति, वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता के प्रति दायित्व है। यही

कारण है कि सामाजिक कार्यक्रमों, जनसमस्याओं और जनहित के मुद्दों पर उनकी सक्रियता निरंतर दिखाई देती है।

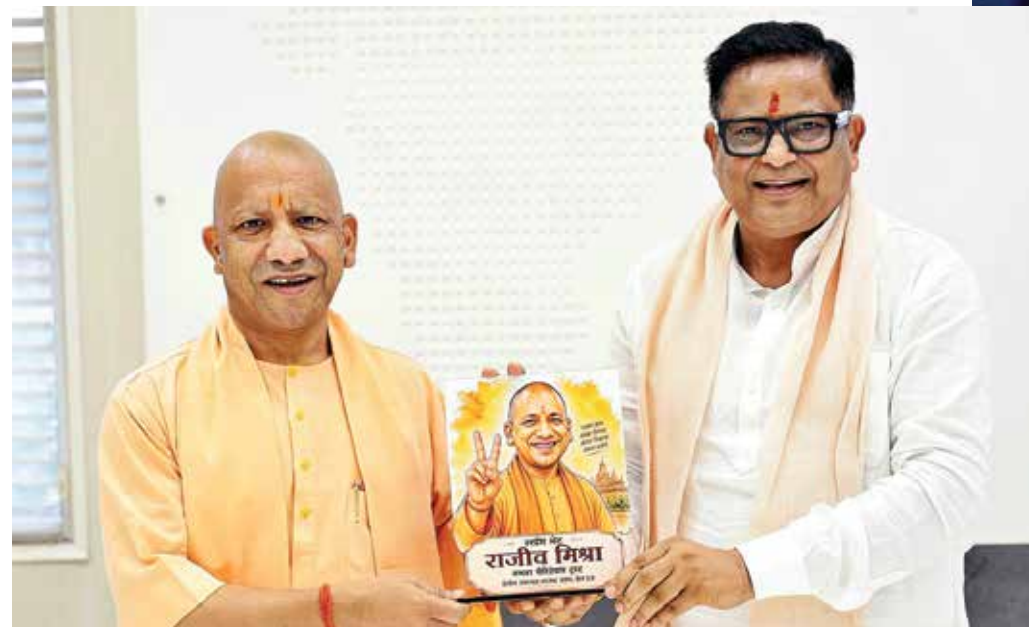
राजीव मिश्रा युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। वे उन्हें शिक्षा, कौशल, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रहित के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देते हैं। उनका विश्वास है कि यदि युवा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें तो देश का भविष्य और अधिक उज्ज्वल हो सकता है।

भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्र प्रथम की भावना उनके सार्वजनिक जीवन की आधारशिला है। वे विकास और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच संतुलन को आवश्यक मानते हैं तथा समाज में सहयोग, संवाद और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं।

आज जब समाज को संवेदनशील नेतृत्व और सेवा-भाव से जुड़े व्यक्तित्वों की आवश्यकता है, तब राजीव मिश्रा का कार्य प्रेरणा देता है। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों बच्चों की फीस माफ कराने की पहल, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक वृक्षारोपण अभियान तथा सामाजिक सेवा के विविध कार्य उनके व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाते हैं।

निस्संदेह, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं भाजपा के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में राजीव मिश्रा ने जनसेवा को अपने सार्वजनिक जीवन का मूल उद्देश्य बनाया है। समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के प्रति उनका समर्पण उन्हें ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है, जिनसे आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा ले सकती हैं। सच कहा जाए तो समाज को बदलने के लिए केवल बड़े संकल्प नहीं, बल्कि दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने वाला हृदय चाहिए। राजीव मिश्रा की यही संवेदनशीलता उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।

विनोद विप्लव





अनुशासन, संवेदनशीलता और उत्कृष्ट नेतृत्व की मिसाल

बलबीर सिंह

हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश पुलिस में वर्ष 2007 में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले बलबीर सिंह ने लगभग दो दशकों की सेवा में पुलिसिंग के विभिन्न आयामों को करीब से समझा और अपनी कार्यशैली से अलग पहचान बनाई है। शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जैसे महत्वपूर्ण जिलों में विभिन्न चुनौतीपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक प्रबंधन और सतर्कता से जुड़े क्षेत्रों में अपनी दक्षता का परिचय दिया है। वर्तमान में वे पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर के पद पर कार्यरत हैं।



वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्ति के बाद उनका कार्यक्षेत्र लगातार व्यापक होता गया। शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में अलग-अलग जिम्मेदारियों ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के विविध सामाजिक और भौगोलिक परिवेश को समझने का अवसर दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में पुलिसिंग अपने आप में चुनौतीपूर्ण होती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच, सीमित संसाधनों और बदलते अपराध के स्वरूप के बीच पुलिस प्रशासन को प्रभावी बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन परिस्थितियों में काम करते हुए बलबीर सिंह ने व्यावहारिक अनुभव अर्जित किया।

अधिकारी ने अपने अनुभव और ज्ञान को प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा।

उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय विशेष जांच और भ्रष्टाचार निरोधक कार्यों से भी जुड़ा रहा है। हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक का दायित्व संभालने से पहले वे धर्मशाला में एसपी, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नॉर्थरेंज के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। इस जिम्मेदारी में उन्हें सतर्कता संबंधी महत्वपूर्ण मामलों और भ्रष्टाचार निरोधक पहलों का नेतृत्व करने का अवसर मिला। ऐसे दायित्वों में निष्पक्षता, कानूनी प्रक्रिया की समझ, गोपनीयता और निर्णय लेने की क्षमता का विशेष महत्व होता है। उनके अनुभव ने पुलिस सेवा के इस महत्वपूर्ण पक्ष में उनकी प्रशासनिक और जांच संबंधी दक्षता को और मजबूत किया।

पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2010 में 'पुलिसवाला पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें पुलिस महानिदेशक की ओर से दो बार डीजीपी डिस्क भी प्राप्त हो चुकी है। ये सम्मान उनके सेवा-काल में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

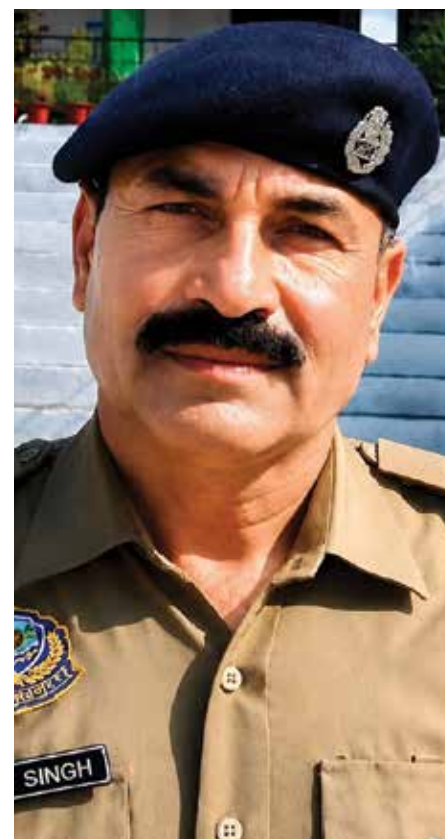
पुलिसिंग के साथ-साथ बलबीर सिंह खेलों में भी गहरी रुचि रखते हैं। वे बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं और हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं में कई बार विजेता रह चुके हैं। खेल के प्रति उनका यह जुड़ाव उनके व्यक्तित्व के एक अलग पक्ष को सामने लाता है। प्रतिस्पर्धा, अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास जैसे गुण पुलिस सेवा और खेल—दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में अपनी सक्रियता से इन गुणों को व्यवहार में उतारा है।

उनकी खेल उपलब्धियों का दायरा राज्य स्तर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पंचकूला में आयोजित राष्ट्रीय वेटरन खेल प्रतियोगिता में मिश्रित युगल बैडमिंटन वर्ग में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया। पुलिस सेवा जैसी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी के बीच खेल के लिए समय निकालना उनके संतुलित व्यक्तित्व और फिटनेस के प्रति जागरूकता को दर्शाता है।

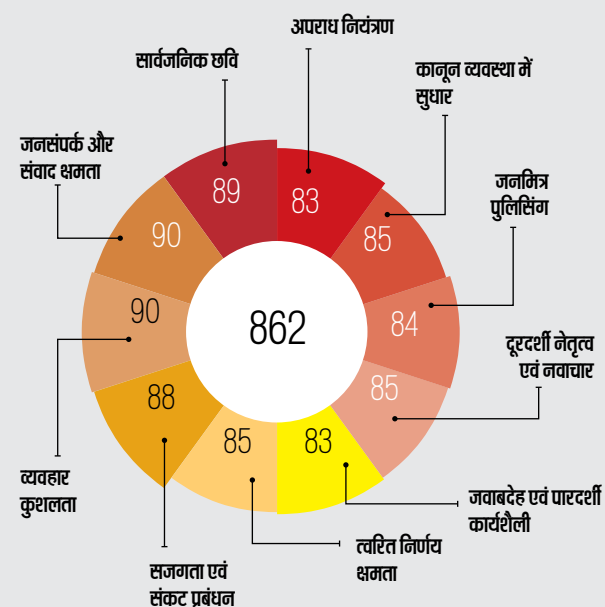
पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर के रूप में बलबीर सिंह के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आधुनिक पुलिसिंग में केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं माना जाता। अपराध की रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया, प्रभावी जांच, तकनीक का उपयोग और आम नागरिकों के साथ बेहतर संवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में व्यापक प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है।

बलबीर सिंह की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि पुलिस सेवा में सफलता केवल वर्दी और पद से नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, अनुशासन, जिम्मेदारी और बहुआयामी व्यक्तित्व से हासिल होती है। भौतिक विज्ञान में उच्च शिक्षा, लंबे समय तक अध्यापन का अनुभव, पुलिस सेवा का व्यापक क्षेत्रीय अनुभव, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक कार्यों में नेतृत्व, विभागीय सम्मान और खेलों में सक्रिय भागीदारी—इन सभी पहलुओं ने उनके व्यक्तित्व को एक व्यापक आयाम दिया है।

एक शिक्षक से पुलिस अधिकारी तक का उनका सफर बताता है कि ज्ञान और अनुभव जब अनुशासन तथा सेवा-भावना से जुड़ते हैं, तो नेतृत्व की क्षमता और मजबूत होती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में लगभग दो दशक की उनकी सेवा यात्रा इसी निरंतर विकास और जिम्मेदारियों के विस्तार की कहानी है। वर्तमान दायित्व में भी उनके अनुभव, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक समझ से हमीरपुर में प्रभावी पुलिस व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद की जाती है।



बिलासपुर जिले के मूल निवासी बलबीर सिंह का व्यक्तित्व केवल एक पुलिस अधिकारी तक सीमित नहीं है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उन्हें विशिष्ट बनाती है। उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और इसी विषय में यूजीसी-नेट भी उत्तीर्ण किया। पुलिस सेवा में आने से पहले उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक विद्यालय में प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दीं। शिक्षा के क्षेत्र से पुलिस सेवा में आए इस

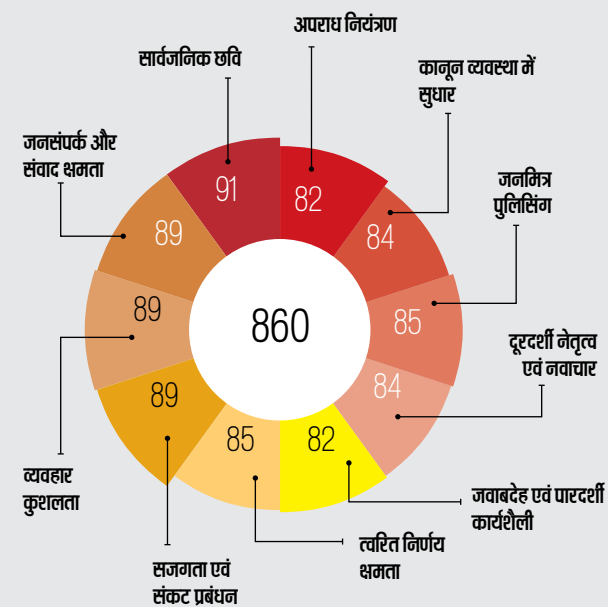


अनुशासन और प्रभावी अपराध नियंत्रण की पुलिसिंग

विजय जे. पटेल

खेड़ा, गुजरात

विजय जे. पटेल का पुलिस करियर लंबे समय तक गुजरात की जिला पुलिस व्यवस्था से जुड़ा रहा है। आईपीएस में आने से पहले उन्होंने राज्य पुलिस सेवा में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं। उनकी पेशेवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण अहमदाबाद के जोन-2 में डीसीपी के तौर पर रहा, जहां उन्होंने महानगर प्रशासन में अपना कौशल दिखाया। सन 2022 में वह पाटन जिले के पुलिस अधीक्षक बनाए गए, और अगले साल साबरकांठा। दोनों ही जिलों में उन्होंने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां संभालीं, और बढ़िया प्रदर्शन किया।



विजय जे. पटेल का करियर इस बात का उदाहरण है कि प्रभावी जिला पुलिसिंग केवल बड़े अभियानों से नहीं बनती। थाना स्तर की सतर्कता, शिकायत पर त्वरित प्रतिक्रिया, गंभीर अपराधों में साक्ष्य आधारित जांच और स्थानीय स्तर पर तनाव को बढ़ने से रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खेड़ा में उनकी वर्तमान भूमिका इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कायम करने की चुनौती है। उनके अब तक के कार्य और पुलिस नेतृत्व का अनुभव उन्हें गुजरात के महत्वपूर्ण जिला पुलिस कप्तानों में एक उल्लेखनीय स्थान देता है।

और शहरी दोनों प्रकार के क्षेत्र आते हैं। नडियाद जैसे प्रमुख शहर के साथ जिले के अनेक ग्रामीण इलाके पुलिस के सामने अलग-अलग तरह की चुनौतियां रखते हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना, गंभीर अपराधों की जांच, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, सामाजिक तनाव और स्थानीय विवादों पर समय रहते कार्रवाई करना जिला पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं।

विजय पटेल के कार्यकाल में गंभीर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई को विशेष महत्व मिला है। अप्रैल 2026 में खेड़ा जिले में एक नाबालिग लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार घटना कई वर्षों से चल रही थी और शिकायत सामने आने के बाद खेड़ा टाउन पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो कानून की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की। इस पूरी कार्रवाई में विजय पटेल ने स्पष्ट किया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता दी।

खेड़ा में कानून-व्यवस्था के सामने केवल गंभीर आपराधिक मामले ही चुनौती नहीं हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे विवाद भी कई बार बड़े तनाव का कारण बन सकते हैं। विजय पटेल इस प्रकार के मामलों का त्वरित निस्तारण करते हैं, और यह उनकी पुलिसिंग के उस पक्ष को सामने लाती है जिसमें कानून-व्यवस्था बिगड़ने का इंतजार करने के बजाय स्थानीय शिकायतों पर समय रहते हस्तक्षेप किया जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सामुदायिक विवादों को बढ़ने से रोकना जिला पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होता है।

विजय पटेल की पेशेवर पहचान में अपराध नियंत्रण के साथ प्रशासनिक निगरानी भी महत्वपूर्ण है। जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में उनकी जिम्मेदारी केवल गंभीर मामलों की निगरानी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली, जांच की गुणवत्ता, कानून-व्यवस्था की स्थिति और नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा भी इसमें शामिल है।

साबरकांठा में एसपी के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें जिला स्तर पर पुलिस नेतृत्व का व्यापक अनुभव दिया। वहीं खेड़ा में उनकी वर्तमान जिम्मेदारी उन्हें अपराध नियंत्रण के साथ सामाजिक संवेदनशीलता और नागरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर काम करने का अवसर देती है। उनके कार्यकाल में सामने आए मामलों से यह भी स्पष्ट होता है कि गंभीर अपराधों में त्वरित प्राथमिकी, आरोपियों की गिरफ्तारी, तकनीकी साक्ष्य और जांच के वैज्ञानिक तरीकों पर जोर दिया जा रहा है।

विजय जे. पटेल की पुलिस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस तक पहुंचना भी है। यह यात्रा लंबे पुलिस अनुभव, संगठनात्मक समझ और जिम्मेदारियों के क्रमिक विस्तार को दर्शाती है। जिला पुलिस की विभिन्न भूमिकाओं में काम करने के बाद आईपीएस में पदोन्नति और फिर महत्वपूर्ण जिलों की कमान उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करती है।

आज खेड़ा के एसपी के रूप में उनके सामने अपराध नियंत्रण के साथ-साथ साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, सामाजिक विवादों की रोकथाम और पुलिस-जन संबंधों को मजबूत करने की चुनौती है। उनकी कार्यशैली में गंभीर मामलों पर त्वरित कार्रवाई, जांच की निगरानी और कानून-व्यवस्था को समय रहते नियंत्रित करने का दृष्टिकोण दिखाई देता है।



गुजरात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी विजय जे. पटेल वर्तमान में खेड़ा-नडियाद जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। 2017 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी विजय पटेल राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होकर भारतीय पुलिस सेवा में आए अधिकारियों में शामिल हैं। वर्ष 2025 में गुजरात में हुए बड़े पुलिस प्रशासनिक फेरबदल में विजय जे. पटेल को खेड़ा-नडियाद का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। खेड़ा की पुलिस कमान उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिले में ग्रामीण



संघर्ष, शिक्षा और संवेदनशील
पुलिसिंग की मिसाल

पापिया सुल्ताना

पश्चिम मेदिनीपुर

पश्चिम बंगाल पुलिस में पापिया सुल्ताना का नाम उन महिला पुलिस अधिकारियों में लिया जाता है, जिन्होंने राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा तक का सफर तय करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। वर्तमान में पश्चिम मेदिनीपुर की पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत पापिया सुल्ताना की पहचान कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, सामुदायिक पुलिसिंग और युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने वाली पहलों से भी जुड़ी है। उन्हें पश्चिम बंगाल की पहली मुस्लिम महिला आईपीएस अधिकारी के रूप में भी व्यापक रूप से पहचान मिली है।



पापिया सुल्ताना की यात्रा केवल एक पुलिस अधिकारी के पद तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि शिक्षा, आत्मविश्वास और लगातार सीखने की क्षमता के माध्यम से आगे बढ़ने की कहानी है। उनकी कार्यशैली में कानून का प्रभावी अनुपालन, समुदाय से संवाद, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं को सशक्त बनाने की सोच साथ-साथ दिखाई देती है। यही संतुलन उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस की चर्चित महिला अधिकारियों में एक विशिष्ट स्थान देता है।

डिग्रियां हासिल कीं तथा स्पेनिश और फ्रेंच भाषाओं में डिप्लोमा भी किया। उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन से जुड़े शोध कार्य में भी रुचि दिखाई।

उनकी पुलिस सेवा की शुरुआत पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा से हुई। वर्ष 2008 में उन्होंने राज्य पुलिस सेवा की परीक्षा पास की और उप पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवा शुरू की। आगे चलकर उनकी कार्यक्षमता और अनुभव के आधार पर उन्हें भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति मिली। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी के रूप में उनका चयन पुलिस सेवा में उनके लंबे अनुभव और पेशेवर उपलब्धियों का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा।

शुरुआती सेवा के दौरान पापिया सुल्ताना ने फील्ड पुलिसिंग से लेकर सशस्त्र पुलिस और प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। महिला और बाल सुरक्षा से जुड़ा उनका काम उनके करियर का विशेष पक्ष रहा है। शुरुआती पुलिस कार्यकाल में बड़ी संख्या में लड़कियों को कठिन परिस्थितियों से निकाला और उन्हें सुरक्षा तथा पुनर्वास उपलब्ध कराए।

फरवरी 2024 में संदेशखाली प्रकरण ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा के आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की थी। पापिया सुल्ताना इस प्रक्रिया का हिस्सा थीं और उन्होंने क्षेत्र में जाकर महिलाओं से बातचीत की तथा उनके बयान दर्ज किए। उन्होंने प्रभावित महिलाओं से सीधे संपर्क कर उनके बयान लिए। संदेशखाली में उनकी भूमिका बाद में राजनीतिक बहस का विषय भी बनी।

कुछ रिपोर्टों में उनके द्वारा शिकायतों से संबंधित दस्तावेज और चिकित्सकीय प्रमाण मांगे जाने पर सवाल उठाए गए। वहीं, उनके स्थानांतरण को लेकर भी चर्चा हुई। उन्हें होमगार्ड संगठन से हटाकर बैरकपुर की पहली बटालियन में भेजा गया और बाद में वे बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल ब्रांच में डीसी के रूप में कार्यरत रहीं। हालांकि उस समय पुलिस विभाग ने स्थानांतरण को प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया था।

पश्चिम मेदिनीपुर की पुलिस अधीक्षक के रूप में उनकी भूमिका ने उनके करियर को एक नया आयाम दिया है। यह जिला भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से विविध है तथा यहां ग्रामीण क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्र भी हैं। कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा के साथ सामाजिक विकास से जुड़े विषयों पर भी जिला पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

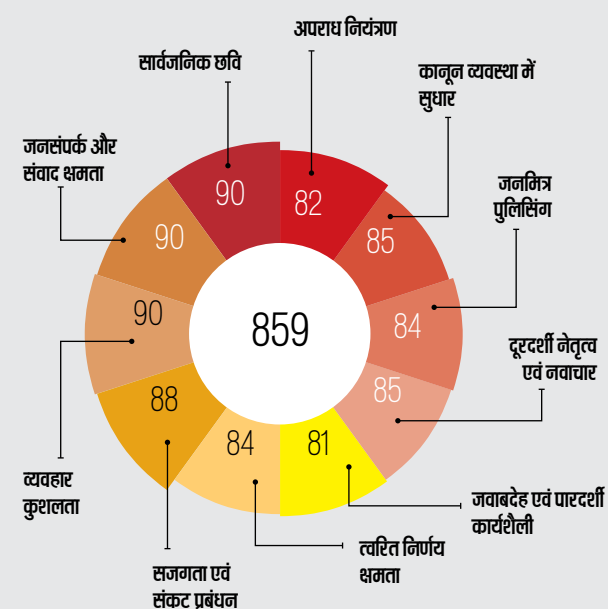
उनके नेतृत्व में पश्चिम मेदिनीपुर पुलिस ने पुलिस को समुदाय के साथ जोड़ने वाली कुछ नई पहलों पर भी जोर दिया है। इनमें 'प्रस्तुति' कार्यक्रम उल्लेखनीय है, जिसके तहत पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, फिटनेस और लिखित परीक्षा की तैयारी में मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की गई। पापिया सुल्ताना ने विद्यार्थियों को अनुशासन और निरंतर तैयारी का महत्व समझाते हुए विशेष रूप से छात्राओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और करियर निर्माण पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया।

उनकी सोच पुलिस की भूमिका को केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं रखती। जुलाई 2026 में पश्चिम मेदिनीपुर पुलिस ने 'पुलिस असिस्टेंस इन करियर एंड एम्प्लॉयमेंट एन्हांसमेंट' यानी 'पेस' पहल शुरू की। पहले चरण में करीब एक हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया।

2026 में विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम मेदिनीपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारियों में रहा। चुनाव परिणामों के बाद कुछ क्षेत्रों में हिंसा और राजनीतिक तनाव की घटनाएं सामने आईं। जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से स्थिति की समीक्षा की तथा बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की गईं। ऐसे संवेदनशील माहौल में पुलिस की चुनौती निष्पक्षता, कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के बीच संतुलन कायम करने की होती है।



हावड़ा जिले के बाउड़िया क्षेत्र में जन्मी पापिया सुल्ताना का पारिवारिक परिवेश शिक्षा और पेशेवर सोच से जुड़ा रहा। उनके पिता अरजहान हलदर इंजीनियर और मां सलीमा जेहान मदरसा शिक्षिका रही हैं। परिवार से मिले शिक्षा के संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां भी उल्लेखनीय हैं। उपलब्ध प्रोफाइलों के अनुसार उन्होंने एमबीए, जेंडर डेवलपमेंट में परास्नातक, एलएलबी और एलएलएम जैसी

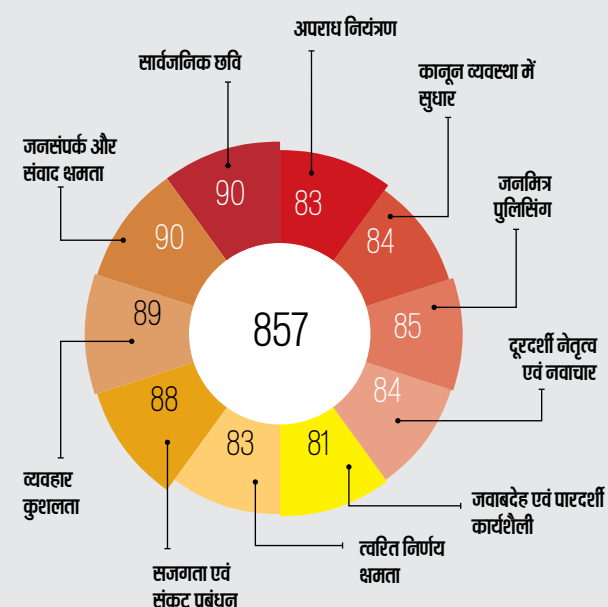


तकनीक की समझ, फील्ड का अनुभव
और अपराध पर सटीक प्रहार

शशांक जायसवाल

दिल्ली ट्रैफिक (अब रोहिणी), दिल्ली

दिल्ली जैसे महानगर में पुलिस नेतृत्व केवल कानून-व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बदलते शहरी अपराध, यातायात, तकनीक, संगठित गिरोहों और नागरिक सुरक्षा की लगातार बदलती चुनौतियों को समझने की क्षमता भी मांगता है। भारतीय पुलिस सेवा के 2014 बैच के अधिकारी शशांक जायसवाल इसी बहुआयामी पुलिस नेतृत्व की एक उल्लेखनीय मिसाल हैं। वर्तमान में रोहिणी जिले के पुलिस उपायुक्त के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे जायसवाल ने एक दशक से अधिक की सेवा में दिल्ली के कई महत्वपूर्ण जिलों और विशेष इकाइयों में काम करते हुए व्यापक अनुभव अर्जित किया है।



शशांक जायसवाल की पुलिसिंग की खासियत है—तकनीक की समझ, प्रशासनिक दक्षता, फील्ड अनुभव और अपराध नियंत्रण का संतुलित मेल। विजिलेंस, नॉर्थ-ईस्ट, नॉर्थ-वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिम्मेदारियां निभाने के साथ उन्होंने मिजोरम और दिल्ली यातायात पुलिस में भी अपनी कार्यक्षमता साबित की है।

उनकी शैक्षणिक यात्रा भी उनके पेशेवर दृष्टिकोण को समझने की कुंजी है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल

मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में भी रोहिणी पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। मई 2026 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मणिपुर तक फैले अंतरराज्यीय मादक पदार्थ नेटवर्क का खुलासा करते हुए दस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और हेरोइन तथा कच्ची अफीम सहित लगभग 16 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए। जांच के तार मणिपुर के रास्ते म्यांमार सीमा क्षेत्र तक जुड़ने की बात सामने आई। यह कार्रवाई स्थानीय सूचना को व्यापक अंतरराज्यीय जांच में बदलने की पुलिस क्षमता को दर्शाती है।



इंजीनियरिंग में बी.टेक. करने के बाद उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड से वित्त एवं मार्केटिंग में दोहरी विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया। पुलिस सेवा में आने से पहले प्रतिष्ठित कॉरपोरेट कंपनियों में काम करने का अनुभव भी उन्हें मिला। तकनीकी और प्रबंधन की यह पृष्ठभूमि आगे चलकर उनके प्रशासनिक और परिचालन दृष्टिकोण की ताकत बनी।

दिल्ली यातायात पुलिस में उनका कार्यकाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। अक्टूबर 2023 से यातायात प्रभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने डीसीपी यातायात मुख्यालय के रूप में भी कार्य किया। दिल्ली में यातायात प्रबंधन अपने आप में अत्यंत जटिल दायित्व है, जिसमें सड़क सुरक्षा, दुर्घटना नियंत्रण, बड़े आयोजनों की यातायात व्यवस्था और महत्वपूर्ण मार्गों का प्रबंधन शामिल है। इस भूमिका में उनके प्रशासनिक कौशल के साथ उनका मानवीय पक्ष भी सामने आया। दिल्ली यातायात पुलिस के अप्रैल 2025 के आधिकारिक समाचार पत्र के अनुसार, उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद की। एक घटना में उन्होंने पलटते हुए ट्रक से चालक को बाहर निकाला, जबकि दूसरी दुर्घटना में बेहोश व्यक्ति को सीपीआर देकर सहायता पहुंचाई।

उनकी प्रशासनिक क्षमता को भी सम्मान मिला। आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, वर्ष 2024 में उत्कृष्ट प्रशासनिक कर्तव्यों के लिए उन्हें पुलिस आयुक्त की डिस्क प्रदान की गई। भारत सरकार की आईपीएस सिविल सूची में पुलिस पदक 2022 सहित उनके अन्य सेवा सम्मानों का भी उल्लेख मिलता है।

वर्ष 2026 में दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक फेरबदल के दौरान उन्हें डीसीपी यातायात से रोहिणी जिले की कमान सौंपी गई। इसके बाद रोहिणी में संगठित अपराध और हथियारबंद गिरोहों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। गोगी गिरोह के छह सदस्यों की गिरफ्तारी के दौरान 18 पिस्तौल और 111 गोलियां बरामद की गईं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े तीन कथित शूटरों को गिरफ्तार कर तीन पिस्तौल और बड़ी मात्रा में गोलियां बरामद की गईं। पुलिस के अनुसार, इनका संबंध दिल्ली और चंडीगढ़ के कारोबारियों को निशाना बनाने की साजिश से था और कार्रवाई से दिल्ली से आजमगढ़ तक फैले कथित शूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचा।

वाहन चोरी के संगठित नेटवर्क पर भी कार्रवाई हुई। जून 2026 में छह आरोपियों से 19 चोरी की कारें बरामद की गईं, जिन्हें दिल्ली से चोरी कर पंजाब और राजस्थान में बेचने का नेटवर्क सामने आया। अगस्त में 72 घंटे के विशेष अभियान के दौरान 161 चोरी के दोपहिया वाहन बरामद कर 103 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई भी उनकी प्राथमिकता रही। जुलाई 2026 में कंझावला में एक संपत्ति कारोबारी की हत्या के बाद टिल्लू ताजपुरिया गिरोह से जुड़े दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। महिला सुरक्षा के मामलों में भी त्वरित कार्रवाई की गई।

शशांक जायसवाल की पहचान केवल एक कठोर अपराध नियंत्रक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप पुलिसिंग की रणनीति बनाने वाले अधिकारी के रूप में उभरती है। इंजीनियरिंग और प्रबंधन की शिक्षा, कॉरपोरेट अनुभव, मिजोरम की सेवा, दिल्ली के विभिन्न जिलों का अनुभव, यातायात पुलिस का नेतृत्व और अब रोहिणी की कमान—इन सभी ने उनके व्यक्तित्व को व्यापक बनाया है।

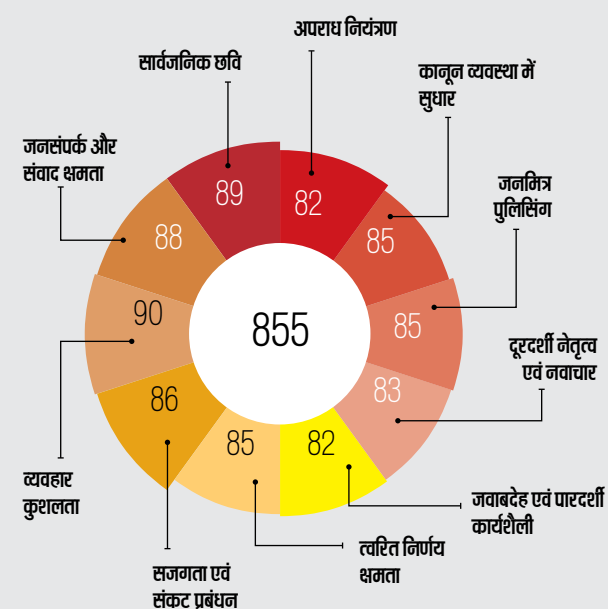
रोहिणी में उनकी चुनौती बड़ी है, लेकिन अब तक की कार्यशैली यह संकेत देती है कि वे तकनीक, सूचना, समन्वय और जमीनी पुलिसिंग को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। संगठित गिरोहों पर प्रहार से लेकर आम नागरिक की सुरक्षा तक, उनका दृष्टिकोण एक ऐसे आधुनिक पुलिस नेतृत्व की तस्वीर पेश करता है जिसमें सख्ती के साथ संवेदनशीलता और रणनीति के साथ त्वरित कार्रवाई का संतुलन दिखाई देता है।

संगठित अपराध के खिलाफ सख्त और रणनीतिक पुलिसिंग

प्रभात कुमार

धनबाद, झारखंड

बिहार के वैशाली जिले के मौना विशुनपुर गांव से आने वाले प्रभात कुमार की शुरुआती शिक्षा सरकारी विद्यालय में हुई। उन्होंने मुजफ्फरपुर से इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई पूरी की तथा महाराष्ट्र से एमबीए किया। पुलिस सेवा में आने से पहले वे निजी बैंक में मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं। नौकरी के साथ उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जारी रखी और 2013 की यूपीएससी परीक्षा क्रेक कर आईपीएस में झारखंड कैडर हासिल किया।



प्रभात कुमार की कार्यशैली में संगठित अपराध के नेटवर्क पर प्रहार, फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान, जांच की गुणवत्ता, पुलिस बल की क्षमता निर्माण और नागरिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण को समान महत्व मिलता है। धनबाद में उनकी चुनौती बड़ी है, लेकिन अब तक की पुलिस कार्यवाई यह संकेत देती है कि उनकी प्राथमिकता स्पष्ट है—कानून का प्रभावी पालन, संगठित अपराध पर निर्णायक दबाव और आम नागरिक के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना।



अध्ययन का अवसर मिला। 2016 में वे झारखंड के चर्चित सफायर इंटरनेशनल स्कूल हत्याकांड की जांच प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों में शामिल थे। उन्होंने मामले में उपलब्ध फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया।

सेवा के दौरान प्रभात कुमार ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। वे रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक रहे, जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया और बाद में पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी भी संभाली। धनबाद आने से पहले वे पाकुड़ के एसपी थे। इन विभिन्न पदों ने उन्हें ग्रामीण और शहरी कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन तथा संवेदनशील क्षेत्रों की चुनौतियों का व्यापक अनुभव दिया।

धनबाद में पदभार संभालते समय उन्होंने स्पष्ट किया था कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। खास तौर पर आर्थिक अपराध और संगठित अपराध पर कार्यवाई को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। वे ऐसी पुलिसिंग विकसित करना चाहते हैं जिसमें आम नागरिक को अनावश्यक रूप से थानों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उनकी प्राथमिकताओं का असर धनबाद पुलिस की कार्यवाई में दिखाई दिया। वर्ष 2025 में जिले में अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया, जिसमें 1,799 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस की कार्यवाई में हत्या, डकैती, लूट, चोरी, अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और हथियार कानून से जुड़े मामले शामिल थे। यह अभियान अपराध नियंत्रण को केवल किसी एक श्रेणी तक सीमित रखने के बजाय व्यापक आपराधिक नेटवर्क पर कार्यवाई की रणनीति को दर्शाता है।

संगठित अपराध के खिलाफ उनकी रणनीति में अलग कोर टीम बनाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। धनबाद में सक्रिय गिरोहों और उनके अपराध करने के तरीकों का विश्लेषण कर एक विशेष टीम को संगठित अपराध पर केंद्रित किया गया। उनका जोर ऐसे नेटवर्क को तोड़ने पर रहा, जिनके माध्यम से अपराध लगातार दोहराए जाते हैं।

वर्ष 2026 में फरार और वांछित अपराधियों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया गया। अप्रैल में धनबाद पुलिस ने एक ही दिन जिले भर में 249 लंबित वारंटों का निष्पादन किया और 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें गिरफ्तारी वारंट के साथ गवाह, कुर्की और स्थायी वारंट भी शामिल थे। एसएसपी ने लंबित वारंटों के निष्पादन को अपराध नियंत्रण और कानून के प्रति अपराधियों में भय पैदा करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।

धनबाद में उनकी पुलिसिंग का एक उल्लेखनीय पक्ष कुख्यात संगठित अपराधी प्रिंस खान और उसके नेटवर्क के खिलाफ कार्यवाई भी रही है। पुलिस ने उसके सहयोगियों और नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाया तथा बाद में वासेपुर में उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्यवाई भी की गई। यह कार्यवाई लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा थी।

अपराध नियंत्रण के साथ प्रभात कुमार ने पुलिस बल की क्षमता और जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया। शिकायतों के निस्तारण में भी उनकी निगरानी दिखाई देती है। जून 2026 में धनबाद पुलिस ने पीजी पोर्टल पर दर्ज 376 शिकायतों का निस्तारण किया। एसएसपी ने शेष मामलों को भी समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाने के निर्देश दिए।

अपराध समीक्षा बैठकों में वे लंबित मामलों को कम करने, अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान और गुप्त मोबाइल की बरामदगी जैसे लक्ष्यों पर भी जोर देते रहे हैं। जुलाई 2026 में हुई समीक्षा में पुलिस ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अपराध में करीब 30 प्रतिशत कमी दर्ज की।

प्रभात कुमार की पुलिसिंग का एक और पहलू पुलिसकर्मियों की परिचालन क्षमता बढ़ाना है। जून 2026 में धनबाद के 2,586 पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए वार्षिक फायरिंग दक्षता अभ्यास आयोजित किया गया।

झारखंड कैडर के 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रभात कुमार वर्तमान में धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 28 मई 2025 को धनबाद एसएसपी का पदभार संभाला था और तब से कोयलांचल में संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, फरार अपराधियों तथा कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार कार्यवाई को प्राथमिकता दी है।

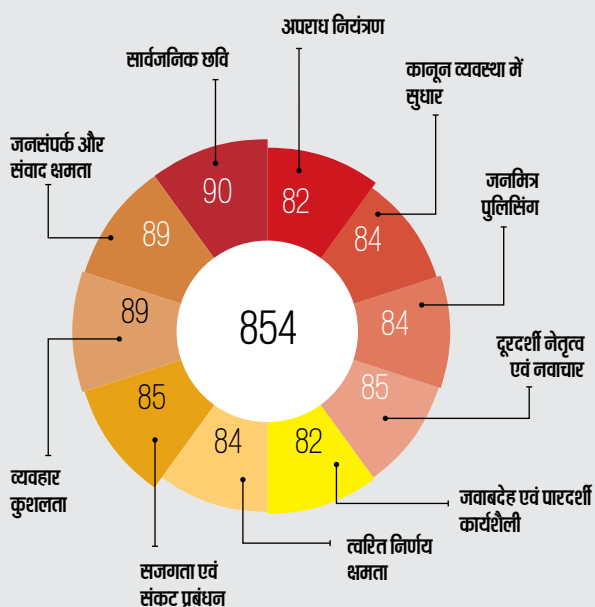
प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें जटिल आपराधिक मामलों के

संवेदनशीलता और दृढ़
पुलिसिंग की मिसाल

डॉ. नवजोत सिमी

अरवल, बिहार

पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली डॉ. नवजोत सिमी का पेशेवर सफर इसलिए भी प्रेरक है क्योंकि उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र से निकलकर भारतीय पुलिस सेवा को अपना करियर बनाया। उन्होंने बीडीएस की पढ़ाई पूरी की और कुछ समय तक दंत चिकित्सक के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का निर्णय लिया। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और उन्हें बिहार कैडर आवंटित हुआ।



बिहार पुलिस की चर्चित महिला आईपीएस अधिकारियों में डॉ. नवजोत सिमी का नाम विशेष पहचान रखता है। वर्तमान में वे अरवल की पुलिस अधीक्षक हैं। पुलिस सेवा के शुरुआती दौर में उनकी तैनाती पटना में रही। इसके बाद वे रोहतास जिले के डेहरी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहीं। डेहरी जैसे महत्वपूर्ण अनुमंडल में उन्हें कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस-प्रशासन समन्वय और संवेदनशील मामलों की निगरानी का अनुभव मिला।

अरवल की पहली महिला एसपी के रूप में उनकी कार्यशैली का सबसे स्पष्ट पक्ष पुलिस और जनता के बीच दूरी कम करने का प्रयास है। उन्होंने केवल कार्यालय में बैठकर शिकायतें सुनने के बजाय थाना स्तर पर पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद को प्राथमिकता दी। मई 2026 में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य जनसमस्याओं का त्वरित समाधान और पुलिस-जन संवाद को मजबूत करना था। डॉ. सिमी स्वयं विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहुंचीं और लोगों की समस्याओं को सुना। इन शिविरों में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, साइबर अपराध, नशे और सामाजिक सौहार्द से जुड़े विषय सामने आए।



उनके करियर का एक महत्वपूर्ण चरण बिहार पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग में रहा, जहां उन्होंने कमजोर वर्गों और महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी जिम्मेदारी संभाली। यह जिम्मेदारी उनके पेशेवर व्यक्तित्व के मानवीय पक्ष को समझने के लिए महत्वपूर्ण रही। उनका मानना है कि महिलाओं, कमजोर वर्गों और संवेदनशील मामलों से जुड़े पुलिस कार्य में केवल कानूनी कार्यवाई पर्याप्त नहीं होती; पीड़ितों का विश्वास हासिल करना, शिकायतों को गंभीरता से लेना और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय भी उतना ही जरूरी होता है।

इसके बाद उन्हें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की बटालियन कमान की जिम्मेदारी मिली। वर्ष 2024 में वे बेगूसराय स्थित बीएसएपी-8 की कमांडेंट बनीं और जुलाई 2025 में उन्हें बीएसएपी-19 का कमांडेंट बनाया गया। इस भूमिका ने उनके अनुभव को जिला पुलिसिंग से आगे बढ़ाकर पुलिस बल के नेतृत्व, अनुशासन, प्रशिक्षण और परिचालन प्रबंधन तक विस्तारित किया।

यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार पुलिस तक शिकायत पहुंचने में ही लोगों को कठिनाई होती है। डॉ. सिमी ने ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों को कार्यवाई और समस्या के समाधान के निर्देश दिए। जून 2026 में भी सहयोग शिविरों के माध्यम से पुलिस-जन समन्वय और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया।

जनता दरबार उनकी पुलिसिंग का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। फरवरी 2026 में सदर थाना परिसर में लगाए गए जनता दरबार में उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया। उनका जोर शिकायतों को केवल दर्ज करने पर नहीं, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर उनके समाधान पर रहा। जून में अपने कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में भी उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुनकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध कार्यवाई के निर्देश दिए।

थाना स्तर पर उनकी निगरानी भी उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। रामपुर चौरम थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार के दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुनने के साथ थाना की कानून-व्यवस्था, पुलिसकर्मियों के व्यवहार और अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। इससे यह संकेत मिलता है कि उनके लिए पुलिसिंग केवल अपराधियों के खिलाफ कार्यवाई तक सीमित नहीं, बल्कि थाने की कार्यसंस्कृति और नागरिकों के साथ पुलिस के व्यवहार से भी जुड़ी है।

अरवल में गंभीर घटनाओं के मामलों में उनका फील्ड स्तर पर सक्रिय रहना भी सामने आया है। जुलाई 2026 में एक घटना के बाद डॉ. नवजोत सिमी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचीं और मामले के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने निष्पक्ष जांच के साथ आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इस तरह की प्रत्यक्ष निगरानी महत्वपूर्ण मामलों में जांच की दिशा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करती है।

डॉ. नवजोत सिमी की पहचान सोशल मीडिया पर भी व्यापक रही है, लेकिन उनकी पेशेवर यात्रा का वास्तविक महत्व उनके पुलिस अनुभव में है। डॉक्टर के रूप में करियर शुरू करने के बाद सिविल सेवा में आना, पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त करना, पटना और डेहरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करना, कमजोर वर्गों और महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी संभालना तथा सशस्त्र पुलिस बल की कमान तक पहुंचना उनके बहुआयामी अनुभव को दर्शाता है।

डॉ. नवजोत सिमी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि करियर की दिशा बदलने का निर्णय यदि दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत के साथ लिया जाए तो नई पहचान बनाई जा सकती है। उनकी यात्रा न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता की भी मिसाल है।



फील्ड पुलिसिंग, एंटी-करप्शन और दिल्ली की चुनौतीपूर्ण कमान

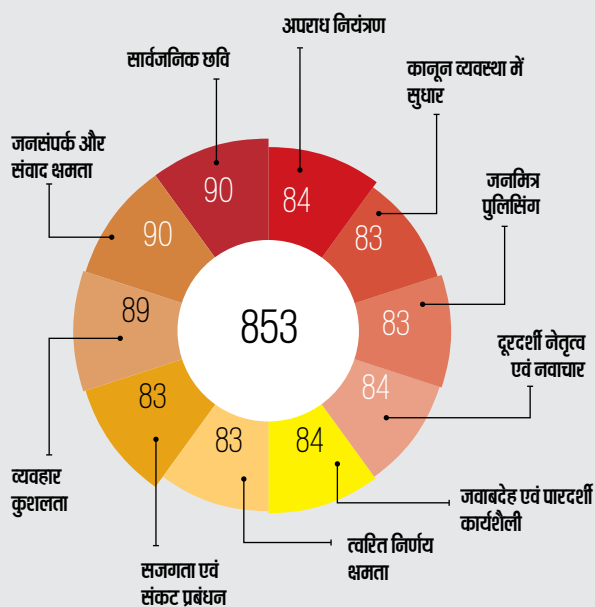
अनंत मित्तल

दक्षिण दिल्ली, दिल्ली

भारतीय पुलिस सेवा के 2015 बैच के अधिकारी अनंत मित्तल वर्तमान में दिल्ली के दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनकी पुलिस सेवा का अनुभव केवल महानगरीय कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में एंटी-करप्शन ब्यूरो और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों से भी जुड़ा रहा है। यही विविध अनुभव उनके पेशेवर व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाता है।



दक्षिण दिल्ली की कमान अनंत मित्तल के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। एक ऐसे अधिकारी के रूप में, जिसने संवेदनशील क्षेत्रों में फील्ड पुलिसिंग के साथ भ्रष्टाचार विरोधी जांच का अनुभव भी हासिल किया है, उनसे अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था के साथ पेशेवर एवं जवाबदेह पुलिस प्रशासन की अपेक्षा की जाती है। उनकी सेवा यात्रा यह बताती है कि आधुनिक पुलिसिंग में केवल वर्दी और अधिकार पर्याप्त नहीं होते; जांच की गहराई, तकनीक का इस्तेमाल, प्रशासनिक अनुशासन और नागरिकों के विश्वास को साथ लेकर चलना भी उतना ही आवश्यक है। अनंत मित्तल का करियर इसी व्यापक और बहुआयामी पुलिसिंग दृष्टिकोण का उदाहरण है।



अनंत मित्तल का जन्म 12 नवंबर 1988 को हुआ। वे हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता बीटेक है। उनके करियर की खासियत विभिन्न प्रकार की पुलिसिंग का अनुभव है। दिल्ली में उन्होंने फील्ड पुलिसिंग से लेकर जिला स्तर की वरिष्ठ जिम्मेदारियां संभालीं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने भ्रष्टाचार और जटिल आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। यह संयोजन उन्हें अपराध की रोकथाम,

जांच, खुफिया सूचना के इस्तेमाल और प्रशासनिक निगरानी—चारों क्षेत्रों में अनुभव प्रदान करता है।

अरुणाचल प्रदेश में उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में एंटी-करप्शन ब्यूरो के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल (एसआईसी) के पुलिस अधीक्षक का पद रहा। एंटी-करप्शन ब्यूरो के एसपी के रूप में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े चर्चित नौकरी घोटाले की जांच की, जिसमें 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में दस्तावेजी साक्ष्य, वित्तीय लेन-देन, तकनीकी इनपुट और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण होता है। इस जिम्मेदारी ने उनके पुलिसिंग अनुभव में एक अलग आयाम जोड़ा।

अरुणाचल प्रदेश में उनकी सेवाओं को राज्य स्तर पर भी मान्यता मिली। फरवरी 2025 में राज्यपाल के. टी. परनाइक ने उन्हें स्टेट गोल्ड मेडल प्रदान किया। यह सम्मान उनकी सेवाओं और राज्य में उनके योगदान की संस्थागत मान्यता का महत्वपूर्ण प्रमाण है।

मई 2025 में दिल्ली पुलिस के बड़े प्रशासनिक फेरबदल के दौरान अनंत मित्तल को अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली वापस भेजा गया। उस समय अनंत मित्तल को उत्तर जिले में अतिरिक्त डीसीपी की जिम्मेदारी दी गई। उत्तर जिले में अतिरिक्त डीसीपी के रूप में उन्हें राजधानी के एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक व्यस्त पुलिस जिले में अपराध नियंत्रण, थाना स्तर की निगरानी और कानून-व्यवस्था से जुड़े दायित्वों का अनुभव मिला।

इसके बाद 2026 में उन्हें दक्षिण जिले का डीसीपी बनाया गया। दक्षिण दिल्ली की पुलिसिंग अपने आप में अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। यहां आवासीय क्षेत्रों के साथ बड़े बाजार, शिक्षण संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल और उच्च सुरक्षा वाले इलाके भी आते हैं। अपराध नियंत्रण के साथ महिला सुरक्षा, सड़क अपराध, साइबर अपराध, नशे से संबंधित अपराध और कानून-व्यवस्था बनाए रखना डीसीपी की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है।

दक्षिण दिल्ली की कमान संभालने के बाद उनकी पुलिसिंग में अपराध की रोकथाम और गंभीर मामलों की त्वरित जांच पर जोर दिखाई देता है। जिला पुलिस की विभिन्न कार्यवाहियों में तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी विश्लेषण, स्थानीय सूचना तंत्र और विशेष टीमों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। यह आधुनिक महानगरीय पुलिसिंग की उस दिशा को दर्शाता है जिसमें अपराध होने के बाद कार्यवाई के साथ-साथ अपराध के पैटर्न और संभावित स्थानों की पहचान कर पहले से रोकथाम की रणनीति तैयार की जाती है।

उनकी कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पहलू अंतर-विभागीय और अंतर-इकाई समन्वय भी है। अरुणाचल में एंटी-करप्शन ब्यूरो में काम करते हुए उन्होंने जांच-केंद्रित पुलिसिंग का अनुभव हासिल किया, जबकि दिल्ली में जिला पुलिस की जिम्मेदारियों ने उन्हें बड़े शहरी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और फील्ड पुलिसिंग का व्यापक अनुभव दिया। इस प्रकार उनका अनुभव जांच और परिचालन पुलिसिंग के बीच एक उपयोगी संतुलन प्रस्तुत करता है।

दक्षिण जिले में डीसीपी के रूप में उनकी भूमिका केवल अपराधियों के खिलाफ कार्यवाई तक सीमित नहीं है। उन्हें पुलिस बल की कार्यक्षमता, थाना स्तर की जवाबदेही, नागरिक शिकायतों के निस्तारण, महिला एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जैसे अनेक मोर्चों को एक साथ संभालना होता है। दिल्ली जैसे महानगर में पुलिस की सफलता का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह भी है कि नागरिकों में सुरक्षा की भावना कितनी मजबूत है।

अनंत मित्तल की अब तक की सेवा यात्रा को देखें तो उसमें तीन अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़े आयाम स्पष्ट दिखाई देते हैं—मैदानी पुलिसिंग, भ्रष्टाचार एवं जटिल मामलों की जांच और महानगरीय जिला पुलिस प्रशासन। अरुणाचल प्रदेश में एंटी-करप्शन ब्यूरो के एसपी के रूप में मिली जिम्मेदारी और स्टेट गोल्ड मेडल से सम्मानित होना उनके जांच एवं प्रशासनिक कौशल की पहचान है। वहीं दिल्ली में उत्तर जिले के अतिरिक्त डीसीपी और अब दक्षिण जिले के डीसीपी के रूप में उनकी जिम्मेदारी राजधानी की चुनौतीपूर्ण शहरी पुलिसिंग से जुड़ी है।



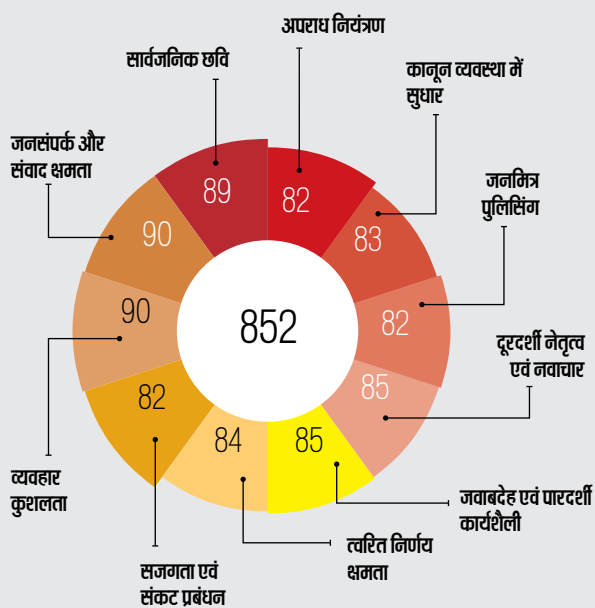


तकनीकी सोच, दृढ़ नेतृत्व और
जनविश्वास की नई पहचान

अदिति सिंह

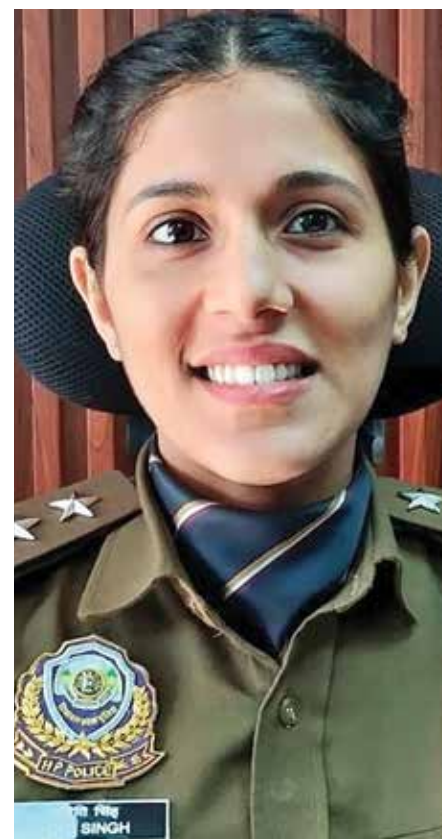
पंचकूला, हरियाणा

बदलते दौर में जब पुलिसिंग की चुनौतियां लगातार जटिल होती जा रही हैं, ऐसे में तकनीकी समझ, प्रशासनिक दक्षता और संवेदनशील नेतृत्व का महत्व और बढ़ गया है। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी अदिति सिंह इसी बदलती पुलिसिंग की एक उल्लेखनीय तस्वीर पेश करती हैं। वर्ष 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी के रूप में उन्होंने कम समय में अलग-अलग जिम्मेदारियों का अनुभव हासिल किया और जुलाई 2026 में पंचकूला की डीसीपी के रूप में नई जिम्मेदारी संभाली।



अदिति सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1995 को हुआ, वह 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। अदिति सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित प्रतिष्ठित सोफिया गर्ल्स स्कूल कैंट की छात्रा रही हैं। उन्होंने वर्ष-2017 में अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कालेज गाजियाबाद से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। उनके पिता डा. संजीव सिंह चिकित्सक हैं, जबकि माता ज्योति सिंह मेरठ तहसील में वरिष्ठ सहायक हैं। अदिति नृत्य में पारंगत हैं, और वाद-

अदिति सिंह की कहानी अभी निर्माण के दौर में है। 2021 बैच की युवा आईपीएस अधिकारी से लेकर पंचकूला की DCP तक का उनका सफर बताता है कि पुलिस सेवा में जिम्मेदारियां तेजी से बढ़ सकती हैं, लेकिन उनके साथ अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ती हैं। पंचकूला में उनकी नई भूमिका उनके प्रशासनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे पुलिस की सख्ती और मानवीय संवेदनशीलता के बीच सही संतुलन कायम करें। यदि पुलिस कार्रवाई तेज होने के साथ नागरिकों का भरोसा भी मजबूत होता है, तो वही किसी अधिकारी के नेतृत्व की वास्तविक सफलता होगी।



विवाद में भी सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुनी जाती थीं। वहीं, खेलों में भी कालेज स्तर पर वॉलीबॉल टीम की भी कैप्टन रह चुकी हैं।

इंजीनियरिंग की शिक्षा ने उन्हें तकनीकी और विश्लेषणात्मक दृष्टि प्रदान की, लेकिन पुलिस सेवा में उनकी भूमिका केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं है। उन्हें शुरुआत में हिमाचल कैडर मिला था, जहां वह एंटी करप्शन व विजिलेंस की एसपी बनी थीं, लेकिन विवाह के बाद उनका कैडर हरियाणा हो गया। खास बात यह रही कि उन्हें हरियाणा में भी इसी विभाग में गुरुग्राम में तैनाती मिली, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार पर जोरदार नकेल कसी थी।

पंचकूला में पदभार संभालते ही अदिति सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दीं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, अपराध नियंत्रण और आम जनता के लिए सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण को प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि प्रत्येक शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

यह दृष्टिकोण आधुनिक पुलिसिंग की उस अवधारणा से मेल खाता है जिसमें पुलिस और जनता के बीच दूरी कम करना बेहद जरूरी माना जाता है। किसी भी शहर में कानून-व्यवस्था केवल पुलिस बल की संख्या या कार्रवाई की सख्ती से मजबूत नहीं होती। नागरिकों को यह विश्वास भी होना चाहिए कि उनकी शिकायत सुनी जाएगी और उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई मिलेगी। अदिति सिंह ने पंचकूला में कार्यभार संभालते समय इसी जनविश्वास को अपनी प्राथमिकताओं में स्थान दिया।

पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न शाखाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। उन्होंने अलग-अलग इकाइयों की कार्यप्रणाली, उनकी जिम्मेदारियों और जिले की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अदिति सिंह की यात्रा की एक विशेषता उनकी अपेक्षाकृत कम उम्र में मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश व हरियाणा, दोनों ही राज्यों में विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस भूमिकाओं में काम किया।

उनकी कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पुलिस की ताकत केवल कार्रवाई में नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास में भी निहित होती है। तकनीकी शिक्षा से मिली विश्लेषणात्मक क्षमता, पुलिस सेवा से मिली प्रशासनिक समझ और जनता की समस्याओं को सुनने की प्रतिबद्धता—इन तीनों का संतुलन उनके नेतृत्व की दिशा तय कर सकता है।

आज जब देश में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और बदलते अपराध स्वरूप जैसी चुनौतियां पुलिस व्यवस्था के सामने हैं, कंप्यूटर साइंस की पृष्ठभूमि रखने वाली एक युवा आईपीएस अधिकारी के लिए तकनीक और पारंपरिक पुलिसिंग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की संभावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उनके वर्तमान कार्यकाल के परिणामों का मूल्यांकन समय के साथ ही किया जा सकेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर उन्होंने जनविश्वास, महिला सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई को प्राथमिकता देकर अपनी दिशा स्पष्ट कर दी है।

अदिति सिंह की अब तक की यात्रा इसी संभावना की ओर संकेत करती है—तकनीकी सोच के साथ प्रशासनिक दृढ़ता, कानून के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संवेदनशीलता और अधिकार के साथ जवाबदेही। पंचकूला में उनकी नई जिम्मेदारी केवल एक पदस्थापना नहीं, बल्कि एक ऐसे पुलिस नेतृत्व की परीक्षा है जिसमें नागरिकों की सुरक्षा के साथ उनका विश्वास भी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

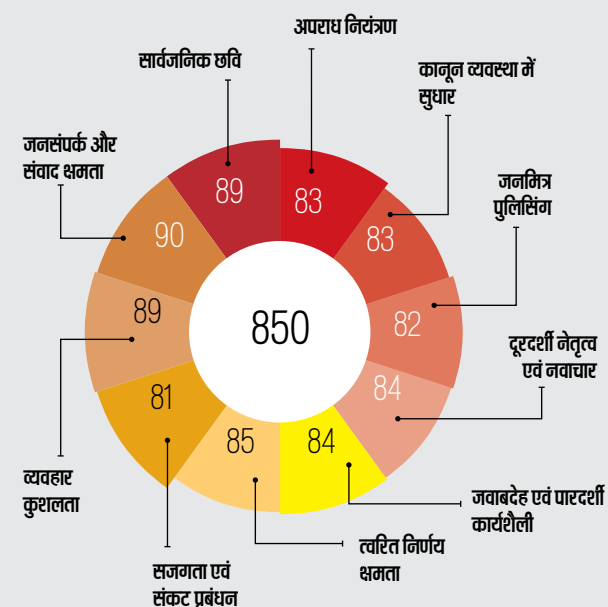


तकनीक, तर्क और संवेदनशील
पुलिसिंग से गढ़ी बदलाव की नई मिसाल

कृषिकेश रावले

पुणे, महाराष्ट्र

आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की चर्चा महानगरों, कॉरपोरेट संस्थानों और तकनीकी कंपनियों तक सीमित दिखाई देती है, ऐसे समय में एक पुलिस अधिकारी ने यह साबित किया है कि अत्याधुनिक तकनीक का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देता है, जब उसका इस्तेमाल आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। महाराष्ट्र कैडर के 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी कृषिकेश रावले इसी सोच के प्रतिनिधि के रूप में उभरे हैं। इंजीनियरिंग की तार्किक सोच, पुलिस सेवा की जिम्मेदारी और समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को साथ लेकर उन्होंने प्रशासन और पुलिसिंग में तकनीक के प्रयोग की एक ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई।



मै केनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. की शिक्षा ने उनके सोचने के तरीके को विश्लेषणात्मक बनाया। उनका मानना है कि इंजीनियरिंग हर समस्या के मूल कारण को तलाशना सिखाती है। यही दृष्टिकोण उन्होंने पुलिसिंग में भी अपनाया। उनके अनुसार, यदि कोई अपराध होता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई कमजोर कड़ी या टूटा हुआ संपर्क अवश्य होता है; उस कड़ी को पहचानकर ठीक करना ही स्थायी समाधान की दिशा है।

कृषिकेश रावले की यात्रा इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें तीन अलग-अलग धाराएं एक साथ दिखाई देती हैं—इंजीनियरिंग की तार्किकता, पुलिस सेवा की दृढ़ता और जनसेवा की संवेदनशीलता। सिंधुदुर्ग में एआई आधारित प्रशासन से लेकर पुणे में स्मार्ट पुलिसिंग, अपराध जांच, अवैध प्रवास के खिलाफ कार्रवाई और युवाओं के बीच नशामुक्ति अभियान तक, उनका काम इस बात का उदाहरण है कि तकनीक तभी सार्थक है जब वह लोगों की सुरक्षा और सुविधा के काम आए।



इसी विश्लेषणात्मक सोच का प्रभाव उनके कार्यों में भी दिखाई देता है। सिंधुदुर्ग में तैनाती के दौरान उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 मई 2025 को सिंधुदुर्ग को भारत का पहला एआई सक्षम जिला बनने की उपलब्धि मिली। यह केवल किसी एक तकनीकी परियोजना की सफलता नहीं थी, बल्कि शासन की कार्यप्रणाली में तकनीक को व्यवस्थित रूप से शामिल करने का प्रयास था।

इस पहल की खासियत यह थी कि एआई का इस्तेमाल केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रखा गया। प्रशासन ने भी सिंधुदुर्ग एआई मॉडल विकसित किया, जिसके माध्यम से आठ प्रमुख सरकारी विभागों में एआई के उपयोग की दिशा में काम किया गया। इस मॉडल के तहत स्मार्ट अपराध-निवारण और पुलिसिंग, बुद्धिमत्तापूर्ण यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कुपोषण की निगरानी जैसे क्षेत्रों में तकनीक का उपयोग किया गया। मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए बायो-अकॉस्टिक अलर्ट सिस्टम जैसी पहल भी इसी तकनीक-आधारित दृष्टिकोण का हिस्सा बनी। यानी एआई को केवल आधुनिकता का प्रतीक बनाने के बजाय उसे नागरिक सुरक्षा और जनकल्याण का साधन बनाने का प्रयास किया गया।

सिंधुदुर्ग मॉडल की सफलता ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। नीति आयोग के अधिकारियों ने जिले का दौरा कर यह समझने की कोशिश की कि इस मॉडल को देश के अन्य हिस्सों में किस प्रकार दोहराया जा सकता है। इस उपलब्धि ने यह संदेश दिया कि तकनीकी नवाचार के लिए केवल बड़े शहरों और विशाल संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती; इच्छाशक्ति और सही दृष्टिकोण के साथ छोटे जिले भी परिवर्तन के प्रयोगशाला बन सकते हैं।

सिंधुदुर्ग के बाद पुणे में भी रावले की तकनीक-आधारित कार्यशैली का प्रभाव देखने को मिला। डीसीपी जोन-1, पुणे के रूप में उन्होंने पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ सामाजिक समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। गणेशोत्सव जैसे बड़े आयोजनों में एआई आधारित भीड़ प्रबंधन प्रणालियों का इस्तेमाल कर लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम किया गया। लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं की मौजूदगी वाले आयोजन में भीड़ के सुरक्षित प्रबंधन के लिए तकनीक का इस्तेमाल उनके आधुनिक पुलिसिंग दृष्टिकोण को दर्शाता है।

रावले का कार्यक्षेत्र केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। पुणे में अवैध प्रवास और मानव तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ चलाए गए अभियान ने भी उन्हें चर्चा में रखा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने एक वर्ष में 100 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया था और 11 महीनों में 105 लोगों को हिरासत में लेकर लक्ष्य से आगे निकल गए। इस अभियान में खुफिया जानकारी, विश्लेषण और व्यवस्थित कार्रवाई को महत्व दिया गया।

युवाओं के बीच बढ़ती नशे की समस्या को लेकर भी रावले ने अलग दृष्टिकोण अपनाया है। वे कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हैं और 'ड्रग्स मुक्ति अभियान' के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। यह उनके उस पुलिसिंग मॉडल का सामने लाता है जिसमें कानून लागू करने के साथ-साथ अपराध और सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों पर काम करने को भी महत्व दिया जाता है।

उनके कार्यों को अगस्त 2026 में मिले केंद्रीय गृहमंत्री उत्कृष्ट गुन्हे अन्वेषण पुरस्कार ने भी एक महत्वपूर्ण मान्यता दी है। यह सम्मान उनकी जांच-पड़ताल की दक्षता और उत्कृष्ट अपराध अनुसंधान के प्रति उनके योगदान को रेखांकित करता है। हालांकि, तकनीक के प्रति गहरी आस्था रखने वाले रावले यह भी मानते हैं कि हर समस्या का समाधान मशीन नहीं कर सकती। उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शायद यही है कि आधुनिक तकनीक के साथ मानवीय संवेदना और नैतिकता को वे बराबर महत्व देते हैं।



पत्रकारिता से जनकेंद्रित पुलिसिंग तक का सफर

नुमल महट्टा

बोगईगांव, असम

असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी नुमल महट्टा ने पुलिस सेवा में अपने लंबे करियर के दौरान कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सामुदायिक पुलिसिंग और जनसंवाद के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। वर्तमान में वे बोगईगांव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। नुमल महट्टा कोई आईपीएस नहीं, बल्कि असम पुलिस सेवा (एपीएस) के 2004 बैच के अधिकारी हैं और अपनी मेहनत व परफॉरमेंस के दम पर जिले के वरिष्ठ पुलिस कप्तान के पद पर पहुंचे हैं। उनकी लंबी सेवा, जिला पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और लगातार चुनौतीपूर्ण पदों पर काम करने के कारण उनका अनुभव वरिष्ठ पुलिस नेतृत्व के स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है।



उनकी सेवाओं को संस्थागत स्तर पर भी सम्मान मिला है। 2024 में उन्हें असम पुलिस के डीजीपी कमिशन मेडल के गोल्ड वर्ग में शामिल किया गया था। इसके अलावा 2025 में भारत सरकार की ओर से जारी पुलिस पदक सूची में उनका नाम मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए शामिल किया गया। उन्होंने मीडिया की दुनिया से पुलिस सेवा में प्रवेश कर संवाद और प्रशासन, दोनों को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाया। नागरिक सेवाओं और अपराध नियंत्रण से लेकर जिला पुलिसिंग तक उनकी भूमिका में कठोर कार्यवाई और जनता से संवाद का संतुलन दिखाई देता है।

में तथ्यों को समझना, लोगों से संवाद करना, विभिन्न पक्षों को सुनना और जटिल विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना जरूरी होता है। पुलिसिंग में भी यही संवाद कौशल जनता की शिकायतों को समझने, स्थानीय सूचनाएं जुटाने और पुलिस तथा नागरिकों के बीच विश्वास कायम करने में उपयोगी साबित होता है। नुमल महट्टा के करियर में यह संवादपरक दृष्टिकोण विशेष रूप से दिखाई देता है।

उनकी महत्वपूर्ण जिला पोस्टिंग में सोनितपुर, कछार और कोकराझार जैसे क्षेत्र शामिल रहे हैं। सोनितपुर में वे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। असम पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड में उन्हें वहां अतिरिक्त एसपी मुख्यालय के रूप में दर्ज किया गया था। बाद में कछार जिले की पुलिस कमान संभालते हुए उन्होंने अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाई, साइबर अपराध और जनसेवा से जुड़े मामलों पर सक्रियता दिखाई।

कछार में उनके कार्यकाल का एक उल्लेखनीय पक्ष पुलिस-जन संवाद और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास रहा। उस समय जिले में बड़ी संख्या में पासपोर्ट सत्यापन लंबित थे। पुलिस ने दो पासपोर्ट मेलों का आयोजन किया, जिससे आवेदकों को सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखने का अवसर मिला। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा खुद को एसपी नुमल महट्टा बताकर लोगों से पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर पैसे वसूलने का मामला सामने आया। आरोपी ने उनके नाम से डिजिटल भुगतान खाता भी बनाया था। महट्टा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर टीम की मदद से आरोपी को पकड़वाया।

कछार में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्यवाई भी उनकी पुलिसिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। अगस्त 2023 में पुलिस ने विशेष सूचना के आधार पर मणिपुर से असम के रास्ते ले जाए जा रहे मादक पदार्थों की खेप पकड़ी और चार लोगों को गिरफ्तार किया। उस कार्यवाई में एसपी के रूप में नुमल महट्टा ने बताया था कि तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए असामान्य रास्ते का इस्तेमाल किया था। बाद के वर्षों में भी कछार पुलिस की ओर से नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्यवाई जारी रही।

कानून-व्यवस्था और संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच पर भी उनकी पुलिसिंग का जोर रहा। अगस्त 2025 में कछार में एक व्यक्ति की मौत के मामले में परिवार की शिकायत पर बीएसएफ कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। महट्टा ने कहा था कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यह पुलिस की उस भूमिका को दर्शाता है जिसमें कानून के सामने सभी पक्षों को समान रूप से जांच के दायरे में रखना आवश्यक होता है।

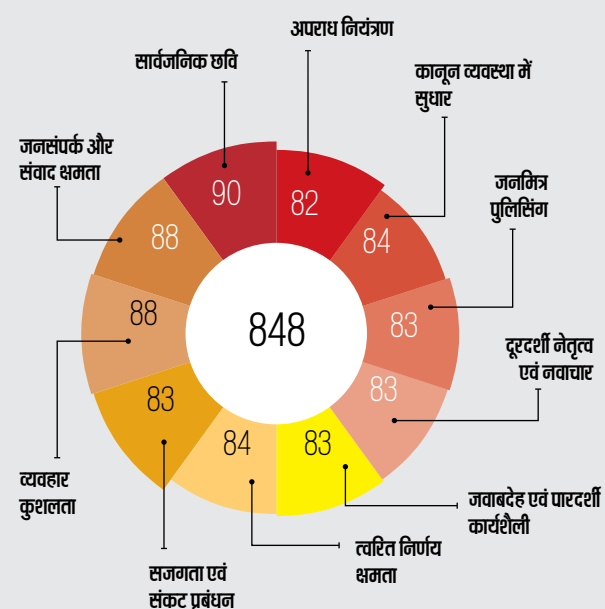
कोकराझार के एसएसपी के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। नवंबर 2025 में असम सरकार ने उनका तबादला गुवाहाटी पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी पश्चिम के रूप में किया। आधिकारिक आदेश में कोकराझार से उनका स्थानांतरण दर्ज है। इसके बाद मार्च 2026 में उन्हें फिर जिला पुलिस की कमान देते हुए बोगईगांव का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। असम सरकार के स्थानांतरण आदेश के अनुसार उन्होंने मोहन लाल मोणा के स्थान पर यह जिम्मेदारी संभाली।

बोगईगांव में उनकी वर्तमान भूमिका उनके लंबे प्रशासनिक और मैदानी अनुभव की अगली परीक्षा है। जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत रखना, अपराधियों पर त्वरित कार्यवाई, नागरिक शिकायतों का समाधान, पुलिस बल की जवाबदेही और संवेदनशील मामलों में प्रभावी हस्तक्षेप उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं। असम पुलिस की वर्तमान आधिकारिक सूची में भी उन्हें एसएसपी बोगईगांव के रूप में दर्ज किया गया है।

उनकी प्रोफाइल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि वे पुलिसिंग को केवल अपराधियों के खिलाफ कार्यवाई के रूप में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, प्रभावी संवाद और जवाबदेह प्रशासन के साथ जोड़कर देखते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें असम पुलिस के अनुभवी और जनकेंद्रित मैदानी अधिकारियों में एक विशिष्ट स्थान देता है।



नुमल महट्टा की पेशेवर यात्रा की सबसे खास बात यह है कि पुलिस सेवा में आने से पहले उन्होंने पत्रकारिता और मीडिया क्षेत्र में कार्य किया था। उन्होंने दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान यानी आईआईएमसी से पत्रकारिता की पढ़ाई की और उससे पहले टीवी इंटरनेशनल तथा ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। इसके बाद उन्होंने ऑयल इंडिया में चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के ओएसडी के रूप में भी सेवाएं दीं। मीडिया से पुलिस सेवा तक का यह अनुभव उनकी कार्यशैली को विशिष्ट बनाता है। पत्रकारिता



अनुभव और अनुशासित
पुलिस नेतृत्व की पहचान

मुथुराजू एम.

चामराजनगर, कर्नाटक

कर्नाटक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मुथुराजू एम. वर्तमान में चामराजनगर जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उन्हें वर्तमान एसपी के रूप में दर्ज किया गया है। इससे पहले वे बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स में पुलिस अधीक्षक और उससे पहले मैसूर सिटी पुलिस में कानून-व्यवस्था के डीसीपी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनके लंबे पुलिस अनुभव में शहरी कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन और विशेष पुलिस इकाइयों के साथ काम करने का अनुभव शामिल है।



मुथुराजू एम. का जन्म 15 जून 1975 को हुआ। वे कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं और उनकी पुलिस सेवा की शुरुआत राज्य पुलिस सेवा से हुई। वर्ष 2021 में उन्हें राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति मिली। भारत सरकार की आधिकारिक आईपीएस चयन सूची में उनका नाम 2017 की चयन सूची में शामिल है और 10 दिसंबर 2021 को उनकी आईपीएस नियुक्ति हुई। इस तरह उनकी यात्रा सीधे आईपीएस भर्ती के बजाय राज्य पुलिस सेवा से आगे बढ़कर आईपीएस तक पहुंचने

मुथुराजू एम. की पुलिस यात्रा मूलतः अनुभव और जिम्मेदारियों के क्रमिक विस्तार की कहानी है। राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस तक का सफर, मैसूर में कानून-व्यवस्था की कमान, बेंगलुरु में विशेष पुलिस इकाई का अनुभव और अब चामराजनगर में जिला पुलिस का नेतृत्व—इन सभी भूमिकाओं ने उनके पेशेवर व्यक्तित्व को व्यापक बनाया है। चामराजनगर में उनके सामने चुनौती है कि अपने शहरी पुलिसिंग और विशेष इकाई के अनुभव को जिले की स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप इस्तेमाल करते हुए कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाए।



वाले अधिकारियों की प्रेरक यात्रा है।

आईपीएस में पदोन्नति के बाद उनका प्रमुख कार्यकाल मैसूर सिटी पुलिस में रहा। वे वहां डीसीपी, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में लंबे समय तक कार्यरत रहे। आधिकारिक आईपीएस सिविल लिस्ट में 2022 में उनकी तैनाती डीसीपी, लॉ एंड ऑर्डर, मैसूर सिटी के रूप में दर्ज है और बाद के रिकॉर्ड में भी यह जिम्मेदारी जारी रही। वर्ष 2023 में उन्हें इसी पद पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में पदोन्नत किया गया।

मैसूर जैसे महत्वपूर्ण और पर्यटक शहर में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालना उनके करियर का अहम चरण रहा। यहां पुलिस के सामने सामान्य अपराध नियंत्रण के साथ पर्यटन, भीड़ प्रबंधन, महत्वपूर्ण आयोजनों की सुरक्षा, यातायात और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती रहती है। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में लंबे समय तक काम करने से उन्हें बड़े शहरी पुलिस संगठन के संचालन और थाना स्तर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक समन्वय का व्यापक अनुभव मिला।

जुलाई 2025 में मुथुराजू एम. का स्थानांतरण मैसूर सिटी से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स में पुलिस अधीक्षक के रूप में हुआ। उस समय मैसूर पुलिस में उनके स्थान पर नए डीसीपी की नियुक्ति की गई थी। बाद में सितंबर 2025 में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स के पुनर्गठन के दौरान उन्हें ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अंतर्गत बीएमटीएफ में भी पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ किया गया। सरकार के आदेश के अनुसार इस पद को पुलिस अधीक्षक, ईटेलिजेंस के समकक्ष दर्जा और जिम्मेदारियों वाला पद माना गया था।

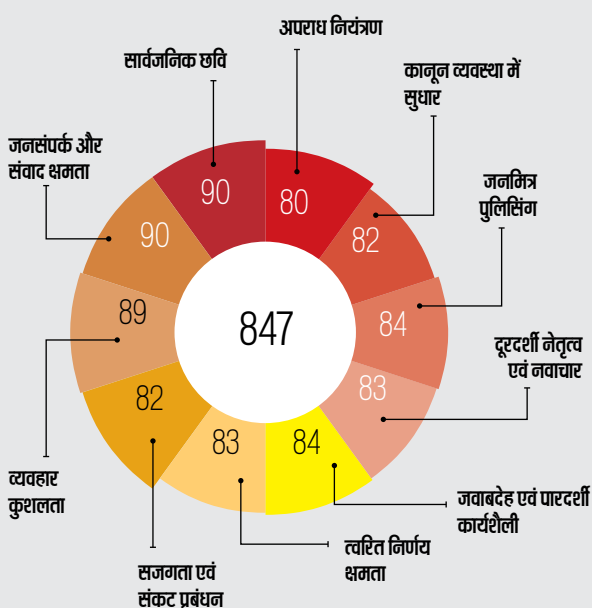
बीएमटीएफ में उनका कार्यकाल शहरी प्रशासन और पुलिसिंग के उस क्षेत्र से जुड़ा रहा, जहां सरकारी भूमि, अतिक्रमण, अवैध निर्माण और सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित मामलों में पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। इस तरह उनकी सेवा का अनुभव पारंपरिक जिला एवं कानून-व्यवस्था पुलिसिंग से आगे बढ़कर विशेषीकृत शहरी पुलिस कार्य तक भी पहुंचा।

दिसंबर 2025 के अंत में कर्नाटक सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बड़े फेरबदल में मुथुराजू एम. को बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स से स्थानांतरित कर चामराजनगर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया। वर्ष 2026 से वे चामराजनगर पुलिस की कमान संभाल रहे हैं और अगस्त 2026 में जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उनका नाम एसपी के रूप में दर्ज है।

चामराजनगर की पुलिसिंग उनके लिए मैसूर और बेंगलुरु के अनुभव से अलग तरह की चुनौती लेकर आती है। जिले में ग्रामीण और वन क्षेत्र हैं तथा कर्नाटक के अन्य हिस्सों के साथ-साथ तमिलनाडु और केरल की सीमाओं से जुड़ी भौगोलिक परिस्थितियां भी पुलिस के लिए विशेष महत्व रखती हैं। ऐसे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के साथ सीमावर्ती इलाकों की निगरानी, तस्करी पर नियंत्रण, वन क्षेत्र से जुड़े अपराध और स्थानीय कानून-व्यवस्था पर लगातार ध्यान देना आवश्यक होता है।

जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में मुथुराजू एम. की जिम्मेदारी केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है। थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली की निगरानी, गंभीर मामलों की जांच की समीक्षा, कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर, पुलिस बल के अनुशासन और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी उनके दायित्व का हिस्सा है। मैसूर में कानून-व्यवस्था की लंबी जिम्मेदारी और बेंगलुरु में विशेष पुलिस इकाई के अनुभव से उन्हें जिला पुलिस नेतृत्व के लिए व्यापक प्रशासनिक दृष्टि मिली है।

उनकी सेवा यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू निरंतर पदोन्नति और जिम्मेदारियों का विस्तार भी है। राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस तक पहुंचना, मैसूर जैसे महत्वपूर्ण शहर में डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में लंबे समय तक जिम्मेदारी संभालना, फिर बेंगलुरु की विशेष पुलिस इकाई में काम करना और अंततः चामराजनगर जैसे जिले की पुलिस कमान हासिल करना उनके अनुभव की विविधता को दर्शाता है।



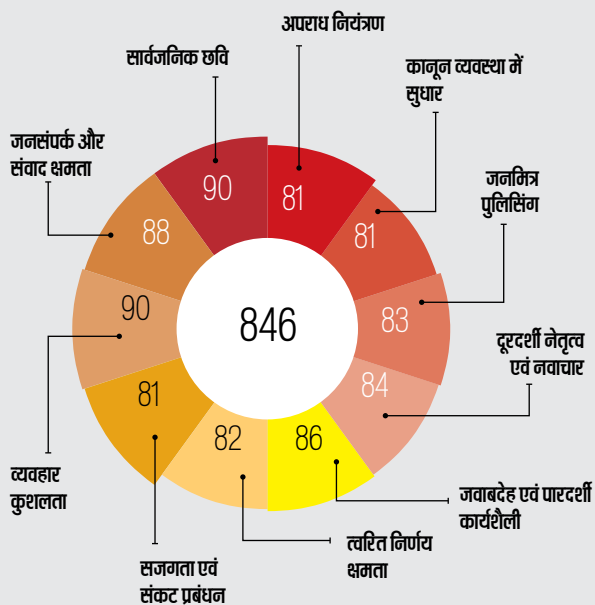


अनुभव, अनुशासन और जनकेंद्रित पुलिसिंग की मिसाल

विवेक स्येम्

ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय

मेघालय की दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, पर्यटन, यातायात, मादक पदार्थ, सामुदायिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण जैसी अनेक चुनौतियाँ एक साथ मौजूद हैं। ऐसे परिवेश में जहाँ अनुभव, अनुशासन, त्वरित निर्णय क्षमता और जनता से जुड़ाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं विवेक स्येम् इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ पुलिसिंग को आगे बढ़ाने वाले अधिकारियों में शामिल हैं। वर्तमान में वे पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं और जनवरी 2025 से इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं।



आज पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक के रूप में उनके सामने शिलांग की सुरक्षा, यातायात, पर्यटन, साइबर अपराध, मादक पदार्थ, सार्वजनिक आयोजन और कानून-व्यवस्था जैसी विविध चुनौतियाँ हैं। विवेक स्येम् के पुलिस जीवन की खासियत यही है कि उन्होंने कठोर कानून-व्यवस्था और मानवीय पुलिसिंग के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। विशेष अभियानों से लेकर संवेदनशील अनुसंधान, तकनीक आधारित सेवाओं से लेकर पुलिस कल्याण और जन-भागीदारी तक, उनका कार्य अनुशासन, तैयारी, जवाबदेही और जनसेवा केंद्रित पुलिस नेतृत्व की तस्वीर प्रस्तुत करता है।



गया। वर्ष 2017 तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया। इसके बाद पश्चिमी जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक के रूप में उन्होंने ग्रामीण, सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों की पुलिसिंग का अनुभव हासिल किया। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, घुसपैठ विरोधी निदेशालय तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने प्रशिक्षण, विशेष अभियान, सीमा सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का व्यापक अनुभव प्राप्त किया।

विवेक स्येम् के कार्यकाल का महत्वपूर्ण पक्ष उग्रवाद विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका रही है। उन्होंने अनेक विशेष अभियानों का नेतृत्व किया और पुलिस की सामरिक क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया। पूर्वी खासी हिल्स में विशेष अभियान दल को सक्रिय और व्यवस्थित रूप देने की दिशा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पहल की।

उनकी पहचान प्रभावी अनुसंधान अधिकारी के रूप में भी बनी है। सोनम रघुवंशी प्रकरण जैसे अत्यधिक चर्चित मामले में पुलिस की कार्रवाई ने देशभर का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे मामलों में साक्ष्य आधारित अनुसंधान, विभिन्न टीमों के बीच समन्वय और जन-अपेक्षाओं के बीच निष्पक्षता बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। विवेक स्येम् पुलिसिंग को केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं मानते। उनके लिए बेहतर पुलिस व्यवस्था का अर्थ ऐसी प्रणाली तैयार करना भी है, जिससे नागरिकों को पुलिस सेवाएं आसानी और पारदर्शिता के साथ मिल सकें। सेवा वितरण में ऑनलाइन सत्यापन जैसी पहल इसी सोच को दर्शाती है।

पुलिसकर्मियों का कल्याण भी उनके कार्य-दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उन्होंने पुलिस बल के कार्यस्थल और जीवन-स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। शराब की लत से जूझ रहे पुलिसकर्मियों के लिए अल्कोहलिक्स एनॉनिमस के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने की पहल उनके संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाती है। पुलिस आवास और आधारभूत संरचना के विकास, थानों के आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा सुविधाओं में सुधार पर भी उन्होंने ध्यान दिया है।

शारीरिक दक्षता और परिचालनिक तैयारी को लेकर भी विवेक स्येम् ने विशेष पहल की। पूर्वी खासी हिल्स में शुरू किया गया इकेएच फिट चैलेंज पुलिसकर्मियों की शारीरिक क्षमता को परखने और बेहतर बनाए रखने की दिशा में प्रयास है। इससे बल में स्वास्थ्य, फिटनेस और पेशेवर तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा मिला है।

जन-भागीदारी उनकी पुलिसिंग का एक और महत्वपूर्ण आधार है। गांव रक्षा दलों के नेटवर्क को मजबूत करते हुए उनके कार्यकाल में इनकी संख्या 250 से अधिक हुई। स्थानीय समुदायों को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने की यह पहल अपराध रोकथाम, सामुदायिक सुरक्षा और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने में सहायक है।

मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में भी उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। मेघालय अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस अधीक्षक रहते हुए उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली राज्य की डीआरईएएम पहल से संबंधित विचार-विमर्श में भाग लिया। उनका मानना है कि नशे की समस्या केवल पुलिस कार्रवाई से समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए समुदाय, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक संस्थाओं के साथ निरंतर सहयोग जरूरी है।

कानून-व्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ दायित्व के दौरान उन्होंने 102 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के क्रियान्वयन में भी भूमिका निभाई। इससे आपात स्थितियों में पुलिस प्रतिक्रिया और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने का अनुभव मिला।

उनकी सेवाओं को कई पुरस्कारों और प्रशस्तियों से सम्मानित किया गया है। इनमें डीजीपी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रशस्ति पुरस्कार, त्वरित अनुसंधान के लिए राज्यपाल पदक, मुख्यमंत्री पुलिस पदक (2022) और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (2024) प्रमुख हैं।

स 11 दिसंबर 1975 को जन्मे विवेक स्येम् ने अपने पुलिस जीवन की शुरुआत राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में की और वर्ष 2015 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। लगभग तीन दशकों के अनुभव में उन्होंने मैदानी पुलिसिंग, विशेष अभियान, अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रशासन और कानून-व्यवस्था प्रबंधन जैसी विभिन्न जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। यही विविध अनुभव उनके नेतृत्व की प्रमुख ताकत है।

वर्ष 2013 में उन्हें शिलांग नगर का पुलिस अधीक्षक बनाया



फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के सर्वे में कुछ ऐसे भी पुलिस कप्तान रहे, जिन्होंने अत्यन्त सराहनीय कार्य किया, बावजूद इसके टॉप 25 की शीर्ष सूची में स्थान बनाने से बेहद नजदीकी अंक से चूक गए। फेम इंडिया-एशिया पोस्ट ने पांच ऐसे पुलिस अधिकारियों को भी विशेष 'सुपर-5' श्रेणी में शामिल किया है, जिनका कार्य और नेतृत्व पुलिसिंग के अलग-अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। यह पहल देश में उन पुलिस अधिकारियों को सामने लाने और प्रोत्साहन देने का प्रयास है, जो बदलते अपराध परिदृश्य और नई सामाजिक चुनौतियों के अनुरूप पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, तकनीक-सक्षम, उत्तरदायी और जनकेंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।


डॉक्टर छोड़ अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन

डॉ. इराज राजा

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश कैडर के 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. इराज राजा वर्तमान में गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक हैं। उनका जन्म 5 दिसंबर 1986 को आगरा में हुआ और उनकी शैक्षणिक योग्यता एमबीबीएस तथा पुलिस प्रबंधन में मास्टर डिग्री है। उन्होंने बतौर चिकित्सक पांच साल तक सरकारी नौकरी की और इस दौरान यूपीएससी की कठिन परीक्षा क्रैक कर यूपी कैडर में आईपीएस सेवा ज्वाइन की। वे जुलाई 2024 से गाजीपुर के एसपी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें अपराधियों के काल के तौर पर जाना जाता है व पुलिस महानिदेशक की सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कमेंडेशन डिस्क भी मिल चुकी हैं।

गाजीपुर जैसे बड़े और विविध भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले में डॉ. इराज राजा की पुलिसिंग का प्रमुख फोकस अपराध नियंत्रण, संगठित अपराध पर कार्रवाई और अपराधियों की निगरानी रहा है। उन्होंने ऐसे अपराधियों की पहचान और निगरानी पर जोर दिया, जिनके खिलाफ एक से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आवश्यकता के अनुसार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई को भी उनकी रणनीति का हिस्सा बनाया गया।

उनके नेतृत्व में गाजीपुर पुलिस ने संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ अभियान चलाए। जून 2026 में 'ऑपरेशन वज्रपात' के दौरान पुलिस ने 50 आपराधिक गिरोहों और उनके 401 सदस्यों की पहचान की। यह कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपराधियों के नेटवर्क और उनकी गतिविधियों की निगरानी पर आधारित थी।

अपनी सेवा के शुरुआती कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 150 से अधिक एनकाउंटर की श्रृंखला बनाई, जिससे अपराधियों में उनका खौफ देखा गया। गाजीपुर और अन्य तैनाती के दौरान उन्होंने आरपीएफ जवानों की हत्या जैसे गंभीर मामलों में शामिल कुख्यात बदमाशों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। गाजियाबाद, जालौन और गाजीपुर जैसे जिलों में बतौर पुलिस अधीक्षक सेवाएं देते हुए उन्होंने गंभीर अपराधों में आपसी समझौते या पंचायत की संस्कृति को नकार कर सख्त कानूनी कार्रवाई व एफआईआर दर्ज करने पर जोर दिया है।

डॉ. इराज राजा की चिकित्सा शिक्षा उनकी पुलिसिंग में संवेदनशीलता के एक अलग आयाम को जोड़ती है। कानून का प्रभावी अनुपालन और नागरिकों के साथ जिम्मेदार व्यवहार उनके पेशेवर दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। गाजीपुर के एसपी के रूप में उनका कार्य अपराधियों पर दबाव बनाने के साथ पुलिस-जन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी केंद्रित दिखाई देता है।


तकनीक और सुरक्षा प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी

आर. आनंद

पथनमथिट्टा, केरल



के

रल कैडर के 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी आर. आनंद वर्तमान में पथनमथिट्टा के जिला पुलिस प्रमुख हैं। जुलाई 2025 में उन्हें डीसीपी वीआईपी सिक्कोरिटी के पद से स्थानांतरित कर पथनमथिट्टा का एसपी बनाया गया था।

पथनमथिट्टा की पुलिसिंग उनके लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि जिले में विश्वप्रसिद्ध सबरीमला तीर्थस्थल आता है, और यहां विशाल तीर्थयात्री भीड़ का प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी चुनौतियां भी रहती हैं। आर. आनंद ने इन चुनौतियों के समाधान में तकनीक के उपयोग को महत्व दिया है।

सबरीमला में एआई आधारित तीर्थयात्री प्रबंधन लागू कर उच्च क्षमता वाले कैमरे, ड्रोन, फेस डिटेक्शन और विश्लेषण के जरिए भीड़ की स्थिति का आकलन करने की योजना है। पंडालम में सोने की बड़ी चोरी के मामले में केरल पुलिस ने कर्नाटक पुलिस के साथ मिलकर तमिलनाडु तक जांच का विस्तार किया और गिरोह के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया।

वायनाड में 2020 में एक मूक-बधिर और मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य बलात्कार के कठिन मामले की उन्होंने तत्कालीन एएसपी मानंतवडी के रूप में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की और एक साल के भीतर आरोपी को दोहरी आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। उत्कृष्ट जांच कार्य के लिए उन्हें केरल के पुलिस महानिदेशक और राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा 'बैज ऑफ ऑनर' से भी नवाजा जा चुका है। वर्ष 2022 में उन्हें जांच में उत्कृष्टता के लिए 'केंद्रीय गृह मंत्री के एक्सीलेंस इन इनवेस्टिगेशन' मेडल से सम्मानित किया गया।

गौरव सिंह

शिमला, हिमाचल प्रदेश

नशा तस्करी के खिलाफ रणनीतिक
पुलिसिंग की मिसाल

हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह ने जिला कुल्लू और सोलन के पुलिस अधीक्षक के रूप में संगठित नशा तस्करी के खिलाफ प्रभावी, नवाचारी और परिणामोन्मुख पुलिसिंग की मिसाल पेश की है। उनकी कार्यशैली में अपराधियों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ-साथ पूरे आपराधिक नेटवर्क, उसके वित्तीय स्रोत और सप्लाई चेन को निशाना बनाने की रणनीति दिखाई देती है।

कुल्लू के एसपी के रूप में उनके कार्यकाल में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में करीब 123 किलोग्राम चरस बरामद की। इसी दौरान करीब 6.3 किलोग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपये थी।

गौरव सिंह ने हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस मामलों में वित्तीय जांच को भी महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में आगे बढ़ाया। कुल्लू में मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर चार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त या फ्रीज करने की कार्रवाई की गई। इससे नशे के कारोबार की आर्थिक नींव पर प्रहार करने का नया मॉडल सामने आया।

सोलन के एसपी के रूप में उन्होंने इसी रणनीति को और व्यापक बनाया। करीब 37 किलोग्राम चरस की बड़ी बरामदगी के साथ अंतरराज्यीय नशा नेटवर्क पर कार्रवाई की गई।

तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके नेतृत्व में कुल्लू में हिमाचल प्रदेश का पहला ईटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया गया, जिसने तकनीक आधारित यातायात प्रवर्तन को नई दिशा दी।





Umashree Foundation

(To creat Endless Happiness)



Address -
F Block - sector -50
Noida -201304 (Delhi NCR)

Contact - +91-9911976808
Email ID - ss.fameindia@gmail.com



Instagram - @ra.jshree4866



साइबर अपराध के खिलाफ
आधुनिक पुलिसिंग

अधिराज सिंह राणा

सीआईडी एवं साइबर क्राइम, आंध्र प्रदेश



आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अधिराज सिंह राणा वर्तमान में आंध्र प्रदेश सीआईडी में एसपी, साइबर क्राइम्स के रूप में कार्यरत हैं। साइबर अपराध के बदलते स्वरूप ने पुलिसिंग के सामने नई चुनौती पैदा की है और राणा की विशेषज्ञता इसी क्षेत्र में केंद्रित है। उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सीआईडी की साइबर क्राइम टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की है।

दिसंबर 2025 में आंध्र प्रदेश पुलिस और दूरसंचार विभाग के समन्वय से एक अंतरराष्ट्रीय 'सिम बॉक्स' नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। यह नेटवर्क इंटरनेट आधारित अंतरराष्ट्रीय कॉल को स्थानीय मोबाइल कॉल में बदलने के लिए सिम बॉक्स का इस्तेमाल करता था और इससे लगभग 20 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ था।

इस मामले में दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों से संचालित साइबर अपराध नेटवर्क के भारत में मौजूद नेटवर्क की पहचान की गई। इस कार्रवाई में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें दो विदेशी नागरिक भी शामिल थे। मार्च 2026 में इस मामले की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सीआईडी की साइबर क्राइम टीम को एबीसीडी पुरस्कारों में तीसरा स्थान भी मिला।

राणा ने म्यांमार में साइबर गुलामी के लिए फंसाए गए भारतीय नागरिकों के मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पुलिस संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट के खिलाफ राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। उनकी पुलिसिंग आधुनिक तकनीक, अंतरराष्ट्रीय समन्वय, डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय अपराध की जांच के संयोजन का उदाहरण है।

लोगेश कुमार पी.

चरखी दादरी, हरियाणा

चरखी दादरी में जिम्मेदार जिला
पुलिस नेतृत्व

हरियाणा कैडर के 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी लोगेश कुमार पी. वर्तमान में चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक हैं। उनका जन्म 21 मार्च 1988 को तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने गणित में स्नातक, एमबीए तथा फेलोशिप स्तर की शिक्षा प्राप्त की है।

आईपीएस में आने के बाद उन्होंने हरियाणा के विभिन्न पुलिस पदों पर काम किया। चरखी दादरी से पहले वे झज्जर जिले में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात थे। वहां उन्होंने कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पुलिसिंग को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने पर विशेष काम किया। युवाओं को जागरूक करने और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रमों में भाग लिया। नकली डीपी लगाकर पैसे ऐंठने वाले घोटालों के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए।

चरखी दादरी के जिला पुलिस प्रमुख के रूप में उनकी जिम्मेदारियों में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, गंभीर मामलों की जांच की निगरानी और थाना स्तर की पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाना शामिल है। चरखी दादरी में ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के बीच पुलिसिंग का संतुलन महत्वपूर्ण है। उन्होंने जमीनी स्तर पर गश्त बढ़ाने, अपराधियों पर नकेल कसने और आम जनता व पुलिस के बीच समन्वय को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया।

चरखी दादरी के एसपी के रूप में उनकी भूमिका ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब जिला पुलिस को पारंपरिक अपराधों के साथ साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा और सामाजिक विवादों जैसी नई चुनौतियों पर भी काम करना पड़ रहा है। जिला पुलिस की कमान संभालने का उनका अनुभव उनके करियर में एक महत्वपूर्ण चरण है।



इंपैक्ट फीचर



देश के हिन्दू तीर्थ स्थलों में बिहार के मधुबनी जिला मुख्यालय के निकट मंगरौनी गांव स्थित एकादश रुद्र महादेव का अलग ही महत्व है। ये महत्व इसलिये भी बढ़ जाता है कि यह अपने आप में दुनिया में अनोखी जगह है, जहां एक साथ शिव के विभिन्न रूपों 11 शिवलिंगों का दर्शन व पूजन का अवसर मिलता है। यहां शिव 11 रूपों महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम देवदेवा, भदोद्भव एवं कपालिश्च के दर्शन का सौभाग्य शिव भक्तों को विशेष तौर पर मिलता है।

मधुबनी में स्थापित है एकादश रुद्र महादेव का दुर्लभ मंदिर

इसके अलावा इस एकादश रुद्र मंदिर परिसर में विष्णु के विभिन्न अवतारों, श्रीविद्यायंत्र, विष्णुपद गया क्षेत्र, महाकाल, महाकाली, गणेश सरस्वती आदि साथ ही आम एवं महुआ का आलिंगन-बद्ध वृक्ष, भगवान शिव, पार्वती, महा-लक्ष्मी, महा-सरस्वतीयंत्र, विष्णु-पादुका आदि के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है।

इस परिसर स्थित पीपल वृक्ष का भी तांत्रिक महत्त्व अलग ही है। कहते हैं कि इसके स्पर्श मात्र से भूत प्रेत के प्रभाव से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। वहीं श्रीविद्यायंत्र के दर्शन व पूजन से लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की कृपा बनी रहती है।

सोमवार के दिन यहां भंडारे का आयोजन किया जाता है, इस दिन यहां रुद्राभिषेक एवं षोडशोपचार पूजन करते हैं तो उनकी इच्छित मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। पंडित जी बताते हैं कि यहां एक ही शक्ति-वेदी पर स्थापित शिव के सभी एकादश रुद्र लिंग रूपों में 10 मई से 21 मई 2000 ई. के बीच विभिन्न तरह की आकृतियां उभर आयीं।

1 महादेव - विगत 30 जुलाई 2001 को अर्द्ध-नारीश्वर का रूप प्रकट हुआ है। कामाख्या माई का ये भव्य रूप है। पांचवें सोमवारी के दिन गणेश जी गर्भ में प्रकट हुए। शिवलिंग पर ये रूप स्पष्ट नजर आती है।

2 शिव - प्रभु श्री राम ने कहा था कि मैं ही शिव हूँ। इस लिंग में सिंहासन का चित्र उभरा है, जो प्रभु श्री राम का सिंहासन दर्शाता है।

3 रुद्र - भय को हराने वाले इस लिंग में बजरंगबली पहाड़ लेकर उड़ रहे हैं बड़ा ही अद्भुत चित्र प्रकट हुआ है।

4 शंकर - गीता के दसवें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही शंकर हूँ। इस लिंग में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, बांसुरी और बाजूबंद स्पष्ट दृष्टिकोण होता है।

5 नील लोहित - जब महादेव ने विषपान किया था, तब उनका नाम नील लोहित पड़ गया था। इस लिंग में सांप एवं ऊँ का अक्षर प्रकट हुआ है।

6 ईशान - हिमालय पर निवास करने वाले महादेव जिसे केदारनाथ कहते हैं विगत नौ जुलाई 2001 सावन के पहले सोमवार को राजराजेश्वरी का रूप प्रकट हुआ।

7 विजय - इस शिवलिंग में छवि बन रही है जिस कारण आकृति अस्पष्ट है।

8 भीम - महादेव का एक रूप भी है। इस शिवलिंग में गदा की छवि उभर कर सामने आयी है। गदा का डंडा अभी धीरे-धीरे प्रकट हो रहा है।

9 देवादेव - ये लिंग सूर्य का रूप है। इस शिवलिंग में गदा के नीचे दो भागों से सूर्य की किरणें फूटकर शीर्ष में मिल रही है।

10 भवोद्भव - इस लिंग में उमा शंकर की आकृति प्रकट हुई है। दोनों आकृतियां धीरे-धीरे बढ़ रही है।

11 कपालिश्च - महादेव का एक रूप बजरंगबली है। बजरंगबली ब्रह्मचारी थे, इसलिये संभवतः इस लिंग में कोई चित्र नहीं उभर रहा है।

कांची पीठ के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल व अधीक्षण पुरातत्व-विद डॉ. फणीकांत मिश्र आदि आये तो यहां शिव के एकादश रुद्र का अलौकिक रूप देख भाव विह्वल हो गये। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में धार्मिक दृष्टिकोण से अद्वितीय पूजन व तीर्थ स्थल है।

किसी दिन ये शिवलिंग अपने आप पूरा लाल हो जायेगा।

बाबा जी का कहना है कि सभी शिव भक्तों को मात्र एक बार आकर इन शिवलिंगों उभरी हुई आकृतियों को देखे तो पता लगेगा कि ऐसे शिवलिंग विश्व में कहीं भी नहीं हैं।

गौरतलब है कि प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित मुनीश्वर झा ने 1953 ई. में यहां शिव मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में स्थापित सभी शिवलिंग काले ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं जिनका प्रत्येक सोमवार शाम को दूध, दही, घी, मधु, पंचामृत, चंदन आदि से स्नान होता है। श्रृंगार के लिये विशेष तौर पर कोलकाता से कमल के फूल मंगाये जाते हैं। प्रधान पुजारी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान करने नहीं गया नहीं जा पाते उनके लिये यहां गया क्षेत्र बना है जहां पिंडदान कर मुक्ति पायी जाती है।

जागरूकता ही है बचाव का रास्ता सुरक्षित स्कूली वाहन पहली प्राथमिकता

शैक्षणिक सत्र
में सुरक्षित स्कूली
वाहनों से हो
विद्यार्थियों का
आवागमन



प्रदेश के सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से अपील

- स्कूल वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण
- 12 वर्ष तक के विद्यार्थियों के परिवहन में प्रयुक्त स्कूल वाहनों में एक परिचारक/परिचारिका की अनिवार्यता
- वाहन के सुरक्षा मानकों, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी अलार्म आदि उपकरणों की प्रतिमाह हो जांच
- स्कूल वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा एवं अन्य आनुषंगिक प्रपत्रों की वैधता की नियमित जांच तथा अनफिट वाहनों का बहिष्कार

याद रखिए, छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन तथा अभिभावकों एवं स्कूली प्रबंधन की सजगता अत्यंत आवश्यक है।

परिवहन हेल्पलाइन
149 | 1800-1800-151

मुख्यमंत्री
हेल्पलाइन 1076



सुरक्षित बचपन-विकसित उत्तर प्रदेश

विकास की गति अपार-इबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश





मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लाया है

देहरादून शहर में पहले आओं पहले पाओं स्कीम के तहत
अपने **घर** का सपना पूरा करने का एक सुनेहरा मौका।

एम.डी.डी.ए. की ट्रांसपोर्ट नगर फेस-2, आई.एस.बी.टी. एवं आमवाला तरला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून की आवसीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों हेतु पंजीकरण प्रारम्भ:-

HIG | MIG | STUDIO APARTMENT | L.I.G.



क्र. स.	फ्लैटों की श्रेणी	अनुमानित कीमत रु लाख में।	पंजीकरण धनराशि रु लाख में।	फ्लैट का अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फीट)	फ्लैटों की संख्या
1.	अल्प आय वर्ग (LIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड	22.90	2.30	582.82	60
2.	अल्प आय वर्ग (LIG 'C' Block) आलयम, सहस्त्रधारा रोड	23.29	2.32	582.82	16
3.	मध्यम आय वर्ग (MIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड	65.85	6.59	1503.40	112
4.	उच्च आय वर्ग (HIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड	75.64	7.57	1877.83	112

क्र. स.	फ्लैटों की श्रेणी	अनुमानित कीमत रु लाख में।	पंजीकरण धनराशि रु लाख में।	फ्लैट का अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फीट)	फ्लैटों की संख्या
5.	स्टूडियो अपार्टमेंट आलयम, सहस्त्रधारा रोड	32.29	3.23	798.18	48
6.	अल्प आय वर्ग (LIG) ट्रांसपोर्ट नगर, फेज-2	19.90	2.00	453.53	97
7.	मध्यम आय वर्ग (MIG) ट्रांसपोर्ट नगर, फेज-2	49.50	4.95	1090	27
8.	उच्च आय वर्ग (HIG) आई.एस.बी.टी.	71.50	7.15	1954	130

विशेष छूट :-

- उक्त भवनों में एक मुश्त धनराशि जमा किये जाने पर 02 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- यदि कोई महिला/सिनियर सिटिजन/दिव्यांग इस हेतु आवेदन करे तो उनको 01 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट उनके पूर्ववत 02 प्रतिशत की छूट प्रदान करने के उपरान्त अवशेष देय धनराशि प्रदान की जायेगी।

आलयम आवसीय योजना
की जानकारी हेतु
मो. **8006409136**



आई.एस.बी.टी./ट्रांसपोर्ट नगर
आवसीय योजना की जानकारी हेतु
मो. **9193639595**

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

सहारनपुर रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून। फोन : 0135-663150

E mail: info.mdda@mddaonline.in Website : www.mddaonline.in

पंजीकरण फॉर्म प्राधिकरण के साइट ऑफिस, कार्यालय व नीचे दिये गए बैंक की शाखाओं में भी उपलब्ध है।